द्वितीय संस्करण
अप्रैल 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ई-निर्णय पत्रिका
की प्रस्तुति

न्यायाङ्गना

न्याय की किरण

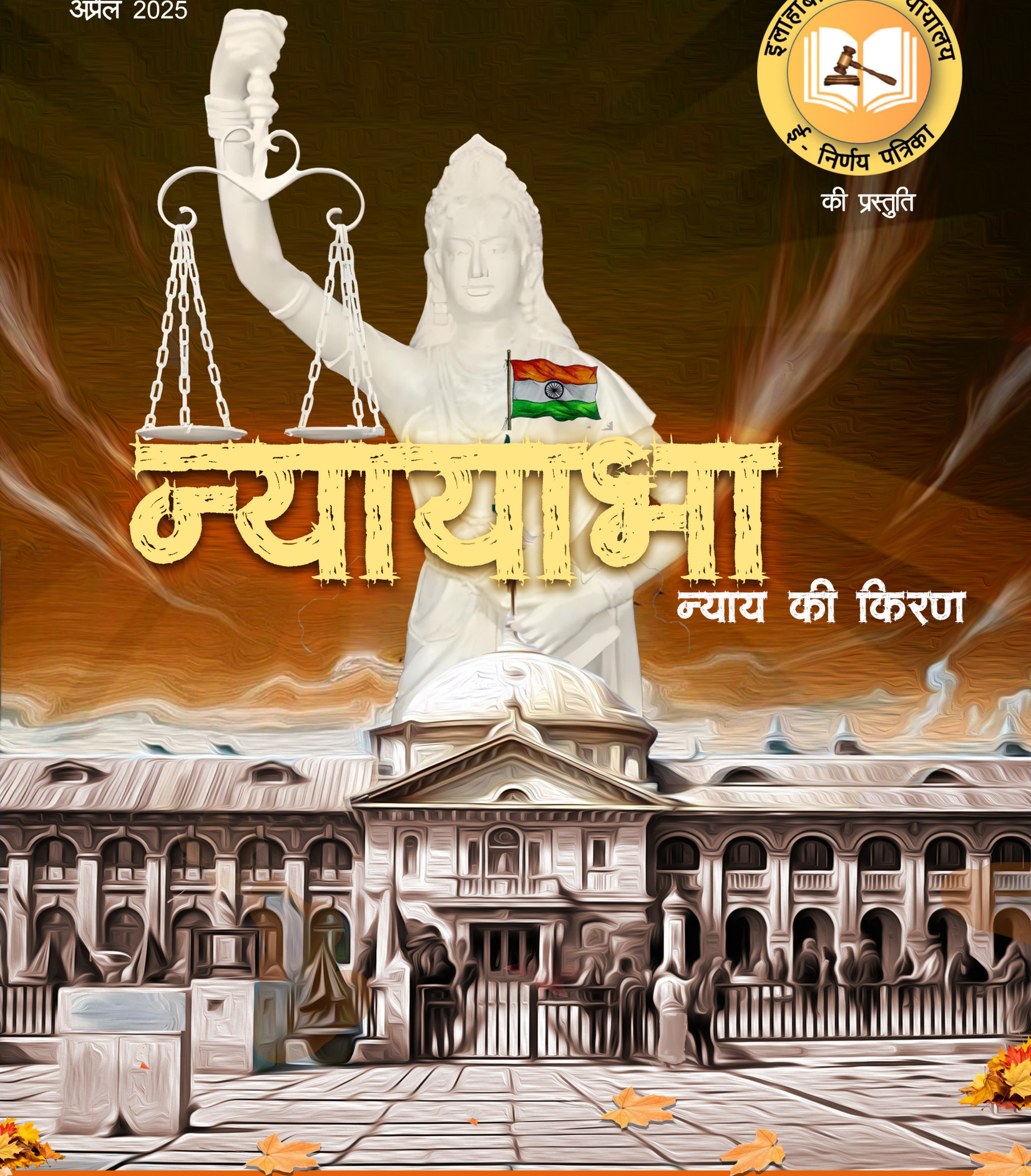

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
द्वारा प्रस्तुत

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई पत्रिका)

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली
(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति
श्री विक्रम डी. चौहान
सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति
श्री अजित कुमार
अध्यक्ष

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई. कमेटी

भारत के तत्कालीन **मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** ने भारत के जनमानस को उनकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय उपलब्ध कराकर उनमें विधिक जागरूकता फैलाने के लिए, 23 जनवरी, 2023 को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र भेज कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय मे एक **ए.आई. कमेटी** के गठन का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन मे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे **उच्च न्यायालय ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी** का गठन 25 जनवरी, 2023 को हुआ।

कमेटी का प्रथम गठन **माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी**, अध्यक्ष व **माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान**, सदस्य के रूप मे हुआ। 29 मार्च, 2023 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला**, अध्यक्ष व **माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव**, सदस्य के रूप मे कमेटी को पुनर्गठित किया गया। 09 मई, 2023 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार**, अध्यक्ष एवं **माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान**, सदस्य के रूप मे कमेटी का पुनर्गठन हुआ। तदोपरान्त दिनांक 26 फरवरी, 2024 को भारत के तत्कालीन **मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़** के निर्देशानुसार ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR) के प्रकाशन हेतु 28 फरवरी, 2024 को **माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान** को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उक्त कमेटी के तीसरे सदस्य के रूप मे नामित किया गया और वर्तमान मे यही कमेटी कार्यरत है।

इस पूरी प्रक्रिया की अवधि मे ही, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ, लखनऊ मे स्वतंत्र **सुवास प्रकोष्ठ** का गठन 16 अगस्त, 2023 को हुआ।

अपने औपचारिक गठन के मात्र तीन माह की अवधि मे, **सुवास प्रकोष्ठ** के समस्त कर्मियों के अथक प्रयासों से उच्चतम न्यायालय के 9161 निर्णयों का हिन्दी मे अनुवाद कराकर उच्चतम न्यायालय को गत वर्ष के संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर उपलब्ध कराया गया, यह वास्तव मे एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

सुवास प्रकोष्ठ, उक्त कमेटी के निर्देशों मे यहीं नहीं रुका और आज की तिथि मे उच्च न्यायालय के 22500 से अधिक निर्णयों का अनुवाद कराकर ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका मे प्रकाशित कर चुका है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न लगभग 299 निर्णयों का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जा चुका है ।

भविष्य मे **सुवास प्रकोष्ठ** का प्रयास, उक्त कमेटी के निर्देशानुसार, "रियल टाइम" अनुवाद को वर्तमान से और भी आगे ले जाने का होगा।

माननीय न्यायमूर्ति **श्री अभय एस. ओका**, अध्यक्ष, **उच्चतम न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी** के निरंतर मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष, **ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद,** के सघन पर्यवेक्षण, निगरानी और दिशानिर्देशों के फलस्वरूप **सुवास प्रकोष्ठ** द्वारा ई-निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया गया है।

संपादकीय

आदरणीय पाठकों,

इस ई-पुस्तक **"न्यायभा-न्याय की किरण"** के प्रथम संस्करण में प्रकाशित मूल लेखो के हिंदी अनुवाद को आपसे मिले समर्थन और सराहना के लिए हृदय से आभार, साथ ही आपके द्वारा बड़ी संख्या में प्राप्त ई-मेल के माध्यम से मिली प्रशंसा और सुझाव को ध्यान में रखते हुए, इस द्वितीय संस्करण में, हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनमें न्यायिक क्षेत्र के उल्लेखनीय अंशो और लेखों के अतिरिक्त 2025 के प्रथम तिमाही के एएफआर और पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची को शामिल किया गया है, जो एक बेहतर संगठित संरचना के संकलन के साथ ही न्यायिक क्षेत्र की विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शिका है।

यह भी एक हर्ष का विषय है की भारतवर्ष मे यह पहल केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ही है जो इस प्रकार की ई पत्रिका का संकलन सम्पादन एवं प्रकाशन कर रहा है।

द्वितीय संस्करण मे, इस पत्रिका का उद्घोष भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के उद्घाटन भाषण के हिन्दी अनुवाद से होगा जो उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिनांक 25 नवंबर, 1966 को दिया था। उसके पश्चात यह पत्रिका आपका सामना प्रथमतः उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ दीवानी / सिविल न्यायपालिका की भूमिका और इतिहास से करायेगा तथा आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास से भी परिचित हो पाएंगे, साथ ही आप आपातकाल के दौरान मानवाधिकार की स्थिति अवगत होंगे।

इसके अत्तिरिक्त कई हिन्दी भाषी विधि छात्रों द्वारा ई मेल के माध्यम से निवेदित, 25 जून 1993 को वियना में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गये विएना कन्वेन्शन का हिन्दी अनुवाद भी आपके ज्ञानवर्धन हेतु प्रकाशित किया गया है।

इन सब के पश्चात जिला न्यायिक अधिकारियो, अधिवक्ताओं, वादकारियों, विधिक छात्रों इत्यादि पाठकगणों के लिए 2025 के प्रथम तिमाही के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक) एवं 2025 के प्रथम तिमाही के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक) का प्रकाशन शामिल किया गया है।

हमें यह पूर्ण विश्वास है कि यह द्वितीय संस्करण भी, प्रथम संस्करण की भांति ही, न केवल अपने अंशो/लेखों से आपको प्रेरणा प्रदान करेगा, अपितु न्यायिक क्षेत्र की व्यापक समझ एवं ज्ञान से भी समृद्ध करेगा। साथ ही हम पाठकों के सुविचारों का स्वागत करते है, जिससे हम अपने अगले संस्करण में उनका स्मरण कर, इसे और उपयोगी बना सकें। आप अपने सुझाव हमें ई-मेल के माध्यम से editorialboard.suvascell@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम भविष्य में इस पुस्तक को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

धन्यवाद
संपादक मण्डल

अस्वीकरण

पत्रिका मे प्रकाशित अंशों/लेखों को ए.आई. तकनीक का प्रयोग करके अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/सुवास प्रकोष्ठ, उत्तरदायी नहीं होगी।

अगर आप मूल लेखों को पढ़ना चाहते है तो आपकी सुविधा के लिए उनका स्रोत अनुक्रमणिका में मूल स्रोतों के अंतर्गत दिया गया है।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषयवस्तु	मूल स्रोत	प्रष्ठ संख्या
1.	**इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर दिनांक 25 नवंबर, 1966 का उद्घाटन भाषण,** द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	*Centenary Celebration (1866-1966) – Volume-II*	08
2.	**उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ दीवानी/सिविल न्यायपालिका का इतिहास एवं भूमिका** द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री बिंद बासिनी प्रसाद (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	*Centenary Celebration (1866-1966) – Volume-I*	12
3.	**हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इतिहास** द्वारा श्री सत्येन्द्र नाथ वर्मा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	*Post Centenary Silver Jubilee Celebration – Volume-I*	22
5.	**आपातकाल के दौरान मानवाधिकार** द्वारा श्री सोली जे. सोराबजी वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल	*www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalIntrest/vienna.pdf*	30
5.	**वियना संकल्प एवं कार्य योजना** 25 जून 1993 को वियना में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन द्वारा अंगीकृत	*www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalIntrest/vienna.pdf*	36
6.	**प्रथम तिमाही 2025 के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक)**	*Official website of this Hon'ble court : www.allahabadhighcourt.in*	58

7.	प्रथम तिमाही 2025 के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक)	*Official website of this Hon'ble court : www.allahabadhighcourt.in*	79
8	सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन		82
9.	न्यायाभा-न्याय की किरण का संपादक मण्डल		83

उद्घाटन भाषण

द्वारा माननीय डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
भारत के राष्ट्रपति

दिनांक 25 नवंबर, 1966 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह के अवसर पर

मित्रगण,
मुझे यहाँ आकर और इस उच्च न्यायालय के सौ वर्ष पूर्ण होने पर आपके उत्सव में सहभागिता से प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में, मेरा यहाँ होने का कोई दावा नहीं है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और किसी भी तरह से विधिक सूक्ष्मताओं से परिचित नहीं हूँ। परंतु, जब मेरे समक्ष दया याचिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, तो मुझे कुछ विधिक विवादों पर कुछ अधिवक्ताओं से सलाह लेनी पड़ती है, जिन पर मुझे विचार करना होता है। यह एक ऐसा संबंध है जो मेरा विधि और अधिवक्ताओं के साथ है। यह एक उल्लेखनीय घटना है, एक ऐतिहासिक अवसर है, जैसा कि आपके मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अन्य देशों से भी विधिक व्यवसाय के प्रतिनिधि हमें सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम उन सभी के ऋणी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वे इस देश में रहते हुए एक सुखद और उपयोगी समय व्यतीत करेंगे।

आप पाते हैं कि यह संस्था फोर्ट विलियम प्रेसीडेंसी का भाग होने से विकसित हुई है और धीरे-धीरे इसने वह स्थान प्राप्त कर लिया है जो आज है। इस न्यायालय से जुड़े न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने कानून और राजनीति के विकास में बहुमूल्य योगदान प्रदान किया है। उनमें से कई ऐसे थे जिन्हें हम अधिवक्ता-राजनेता संबोधित करते हैं। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सुंदर लाल, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू आदि के नाम पूर्व में ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा उल्लेख किए जा चुके हैं। वे सभी ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल कानून के क्षेत्र में प्रख्यात थे बल्कि उन्होंने हमारे देश के राजनीतिक जीवन में भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति में अमूल्य योगदान प्रदान किया जिसका हम सभी आज आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के अवसर पर उनके नामों को स्मरण किया जाना चाहिए।

कानून हमेशा से ही विकसित होता रहा है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर रहती है। यह स्वयं में कोई अंत नहीं है। हमारे अपने हिंदू कानून को ही लीजिए। हमारे यहां गोद लेने के तरीके और विवाह के प्रकार क्या हो गए हैं? वे लगभग समाप्त हो गए हैं और गोद लेने और विवाह दोनों ही कानूनों की जगह दूसरे तरह के कानून ने ले ली है। यह ऐसी चीज है जो केवल कानून में ही नहीं बल्कि धार्मिक रूपों में भी होती है। हमारे देश में एक बार यज्ञ, कर्म आदि में विश्वास करने वालों और आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को मानने वालों के बीच बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था। उस विवाद का निर्णय एक महिला मध्यस्थ के संदर्भ में हुआ था। जब शंकराचार्य वहां आए तो मंडन मिश्र एक यज्ञ कर रहे थे।

संन्यासी के वेश में शंकराचार्य को देखकर मंडन मिश्र ने कहा, "आज मैं जो महान यज्ञ कर रहा हूं, उसमें विघ्न डालने क्यों आए हो?"

संस्कृत श्लोक

जब मामला विवादित हो गया और मंडन मिश्र की पत्नी भारती को इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कहा गया, तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे मध्यस्थता की। अपने पति के मामले में पवित्रता, तटस्थता, निष्पक्षता, तटस्थता और पक्षपात से पूरी तरह

मुक्त होकर उन्होंने अपने पति के विरूद्ध निर्णय सुनाया। "निःसंदेह, आध्यात्मिक ज्ञान मात्र अनुष्ठान करने से श्रेष्ठ है" यही भारती ने कहा था। उन्होंने हमें एक अच्छे न्यायाधीश, एक अच्छे मध्यस्थ का आदर्श दिया। उनके पति के साथ उनके संबंध मायने नहीं रखते। यह तथ्य कि उन्हें इन दो महान लोगों के बीच मध्यस्थता करनी थी, मायने नहीं रखता। विशुद्ध निष्पक्षता और सत्य के प्रति निष्ठाः यही एकमात्र चीजें थीं जो उनके लिए महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने शंकराचार्य के पक्ष में निर्णय दिया, जिसके परिणामस्वरूप मंडन मिश्र उनके शिष्य बन गए, एक संन्यासी बन गए, सुरेश्वराचार्य, शंकराचार्य के पहले शिष्य, जिन्होंने श्रृंगेरी में अपना मठ चलाया। आप देख सकते हैं कि चीजें कैसे बदल गईं। आप देख सकते हैं कि एक महिला, जिसे इस तरह के विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए कहा गया था, ने कैसा व्यवहार किया। हम आजकल "न्यायाधीशों को दोषी ठहराने" , "न्यायाधीशों को बरी करने" , "बोलने वाले न्यायाधीशों", "चुप रहने वाले न्यायाधीशों" आदि के बारे में तरह-तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन भारती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने केवल खुद को कार्य में झोंक दिया, अध्ययन किया कि सत्य क्या है और कहा, "यह कि मेरे विचार से शंकराचार्य सही हैं, मंडन मिश्र गलत हैं।" उन्होंने इसे इस तरह से कहा। कानून एक ऐसी चीज है जो निरंतर गतिशील रहती है, जिसे लोगों के मिजाज, पारंपरिक तौर-तरीकों के साथ-साथ हमारे सामने मौजूद आधुनिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कानून का मूल्यांकन करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? कानून क्या कहता है? कानून का एक लक्ष्य सभी लोगों का कल्याण है। यह अमीरों या गरीब लोगों का कल्याण नहीं है, बल्कि इस देश के हर नागरिक का कल्याण है। कानून का यही लक्ष्य है और इसे पूरा करने का प्रयास करता है।

जब मैंने अपने मित्र, मुख्य न्यायाधीश को प्राचीन काल से इलाहाबाद के गौरव के बारे में बात करते सुना, तो मुझे एक श्लोक याद आया जिसमें कहा गया हैः "मुझसे प्राचीन गौरव के बारे में बात मत करो। मुझे बताओ कि तुम वर्तमान में क्या कर रहे हो।" हमारे लिए अपने अतीत पर गर्व करना आवश्यक नहीं है। एक नीग्रो आध्यात्मिक है जो यीशु की मृत्यु के बारे में कहता है, "क्या तुम वहाँ थे जब उन्होंने मेरे भगवान को सूली पर चढ़ाया था? क्या तुम वहाँ थे जब उन्होंने उन्हें कब्र में रखा था?" मैं साल्ट लेक सिटी में था जब यह भजन गाया गया था और वहाँ के नॉर्मन चर्च के प्रमुख ने मुझसे कुछ शब्द कहने के लिए कहा था। मैंने कहा, "आप ये काल्पनिक प्रश्न क्यों उठा रहे हैं कि आप दो हजार वर्ष पहले वहाँ उपस्थित थे या नहीं? समस्या यह है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आप आज नस्लीय कट्टरता, राष्ट्रीय अहंकार आदि की वेदी पर भगवान को सूली पर चढ़ा रहे हैं। दो हजार साल पहले जो घटित हुआ उसके बारे में बात करने में क्या आनंद है?" मुझे याद है कि मैंने यही कहा था।

धृतराष्ट्र, जो विदुर के पास गए, बोले :
संस्कृत श्लोक,

(आप जैसे लोग जो मूल्यों की समझ रखते हैं, जो ब्रह्मांड की सत्ता में विश्वास करते हैं, आप जो कार्य करते हैं वह पवित्र स्थान को और अधिक पवित्र बनाता है, न कि वह जो कुछ वर्ष पूर्व घटित हुआ था।) इसलिए हमें अपने न्यायालयों और संस्थानों को मनुष्य और मनुष्य के बीच, नागरिक और राज्य के बीच संबंधों का उचित मध्यस्थ बनाना चाहिए। यदि हमारे कानून का कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य है, तो उस लक्ष्य को हमारे संविधान की प्रस्तावना में खूबसूरती से वर्णित किया गया हैः न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वः न्याय को खरीदा नहीं जाना चाहिए, न ही किसी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष न्याय हमें उन लोगों द्वारा दिया जाना चाहिए जो न्याय के प्रति समर्पित हैं और जो कानून की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि वास्तविक न्याय हो सके। न्याय होना चाहिएः जो ताकतवरों की इच्छा को आवाज देता है, बहुत पहले से ही प्रचलित है। वह कानून नहीं है। न्याय को सभी व्यक्तियों, नागरिकों और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करना चाहिए और इसे नागरिक और नागरिक के मध्य, नागरिक और राज्य के मध्य और राज्य और संघ के मध्य विवादों पर उचित निर्णय देने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि मेरे मित्र भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। हमें इसी तरह का न्याय लाना है।

स्वतंत्रता एक प्रसिद्ध अवधारणा है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते: एक को माणिक पसंद है, दूसरे को हीरे पसंद हैं, तीसरे को मोती पसंद है। हमें सहन करना चाहिए। कोई भी समाज जो मतभेदों को सहन करता है, वह अपनी रक्षा करने में सक्षम है। कोई भी समाज जो मतभेदों को दबाता है- ऐसी संस्था को कोई नहीं बचा सकता। यह अपने चरित्र में कट्टर और फासीवादी हो जाता है। जब हम कहते हैं कि, जहां तक धर्म के रूपों का संबंध है, हम सब कुछ सहन करते हैं, तो यह केवल एक प्रकार की नकारात्मक सहनशीलता नहीं होनी चाहिए: बल्कि यह उन मूल्यों की सकारात्मक प्रशंसा होनी चाहिए जो विभिन्न धर्मों में स्वयं में निहित हैं। हमें यह प्राप्त हो गया है। हम चाहे जो भी नाम अपनाएं, चाहे हम प्रार्थना का कोई भी रूप (संस्कृत श्लोक), कहें, अगर यह ईमानदारी से इरादा किया जाता है, ईमानदारी से महसूस किया जाता है, तो यह परम सर्वोच्च (संस्कृत श्लोक) तक पहुंचता है और यही स्वतंत्रता का सही अर्थ है। स्वतंत्रता का अर्थ लाइसेंस नहीं है। यह केवल अधिकारों का दावा और दायित्वों का खंडन नहीं है, जैसा कि हमारे मित्र, राज्यपाल ने अभी आपको बताया है। आपको केवल अधिकारों को ही नहीं बल्कि दायित्वों को भी जानना चाहिए, जो आपके पास हैं।

यदि आप दायित्वों की अनदेखी करते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस बन जाती है। इसलिए,यह इस तरह की स्वतंत्रता है जिसे हम इस देश में सुरक्षित रखना चाहते हैं। स्वतंत्रता सभी के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। वह चाहे जो भी करे, जब तक वह समुदाय की नैतिक भावना और लोगों के सामान्य कल्याण के प्रतिकूल न हो, जब तक वह मौजूद है, हमें स्वतंत्रता को संरक्षित रखना होगा।

समानता एक ऐसी अवधारणा है जो अब उभर रही है। निहित स्वार्थ वाले लोग हमेशा समानता की किसी भी प्रवृत्ति का विरोध करेंगे। दूसरे कहेंगे, "क्यों, सभी को समान अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? कानून को प्रत्येक नागरिक की रक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए?" प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाने वाला कानून देश के सर्वोच्च व्यक्ति को दिए जाने वाले कानून से कमतर नहीं होना चाहिए। एक ही तरह के कानून को दोनों का सम्मान करना चाहिए। कानून को व्यक्तियों का सम्मान नहीं करना चाहिए। उसे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए। राजनीतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता के बीज के रूप में, व्यक्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य माना जाना चाहिए, न कि समाज या राज्य को। ये चीजें हो सकती हैं: लेकिन समानता का वास्तविक बिंदु यह है कि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना चरित्र, अपनी प्रतिभा विकसित करना संभव हो। हमें इन सभी चीजों को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए अन्यथा हमारी "समानता" केवल असमानता है। कुछ अन्य लोग कहते हैं, "असमानता प्रकृति का नियम है। हम सभी लोगों को समान नहीं बना सकते। वे अलग- अलग प्रतिभाओं और अलग-अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं।" लेकिन "समानता" का अर्थ यह है कि कानून को सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने चाहिए । यह नहीं कहता कि हमें सभी को एक बनाना चाहिए।

जब हमारे पास "भाईचारा", सह-भावना होती है, तो हमारे पास न केवल विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों आदि के लोग होते हैं, बल्कि हमारे पास दान की वह मूल भावना होती है जो सभी व्यक्तियों को एक साथ बांधती है-उस भावना का विकास, वह सहकारी भावना जिसे हमें आत्मसात करने के लिए कहा जाता है। हमारे लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय आचरण या नैतिक मानकों का न्याय करना आसान नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि एक राष्ट्र का कोई लोकाचार नहीं होता है। इसमें केवल हित होते हैं। हम अपने राष्ट्र का मूल्यांकन केवल इस बात से कर सकते हैं कि किसी विशेष आचरण का तरीका उसके हितों को पूरा करता है या नहीं करता है। लेकिन इस तरह के विचार को छोड़ देना चाहिए। हमें कानून के शासन के तहत शांति का एक प्रकार का पूरक लाना चाहिए। सभी राष्ट्रों को कानून की इस कसौटी के अधीन होना चाहिए। हम अपने देश के भीतर जो लाने का प्रयास करते हैं, हमें पूरे विश्व में लाने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। बंधुत्व का अर्थ है राष्ट्रों का ऐसा सहकारी संघ जहां राष्ट्र अपनी विविधता, अपनी वैयक्तिकता, अपनी विशिष्टता को बनाए रखेंगे, और फिर भी सभी के हितों की सेवा करेंगे। हम इसी तरह के भाईचारे पर जोर दे रहे हैं। ये दायित्व जो हमारे पास होने चाहिए, वे हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं। यह एक अच्छे जीवन की अवधारणा है: अच्छा जीवन एक न्यायपूर्ण जीवन है, एक ऐसा जीवन है जो मतभेदों को सहन करता है,

एक ऐसा जीवन है जहाँ हर किसी को अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ने का मौका मिलता है। यह एक ऐसा जीवन है जहाँ हम अपने राष्ट्र को कई राष्ट्रों में से एक के रूप में देखते हैं, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसे राष्ट्रों के समुदाय की सेवा करनी है।

ये वे आदर्श हैं जो हमारे संविधान में स्थापित किए गए हैं, और लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह संविधान है जिसमें प्रस्तावना में दी गई चार शर्तों के सभी निहितार्थ हैं। यह है कि लोगों को अपने दैनिक जीवन में अपनी क्षमता के अनुसार समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम इस देश के अच्छे नागरिक होंगे। अगर लोग कानून के प्रति सम्मान और कानून को लागू करने वाली अदालतों के प्रति सम्मान खो देते हैं, तो यह हमारे लिए एक बुरा दिन होगा। देश के लिए कानून का सम्मान करना आवश्यक है, देश की सरकार के लिए कानून का सम्मान करना और अदालतों के लिए कानूनी प्रशासन और न्याय के वितरण की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। अगर इस देश में कानून का शासन जारी रखना है, जैसा कि इसे जारी रखना है, तो यह बिल्कुल जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से तुच्छ कारणों से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और लोग उम्मीद करते हैं कि जब कानून का उल्लंघन होता है, तो कानून की महिमा का दावा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। यही सविनय अवज्ञा का अर्थ है जिसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। उन्होंने कानूनों का उल्लंघन किया लेकिन खुद को कानून द्वारा लगाए गए दंड के अधीन कर दिया। उन्होंने कभी उन दंडों से बचने की कोशिश नहीं की। यही हमें करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर हमारे लोगों में कानून के प्रति सम्मान पैदा होता है और अगर हमारी अदालतें बिना किसी दुर्भावना, द्वेष, पूर्वाग्रह या पक्षपात के कानून का प्रशासन करती हैं, तो कानून का सम्मान करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।

मुझे यहां आकर और यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आप सौ वर्ष का उपयोगी जीवन पूरा करने में सफल रहे हैं: और मैं आशा करता हूं कि अगली शताब्दी में आप अपनी परंपराओं को विकसित करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार उनमें वृद्धि करें।

उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ दीवानी/सिविल न्यायपालिका का इतिहास एवं भूमिका

द्वारा श्री बिंद बासिनी प्रसाद
सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

इस राज्य में अधीनस्थ सिविल न्यायपालिका में वर्तमान में निम्नलिखित अदालतें शामिल हैं:
1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश 44
2. दिवानी/सिविल एवं सत्र न्यायाधीश 401
3. दिवानी/सिविल न्यायाधीश 651
4. मुंसिफ 2051
5. न्याय पंचायत 8,662

स्वतंत्रता से पहले, जिला न्यायाधीशों को ज्यादातर भारतीय सिविल सेवा से लिया जाता था। कुछ सीमित पद, सैंतीस में से सात, धीरे-धीरे प्रांतीय न्यायिक सेवा के लिए खोल दिए गए। भारतीय सिविल सेवा के लिए कानून की डिग्री एक अनिवार्य योग्यता नहीं थी; लेकिन प्रांतीय न्यायिक सेवा के लिए यह एक आवश्यक योग्यता थी। बहुत कम अवसरों पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बार से सीधे की गई थी। इस तरह की अंतिम नियुक्ति लगभग वर्ष 1920 में श्री तेज नारायण मुल्ला की हुई थी। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सिविल सेवा का स्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा ने ले लिया। इसके बाद प्रशासनिक सेवा से जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती बंद हो गई और कुछ वर्षों तक जिला न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को प्रांतीय न्यायिक सेवा के संवर्ग से भरा गया। अप्रैल, 1953 में, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई सेवा की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाना था। सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस प्रकार था :

(I) दिवानी/सिविल और सत्र न्यायाधीशों के लिए : . 600-50-800-50-1200 प्रति माह, जिसमें दक्षता बार . 800 है। (II) जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए: . 800-50-1000-75-1750-50-1800 प्रति माह।

सेवा में दिवानी/सिविल और सत्र न्यायाधीशों के पद पर भर्ती निम्नलिखित द्वारा की जाती है - (I) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों से पदोन्नति और (II) उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद सीधी भर्ती।

(क) बैरिस्टर, अधिवक्ता, वकील या प्लीडर, जिनका अनुभव सात वर्ष से अधिक हो।

(ख) न्यायिक अधिकारी, अर्थात् मजिस्ट्रेट और राजस्व शक्तियों का प्रयोग करने वाले, जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम सात वर्ष की सेवा की हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने अब चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, 1966 में रिपोर्ट किए गए ए.एल.जे. 778 में उच्च न्यायिक सेवा नियमों को असंवैधानिक माना है। इसने सेवा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को अस्त-व्यस्त कर दिया है। उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए नए नियम बनाए जाने और प्रख्यापित किए जाने अनिवार्य हैं।

सिविल न्यायाधीश और मुंसिफ़, जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) कहा जाता है, का गठन करते हैं। सेवा की क्षमता और उसमें प्रत्येक प्रकार के पदों

का निर्धारण समय-समय पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जाती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की भर्ती नहीं की जानी है , जो सेवा में भर्ती के लिए आयोग द्वारा परीक्षा की घोषणा की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को 27 वर्ष से अधिक या 22 वर्ष से कम आयु का हो। उम्मीदवार को या तो बार-एट-लॉ होना चाहिए या उसके पास विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री होनी चाहिए या वह उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस करने का अधिकारी होना चाहिए। बार में दो वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त 1958 में हटा दी गई। प्रारंभ में मुंसिफ के पद पर नियुक्तियां की जाती हैं। दिवानी/सिविल जजों की नियुक्ति मुंसिफों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है 250-25-400-30-700-50-850 रूपये के वेतन के साथ दक्षता मानदंड 490 रूपये और 640 रूपये है। यद्यपि दिवानी/सिविल न्यायाधीश मुंसिफों की तुलना में कहीं अधिक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन उनका कोई अलग ग्रेड नहीं है, न ही उन्हें कोई विशेष वेतन दिया जाता है।

इस राज्य में दीवानी अदालतों का संगठन और अधिकार क्षेत्र बंगाल, आगरा और असम दीवानी न्यायालय अधिनियम, XII, 1887 द्वारा शासित है। जिला न्यायाधीशों और दीवानी न्यायाधीशों का आर्थिक अधिकार क्षेत्र असीमित है, जबकि मुंसिफों का अधिकार क्षेत्र केवल पाँच हज़ार रूपए तक है। जिला न्यायाधीशों के पास कुछ अधिनियमों के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र होता है और वे कुछ विशेष प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करते हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मामले या सार्वजनिक और धर्मार्थ ट्रस्टों से संबंधित मुकदमे। जिला न्यायाधीश एक विशेष मूल्यांकन तक के मुकदमों में दीवानी न्यायाधीशों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुन सकते हैं और लघु वाद न्यायालय के निर्णयों के संशोधनों पर सुनवाई कर सकते हैं। कुछ मामलों में, राजस्व न्यायालयों से अपील भी जिला न्यायाधीश के पास होती है। मुंसिफों के सभी अपीलें जिला न्यायाधीश के पास जाती हैं, लेकिन जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें दीवानी न्यायाधीशों को स्थानांतरित किए जाने पर दीवानी न्यायाधीशों द्वारा भी सुनी जा सकती हैं।

इस राज्य में न्याय पंचायतों की स्थापना यू.पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यू.पी. अधिनियम XXVI, 1947) द्वारा की गई थी; और अब राज्य में लगभग 9000 न्याय पंचायतें हैं। 1962 में, न्याय पंचायतों में स्थापित मुकदमों की संख्या 49164 थी। उनके पास सिविल, आपराधिक और राजस्व मामलों में अधिकार क्षेत्र होता है, और वे दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। (ए) अचल संपत्ति के संबंध में अनुबंध के अलावा अन्य अनुबंधों पर देय धन के लिए (बी) चल संपत्ति की वसूली के लिए या उसके मूल्य के लिए, (सी) गलत तरीके से चल संपत्ति को लेने या नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजे के लिए, और (डी) मवेशी अतिचार से होने वाले नुकसान के लिए। राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ या लोक सेवकों के खिलाफ, उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए, या नाबालिगों या पागलों के खिलाफ या साझेदारी खाते पर बकाया राशि के लिए या किसी अविभाजितता या विरासत के तहत हिस्सेदारी के लिए किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, तथा विरोधी पक्षकार को नोटिस देने के पश्चात, प्रादेशिक क्षेत्र का मुंसिफ, किसी न्याय पंचायत के समक्ष लंबित या उसके द्वारा विनिश्चित किसी मामले को वापस ले सकता है, तथा उसका निपटारा कर सकता है या उसे किसी अन्य न्याय पंचायत को अंतरित कर सकता है, या ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो न्यायसंगत हो।

उप-मंडल अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायतों से नामांकन आमंत्रित करने और उनकी जांच करने के बाद उन्हें जिला मजिस्ट्रेट को भेजता है, जो संबंधित सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति करता है। न्यूनतम दस और अधिकतम पच्चीस के अधीन रहते हुए, प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की उतनी संख्या होगी जितनी निर्धारित की जा सकती है। न्याय पंचायत की सदस्यता के लिए नामित प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए, हिंदी पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए। न्याय पंचायत में नियुक्ति के बाद वह ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार नियुक्त पंच अपने बीच से एक सरपंच और एक सहायक सरपंच का चुनाव करते हैं। मामलों के निपटारे के लिए सरपंच पांच पंचों की पीठों का गठन करता है। पीठों के बीच मामलों का वितरण क्रमिक क्रम में पीठों को मामले आवंटित करके

किया जाता है।

बहुत कम मामलों को छोड़कर, जिन्हें उसके असाधारण आरंभिक दिवानी/सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किया जा सकता है, तथा मुंसिफों और दिवानी/सिविल न्यायाधीशों की प्रथम अपीलें और लघु वाद न्यायालयों और न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन, समस्त मूल दिवानी/सिविल कार्य अधीनस्थ दिवानी/सिविल न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। 1962 में दिवानी/सिविल न्यायालयों में मूल वादों की संख्या 71912 थी। वर्ष के दौरान 16038 नियमित अपीलें और 3880 विविध अपीलें संस्थित की गईं। इसके अतिरिक्त न्यायालयों के समक्ष चुनाव, दिवालियापन, निष्पादन और विविध कार्य भी थे। इससे अधीनस्थ दिवानी/सिविल न्यायालयों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का एक व्यापक विचार मिलता है। प्रत्येक प्रकार के कार्य के आंकड़े उद्धृत करना अनावश्यक है। दिवानी/सिविल न्याय प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट में इनका विस्तृत विवरण दिया जाता है।

यद्यपि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार, यह अलगाव केवल दिवानी/सिविल मामलों में ही पूर्ण है, क्योंकि दिवानी/सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 233 से 236 के तहत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में हैं। मोटे तौर पर, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तीन प्रकार के न्यायालय हैं: (1) दिवानी/सिविल (2) आपराधिक और (3) राजस्व। आपराधिक और राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी कार्यकारी सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में हैं। संविधान के अनुच्छेद 237 के तहत मजिस्ट्रेट पर प्रावधान लागू करने वाली कोई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ दिवानी/सिविल न्यायपालिका ने ईमानदारी, स्वतंत्रता और कार्यकुशलता के लिए उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसे ऐसे व्यक्तियों से प्रशंसा और सराहना प्राप्त हुई है, जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों थे और जो मत बनाने में सक्षम थे। 1942 में स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक लड़ाई के बाद जेल से रिहा होने पर न्यायपालिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा मिली थी। इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर अर्ल ऑफ सेलबोर्न ने 1883 में दिए गए एक भाषण में कहा था कि उन्हें "यह देखने का पर्याप्त अवसर मिला कि किस तरह से दिवानी/सिविल मामलों में भारतीय न्यायाधीश अपना कर्तव्य निभाते हैं।" उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि "भारतीय न्यायाधीशों के फैसले, एक सामान्य नियम के रूप में, अंग्रेजी न्यायाधीशों के फैसलों के साथ सबसे अनुकूल तुलना करते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि हर मामले में, "निष्ठा, विद्वता, ज्ञान और निर्णयों की ठोस और संतोषजनक प्रकृति के मामले में भारतीय न्यायाधीश उतने ही सक्षम थे जितने कि अंग्रेज़ न्यायाधीश।" सर लैंसलॉट सैंडरसन ने जून 1927 में लंदन में दिए गए भाषण में अधीनस्थ न्यायाधीशों के काम की गवाही दी और कहा कि भारत में अधीनस्थ न्यायाधीशों के काम करने के तरीके के संबंध में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में उनके सहयोगियों की टिप्पणियों को सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि मामलों की सुनवाई कितनी सावधानी से की गई, निर्णय में कितनी विद्वता दिखाई गई और उन्होंने बताया कि न्यायिक समिति की टिप्पणियों से पता चलता है कि "भारत के न्यायालयों में सर्वोत्तम परंपराओं को बनाए रखा गया है।"

1886 के एचिसन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों पर नियुक्त भारतीयों द्वारा प्रदर्शित "न्यायिक पद के लिए बहुत महान योग्यता" की बात की थी; और श्री एस. पी. सिन्हा (बाद में लॉर्ड सिन्हा) ने इस्लिंगटन आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में "मुंसिफों और अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा किए गए अत्यंत संतोषजनक कार्य" की बात की थी।

अधीनस्थ दिवानी/सिविल न्यायपालिका को ऐसे लोगों से भी ऐसी ही प्रशंसा मिली है जो उनके काम से अधिक निकटता से जुड़े थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर हेनरी रिचर्ड्स ने वायसराय द्वारा उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में जिला न्यायालयों से प्राप्त मूल्यवान सहायता और उन न्यायालयों द्वारा की गई "गहन

और गहन जांच" की सराहना की। मुख्य न्यायाधीश ग्रिमवुड मेयर्स ने 1924 में यू.पी. न्यायिक अधिकारी संघ के चौथे सत्र का उद्घाटन करते हुए उच्च न्यायालय की ओर से अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा प्रदर्शित योग्यता और "उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के प्रति सम्मान" की सराहना की। कुछ वर्षों बाद मुख्य न्यायाधीश सर शाह मुहम्मद सुलेमान ने कहा कि प्रांतीय न्यायिक सेवा इस बात पर गर्व कर सकती है कि उसके जो सदस्य उच्च न्यायालय में आए हैं, वे महान अनुभव, शिक्षा और योग्यता वाले प्रतिभाशाली न्यायाधीश साबित हुए हैं। प्रांतीय सेवा ने ऐसे प्रतिष्ठित और विशिष्ट न्यायाधीशों को उत्पन्न किया है, जिन्होंने वर्षों तक पीठ की शोभा बढ़ाई और अपनी सुस्पष्ट सोच, स्पष्ट अभिव्यक्ति और दृढ़ निर्णय क्षमता के लिए उच्च सम्मान प्राप्त किया।

सर जॉन गिब थॉम ने 1938 में यू.पी. न्यायिक सम्मेलन के ग्यारहवें सत्र के अपने उद्घाटन भाषण में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की कार्यकुशलता, परिश्रम और कर्तव्य के प्रति उच्च भावना की प्रशंसा की। मार्च 1930 में अवध मुख्य न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों ने भी इसी तरह की प्रशंसा की। सर लुइस स्टुअर्ट ने अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर बताया कि मूल मामलों में अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा इंग्लैंड में उच्च न्यायालय के किंग्स बेंच और चांसरी डिवीजनों के न्यायाधीशों द्वारा किया गया था और उन्होंने "अधीनस्थ न्यायाधीशों के समक्ष मामलों के त्वरित निपटान और सावधानीपूर्वक और गहन सुनवाई के दुर्लभ संयोजन" की बात की। 1933 में यू.पी. न्यायिक अधिकारी संघ के आठवें अधिवेशन में सर सैय्यद वजीर हसन ने न केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच बल्कि राज्य और उसके अधीन अधीनस्थ न्यायपालिका के बीच न्याय के वितरण में निर्णय की स्वतंत्रता, आचरण की शुद्धता और कर्तव्य की उच्च भावना की बात की थी। 1946 में माननीय न्यायमूर्ति गुलाम हसन ने न केवल सेवा के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित कार्यकुशलता, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण की ओर इशारा किया, बल्कि यह भी कहा कि सेवा ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है जिन पर किसी भी न्यायिक प्रणाली को गर्व होगा और उन्होंने अपने निर्णयों से न्यायिक इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो हमेशा कानूनी कौशल, उद्योग और उच्च कोटि की योग्यता से चिह्नित होते हैं।

श्री चिंतामणि ने 1919 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि "प्रांतीय न्यायिक अधिकारियों ने जिस ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन किया" और जिन्होंने "कठिन और अच्छे काम के बल पर न्यायिक प्रशासन के पूरे स्वर को ऊंचा उठाया"। दिवानी/सिविल न्याय समिति की रिपोर्ट में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में सर तेज बहादुर सप्रू ने अधीनस्थ न्यायाधीशों के बारे में कहा कि वे दक्षता के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, हालांकि उन्होंने बताया कि वे इतने अधिक काम के बोझ तले दबे हुए थे कि वे कानून के बढ़ते साहित्य से अवगत रहने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे।

उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायिक सेवा ने न केवल सैयद महमूद, पी.सी. बनर्जी, लाल गोपाल मुखर्जी और कई अन्य जैसे उच्च न्यायालय के प्रख्यात न्यायाधीशों को जन्म दिया है, जिन्होंने विधि रिपोर्टों के पन्नों पर अपने निर्णयों से अपनी ख्याति बिखेरी है, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी दिए हैं, जिन्होंने इसी तरह के अन्य क्षेत्रों में जाने का निर्णय लिया और अद्वितीय प्रतिष्ठा प्राप्त की। सर सैयद अहमद जब अपने प्रारंभिक जीवन में राज्य के अधीनस्थ न्यायाधीश थे, तो वे शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र थे और उन्होंने अलीगढ़ में एम.ए.ओ. कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। उनके योग्य पुत्र सैयद महमूद राज्य में जिला न्यायाधीश थे और अपनी असाधारण योग्यताओं के कारण, जिला न्यायाधीशों की श्रेणी III में रहते हुए भी उन्हें उच्च न्यायालय की बेंच में अभूतपूर्व पदोन्नति मिली। विधि रिपोर्टों ने विधि के उनके गहन ज्ञान और कानूनी ज्ञान की सामान्य सीमाओं से परे विषयों के गहन अध्ययन की अमर स्मृतियाँ छोड़ी हैं। सैयद अकबर हुसैन को आज भी उर्दू शायरी के लिए महान कवि हाली के साथ स्थान दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक जीवन का समृद्ध चित्रण करने वाली शायरी आज भी गायी जाती है। राज्य के अधीनस्थ न्यायाधीश श्री बैजनाथ दास एक सक्रिय समाज सुधारक थे और सेवा में रहते हुए सामाजिक सम्मेलनों की अध्यक्षता करते थे। एक अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश श्री एस.सी. बसु संस्कृत और पाली में विद्वत्ता और शोध के लिए प्रसिद्ध हुए। सेवा के एक अन्य सदस्य श्री पी.सी. मोघा दो पुस्तकों के लेखक थे

- "द लॉ ऑफ प्लीडिंग्स" और "कन्वेयन्सर" -इन पुस्तकों ने अग्रणी काम किया और अपने पहले प्रकाशन के बाद से कई संस्करणों में छप चुकी हैं। सेवा के कई अन्य सदस्य हैं, जिनमें से कुछ जीवित हैं, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल की है।

वर्ष 1915 तक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ राज्य की न्यायिक सेवा ने अपने ईमानदारी, निष्ठा और अपने विधि विशेषज्ञों की कानूनी सूझबूझ के लिए पूरी तरह से गौरवशाली प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। भारत सरकार अधिनियम, 1915 ने निम्नलिखित स्रोत निर्धारित किए जिनसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ की जा सकती थीं:
(क) बैरिस्टर, उनके लिए एक तिहाई आरक्षण के साथ,
(ख) आई.सी.एस. जिला न्यायाधीश, उनके लिए एक तिहाई आरक्षण के साथ और
(ग) उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील या दिवानी/सिविल न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले वकील।

एक समय जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ।। से अधिक नहीं थी, उनमें से कम से कम दो राज्य न्यायिक सेवा के सदस्यों में से होते थे। वर्ष 1925 में जब अवध न्यायालय अधिनियम के तहत अवध मुख्य न्यायालय का गठन किया गया था, तो अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि कुल पाँच न्यायाधीशों में से कम से कम एक राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों में से होगा और कम से कम दो भारतीय दिवानी/सिविल सेवा के सदस्य होंगे, जिन्होंने कम से कम 3 वर्षों तक जिला न्यायाधीश के रूप में काम किया हो।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के स्रोत वही बने रहे, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1915 में परिकल्पित था। आरक्षण के अभाव में राज्य न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1935 में 2 से बढ़कर वर्ष 1954 में 7 हो गई।

भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल निम्नलिखित दो स्रोतों से की जाती है:
(क) कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, और
(ख) न्यायिक सेवा के सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य अब जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। इस प्रकार राज्य के सभी जिला न्यायाधीश अब अधीनस्थ न्यायपालिका (जिसे उच्च न्यायिक सेवा के रूप में जाना जाता है) के सदस्य हैं।

भारत सरकार अधिनियम, 1915 से शुरू होकर भारत के संविधान के प्रावधानों में अधीनस्थ न्यायपालिका के महत्व को मान्यता देना, उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा किए गए अग्रणी कार्य के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।

ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से न्यायिक प्रणाली का विकास (1600-1857)

ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से न्यायिक प्रणाली के विकास की संक्षिप्त जांच करना रुचिकर होगा, हालांकि हम केवल कंपनी के शासनकाल के दौरान न्यायिक प्रणाली के विकास

से चिंतित हैं और इस बात से नहीं कि कंपनी, एक व्यापारिक संस्था, किस तरह से एक राजनीतिक शक्ति बन गई; 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को एशिया के सभी हिस्सों में व्यापार करने के लिए एक चार्टर प्रदान किया। 1601 में, महारानी ने कंपनी को "ऐसे और इतने सारे उचित कानून बनाने, लागू करने और बनाने की शक्ति दी, जो उस समय या उनमें से अधिकांश के लिए, कंपनी की अच्छी सरकार के लिए आवश्यक और सुविधाजनक प्रतीत होंगे"। चार्टर को समय-समय पर, 1609, 1661, 1668, 1698 और इसी तरह, परिवर्धन और परिवर्तनों के साथ, लगातार ब्रिटिश संप्रभुओं द्वारा नवीनीकृत किया गया था। कंपनी ने मुगल सम्राटों की अनुमति से, अपने कारखानों के लिए किलेबंदी की, जिनमें से चार मूल रूप से सूरत, मद्रास, बॉम्बे और हुगली में बनाए गए थे। आखिरी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 1640 में स्थापित किया गया था, क्योंकि बंगाल में शुरू हुए नियम समय के साथ इस राज्य के क्षेत्रों में फैल गए। इन किलों के भीतर भारतीयों के साथ-साथ यूरोपीय लोगों ने भी अपने घर बनाए; और जब "नबाब, इस कारण से, उन मूल निवासियों को न्याय दिलाने के लिए काजी या न्यायाधीश को भेजने वाला था, तो कंपनी के कर्मचारियों ने उसे इस कार्यवाही से दूर रहने के लिए रिश्वत दी"। कंपनी की सरकार औपचारिक रूप से 1857 में समाप्त हो गई, जब महान विद्रोह हुआ, जिसे अब भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम, 1858 (21 और 22 विक्ट. सी. 106) द्वारा, जो 1 सितंबर, 1858 को लागू हुआ, यह घोषित किया गया कि उसके बाद से 'भारत का शासन रानी द्वारा और उनके नाम पर' होगा और कंपनी की सभी शक्तियाँ और क्षेत्र रानी में निहित होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को विनियमन प्रांत के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे ब्रिटिश संसद के चार्टर अधिनियमों के तहत गवर्नर-जनरल द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा प्रशासित थे। अन्य भाग, जैसे अवध, गैर-विनियमन क्षेत्र थे क्योंकि उन्हें विनियमों द्वारा नहीं बल्कि गवर्नर-जनरल के कार्यकारी आदेशों द्वारा प्रशासित किया जाता था। इसलिए, न्यायिक प्रणाली मूल रूप से अपने चरित्र में, दोनों भागों में भिन्न थी। यह इस राज्य में पहले दो न्यायिक सेवाओं के अस्तित्व का कारण है, एक अवध में और दूसरी राज्य के बाकी हिस्सों में, हालांकि अब वे एकीकृत हो गए हैं।

कंपनी के शुरूआती दौर में, 1618 में, किंग जेम्स के राजदूत सर थॉमस रो ने तत्कालीन मुगल सम्राट के साथ संधि करके सूरत की फैक्ट्री के लिए विशेषाधिकार हासिल किया था, जिससे कंपनी को केवल यूरोपीय लोगों के बीच विवादों का फैसला करने का अधिकार मिल गया था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, यूरोपीय लोगों के बीच न्याय प्रशासन के लिए कंपनी द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों ने किलेबंदी के भीतर बसे भारतीयों के बीच मामलों की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र को भी हड़प लिया।

जॉर्ज प्रथम द्वारा दिए गए 1726 के चार्टर के द्वारा, क्राउन ने मद्रास, बॉम्बे और फोर्ट विलियम में नगर पालिकाओं और मेयर के न्यायालयों की स्थापना की, जिनमें से प्रत्येक में एक मेयर और नौ एल्डरमैन शामिल थे, जिनमें से सात, मेयर के साथ, स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश नागरिक होने चाहिए थे। यह ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्थापित अदालतों का पहला प्रकार था। उन्हें पक्षों के बीच सभी दिवानी/सिविल मुकदमों, कार्यों और दलीलों की कोशिश करने, सुनने और निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। उसी चार्टर के तहत, तीनों नगरों के गवर्नर और परिषद को गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में गठित किया गया, जहां मेयर कोर्ट के निर्णयों के विरूद्ध अपील की जा सकती थी, यदि मामला 1,000 पगोडा से कम राशि से संबंधित हो। ; तब एक पैगोडा लगभग 8 शिलिंग के बराबर होता था। सरकारी न्यायालय का निर्णय अंतिम होता था; लेकिन यदि मामला 1,000 पगोडा या उससे अधिक की राशि से संबंधित होता था, तो उसके विरूद्ध किंग-इन-काउंसिल में अपील की जा सकती थी।

इसी चार्टर के तहत, प्रत्येक शहर के गवर्नर और परिषद के पांच सदस्यों को शांति न्यायाधीश नियुक्त किया गया और एक आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया, जिसमें ग्रैंड और पेटी जूरी की सहायता से उच्च राजद्रोह को छोड़कर सभी अपराधों की सुनवाई और दंड देने की शक्तियां थीं, ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड में ओयर एंड टर्मिनेर और जेल डिलीवरी

के आयुक्त करते थे।

जॉर्ज प्रथम के 1726 के चार्टर को एक अन्य चार्टर द्वारा नवीनीकृत किया गया, जिसे 1753 में जॉर्ज II द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया, जिसने मेयर के न्यायालयों को जारी रखा, जिसमें कुछ संशोधनों का उद्देश्य उन दोषों को दूर करना था जिनके बारे में कंपनी ने शिकायत की थी। नए चार्टर ने आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए क्वार्टर सेशन कोर्ट की स्थापना की, और तीनों प्रेसीडेंसी शहरों में से प्रत्येक में एक छोटे से मामले की अदालत की भी स्थापना की, जिसे कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कहा जाता है, ताकि उन मुकदमों का निपटारा किया जा सके "जहां ऋण, कर्तव्य या विवादित मामला पांच पैगोडा से अधिक न हो"। इन सभी न्यायालयों को निदेशकों के न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कर दिया गया, जिन्हें चार्टर द्वारा भारत में स्थापित न्यायपालिका के कई न्यायालयों के अच्छे प्रशासन और विनियमन के लिए उप-नियम, नियम और अध्यादेश बनाने के लिए अधिकृत किया गया था।

नए चार्टर द्वारा किया गया मुख्य परिवर्तन यह था कि उन्होंने जो न्यायालय स्थापित किए थे, वे अपने दिवानी/सिविल अधिकार क्षेत्र में उन पक्षों के बीच के मुकदमों तक सीमित थे जो उन कई शहरों के "मूल निवासी" नहीं थे, जिन पर अधिकार क्षेत्र लागू होता था। मूल निवासियों के बीच के मुकदमों को मेयर के न्यायालयों द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाना था जब तक कि पक्षों की सहमति न हो। वे सभी इंग्लैंड के राजा, महामहिम के न्यायालय थे, और इंग्लैंड के सामान्य कानून को लागू करते थे। लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र कंपनी की किलेबंदी के भीतर सीमित था। इन किलेबंदी के बाहर, काजी और मुफ़्ती मुगल शासन के तहत, आपराधिक मामलों में मोहम्मडन कानून के अनुसार और दिवानी/सिविल मामलों में पर्सनल लॉ के अनुसार न्याय करते रहे।वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल क्षेत्र कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कई चरणों में आए। इसलिए, इन क्षेत्रों में न्यायिक व्यवस्था भी क्रमिक रूप से बदलती गई। विलियम क्रुक ने अपनी पुस्तक "एन.-डब्ल्यू.पी. ऑफ इंडिया" (1897) में पृष्ठ 122 और 123 पर उन चरणों का सारांश दिया है, जिनसे इस राज्य के विभिन्न हिस्से कंपनी के अधिकार में आ गए।

1835 तक अवध को छोड़कर उत्तर प्रदेश में शामिल सभी क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे और इसके हिस्से के रूप में गवर्नर-जनरल द्वारा शासित थे। बंगाल में शुरू की गई न्यायिक प्रणाली इस राज्य तक विस्तारित हुई, जब इस राज्य के क्षेत्र के विभिन्न हिस्से कंपनी के प्रभाव में आए।

कार्यपालिका और न्यायिक अधिकारियों के बीच टकराव या संघ पृथक्करण और फिर वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के पुनर्मिलन का वर्णन करने के लिए जगह की कमी है। न्यायालयों के इतिहास और संविधान पर अपने व्याख्यानों में कॉवेल ने इसके बारे में पर्याप्त और ज्ञानवर्धक विवरण दिए हैं।

लॉर्ड क्लाइव 1765 में आखिरी बार भारत आए थे। उन्होंने मुगलों की संप्रभुता का लाभ उठाने का फैसला किया। उन्होंने मुगल सम्राट से राजस्व संग्रह की शक्ति, दीवानी का अनुदान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और राजा शाह आलम द्वारा 12 अगस्त, 1765 को दिए गए फरमान को प्राप्त करके इसमें सफल हुए। भारत में राजस्व संग्रह में तब दीवानी न्याय का पूरा प्रशासन शामिल था। निज़ामत या आपराधिक न्याय का प्रशासन फिलहाल मुगलों के लेफ्टिनेंट, मुर्शिदाबाद के 'नबाब' के पास छोड़ दिया गया था। राजस्व का अधिकांश भाग, और इससे भी अधिक दीवानी न्याय का प्रशासन, 11 मई, 1772 तक 'देशी' एजेंसी के माध्यम से संचालित किया गया था, जब 'कंपनी, उसी तिथि की अपनी घोषणा द्वारा, 'दीवान के रूप में सामने आई' और अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व संग्रह और न्याय के प्रशासन का सीधा प्रभार संभाला।

उसी वर्ष वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। उन्होंने 21 अगस्त, 1772 को पारित न्यायिक विनियमों के तहत, प्रत्येक जिले में राजस्व कलेक्टरों की अध्यक्षता में मुफ़स्सिल दीवानी अदालतें स्थापित कीं। ये अदालतें सभी विवादों, वास्तविक और व्यक्तिगत, विरासत, विवाह और जाति के सभी मामलों और ऋण, अनुबंध और किराए की मांग के सभी दावों का संज्ञान लेती थीं। हालाँकि, ज़मींदारी और तालुकदारी संपत्ति के उत्तराधिकार के सवाल इन अदालतों के समक्ष प्रस्तुत नहीं

किए गए थे, बल्कि गवर्नर-इन-काउंसिल के निर्णय के लिए आरक्षित थे। उसी विनियमन के तहत प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत नामक एक आपराधिक न्यायालय भी स्थापित किया गया था। इसमें एक काजी और एक मुफ़्ती, मोहम्मडन कानून की व्याख्या करने के लिए नियुक्त दो मौलवियों की सहायता से सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई करते थे। राजस्व के अंग्रेजी कलेक्टरों को इन अदालतों की कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। इसी विनियमन द्वारा स्थापित सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत क्रमशः दिवानी/सिविल और फौजदारी न्यायालयों की अपीलों की सुनवाई करती थी।

1774 में, कलकत्ता में मेयर कोर्ट को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, 1772 (13 जियो. III सी. 63) के तहत दिए गए चार्टर द्वारा, उस शहर में एक नया क्राउन कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर कहा जाता है, स्थापित किया गया, जिसे 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके खिलाफ़ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा, जिसे 1781 में पारित किया गया और जिसे एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट (21 जियो. III सी. 70) के रूप में जाना जाता है, यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को देश की प्रथा या गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के नियमों के अनुसार, राजस्व से संबंधित किसी भी मामले में, या इसके संग्रह में किए गए किसी भी कार्य से संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं होगा। सदर दीवानी अदालत का गठन, पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा, रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में किया गया था; और इसी अधिनियम द्वारा पहली बार यह भी प्रावधान किया गया कि £5,000 (50,000 रूपये) या उससे अधिक मूल्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के विरूद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकेगी। इस प्रकार, यद्यपि इस न्यायालय की स्थापना रॉयल चार्टर द्वारा नहीं की गई थी, फिर भी यह कंपनी की सामान्य अदालतों से अलग थी और इसकी अंतिम स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता और मंजूरी से हुई थी।

1793 में, कॉर्नवॉलिस ने मुफ़स्सिल अदालतों को पूरी तरह से पुनर्गठित किया। उस वर्ष गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने कई विनियम पारित किए, जिनमें छोटे-मोटे अपराधों की सुनवाई के लिए जिला और नगर मजिस्ट्रेट की अदालतें और बंगाल के प्रेसीडेंसी में चार सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए, जो अंग्रेज़ जजों की देखरेख में थे, जिन्हें मुस्लिम कानून में पारंगत भारतीयों की सहायता प्राप्त थी, ताकि पहले तो अपराध या दुष्कर्म के आरोपी व्यक्तियों की सुनवाई की जा सके और गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को सदर निज़ामत अदालत में बैठने और पूरे प्रेसीडेंसी में आपराधिक न्याय के प्रशासन की देखरेख करने में सक्षम बनाया जा सके। दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जिला और नगर न्यायाधीशों की अदालतें बनाई गईं। कई जिला और नगर अदालतों से दीवानी अपीलों की सुनवाई के उद्देश्य से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में चार प्रांतीय अपील न्यायालय स्थापित किए गए; कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत को अपीलीय अधिकारिता और 1,000 रूपये से अधिक मूल्य के सभी मुकदमों में निचली अदालतों पर पर्यवेक्षण की सामान्य शक्ति प्राप्त थी। सिटी और जिला अदालतों के नीचे, निचले न्यायाधीशों की दो श्रेणियाँ थीं। 'सबसे पहले, उन अदालतों के रजिस्ट्रार जिन्हें न्यायाधीशों द्वारा अधिकृत किए जाने पर, 200 रूपये से अधिक की राशि के मामलों की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार दिया गया था; उनके आदेश तब तक वैध नहीं थे जब तक कि उन्हें न्यायाधीश द्वारा संशोधित और प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया जाए। न्यायाधीशों की अगली और निचली श्रेणी नेटिव कमिश्नर थे जिन्हें 1793 के विनियमन XL द्वारा 50 सिक्के रूपये से अधिक मूल्य की धनराशि या व्यक्तिगत संपत्ति के लिए दीवानी मुकदमों की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। इन अधिकारियों में से मुख्य आयुक्तों को सदर अमीन और बाकी को मुंसिफ कहा जाता था।

बंगाल प्रणाली के अनुरूप दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1795 में बनारस में तथा वर्ष 1803-05 में विजित एवं अधिग्रहित प्रांतों, अर्थात अवध को छोड़कर वर्तमान उत्तर प्रदेश के शेष भागों में की गई। उसी समय, दो प्रांतीय अपील न्यायालय और सर्किट न्यायालय भी स्थापित किए गए, एक बनारस में और दूसरा बरेली में; और कलकत्ता में सदर अदालतों के अधिकार क्षेत्र को विभिन्न विनियमों द्वारा इन स्थानों तक बढ़ाया गया। 1832 में, 1831 के विनियमन VI द्वारा उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (अवध को छोड़कर वर्तमान उत्तर प्रदेश) के लिए एक अलग

सदर दीवानी और निज़ामत अदालत की स्थापना की गई, जिसमें कलकत्ता में सदर अदालतों के पास मौजूद शक्तियों के समान अधिकार थे।

यह उस प्रणाली की सामान्य रूपरेखा है जो दीवानी और आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए स्थापित की गई थी। वर्ष 1793 न्यायिक स्वतंत्रता के युग का प्रतीक है। सरकार ने उनके न्यायिक और कार्यकारी कार्यों को अलग करने और बाद के कार्यों को करने वाले अधिकारियों को पूर्व के कार्यों का प्रयोग करने वालों के अधिकार के अधीन बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार स्थापित अदालतें काफी समय तक, लगभग अस्सी वर्षों तक चलीं; लेकिन समय-समय पर विस्तार और निरसन की प्रक्रिया के कारण, उन्हें बनाने वाले वैधानिक प्रावधान कुछ अस्पष्टता में लिपटे हुए हैं।

1831 के विनियमन V ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। प्रस्तावना में उद्देश्य यह बताया गया कि देश के प्रशासन से जुड़े अधिक महत्वपूर्ण ट्रस्टों में धीरे-धीरे सम्मानित मूल निवासियों को शामिल किया जाएगा। मुंसिफ को 300 रूपये मूल्य की धन- और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति के लिए मुकदमों की सुनवाई करने और निर्णय करने की शक्ति दी गई, और 300 रूपये मूल्य की भूमि के संबंध में मुकदमों को छोड़कर, ऐसी भूमि को छोड़कर जो राजस्व के भुगतान से छूट प्राप्त थी। न्यायाधीशों को किसी भी ऐसे मुकदमे को सदर अमीनों को संदर्भित करने का अधिकार दिया गया जिसका मूल्य 1,000 रूपये से अधिक नहीं था। एक नया कार्यालय, प्रिंसिपल सदर अमीन का गठन किया गया, जिसके पास 5,000 रूपये से अधिक मूल्य के मुकदमों को संदर्भित किया जा सकता था। रजिस्ट्रार की अदालतें समाप्त कर दी गईं; प्रांतीय अपील न्यायालयों को धीरे-धीरे हटा दिया गया, और दो साल में, अंततः समाप्त कर दिया गया; और न्यायाधीशों को 1000 रूपये से अधिक मूल्य के सभी मुकदमों में मूल अधिकार क्षेत्र दिया गया। 5,000 तक के जुर्माने के लिए सीधे सदर दीवानी अदालत में अपील की जा सकती है।

1793 और 1831 के बीच की अवधि में दिवानी/सिविल न्यायालयों के साथ कलेक्टरों के संबंधों में काफी परिवर्तन हुए।
बंगाल प्रेसीडेंसी में दिवानी/सिविल न्यायालयों के संबंध में, कानून के पाठ्यक्रम ने कुछ न्यायाधीशों के सटीक कार्यों के बारे में काफी भ्रम उत्पन्न किया था। इस विषय पर मूल कानून 1793 के विनियमों में निहित था, जिसके प्रावध. ानों को क्रमशः बनारस और सौंपे गए और विजित प्रांतों में 1795, 1803 और 1804 में विस्तारित किया गया था।

न्यायालय प्रणाली स्वयं, जिस विधान पर वह आधारित थी, उससे संबंधित होने तक, अति निकट समय तक कुछ अस्पष्टता से घिरी रही। वर्ष 1871 से पूर्व किसी भी समय दीवानी न्यायालयों के गठन और क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए, तेरह विभिन्न अधिनियमों में विभाजित विधायी अंशों का अन्वेषण कर उन्हें संयोजित करना आवश्यक है।

1868 में ही बंगाल प्रेसीडेंसी में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों सहित विभिन्न न्यायाधीशों के पुराने पदनामों में बदलाव किया गया था। 1868 के अधिनियम XVI द्वारा सदर अमीन के पद को समाप्त कर दिया गया और प्रधान सदर अमीनों को 'अधीनस्थ न्यायाधीश' नामित किया गया। तीन साल बाद, 1871 का बंगाल दिवानी/सिविल न्यायालय अधिनियम VI, जिसने बंगाल प्रेसीडेंसी में दिवानी/सिविल न्यायालयों के गठन से संबंधित सभी पिछले अधिनियमों और विनियमों को निरस्त कर दिया, 'जिला न्यायाधीशों, अतिरिक्त न्यायाधीशों, अधीनस्थ न्यायाधीशों और मुंसिफों' की नियुक्ति का प्रावधान किया। अंततः, वर्तमान बंगाल, आगरा और असम दिवानी/सिविल न्यायालय अधिनियम XII, 1887 आया, जिसने उपरोक्त प्रांतों में दिवानी/सिविल न्यायालयों की उन्हीं चार श्रेणियों के लिए भी प्रावधान किया।ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा स्थापित न्यायालयों ने अधिकांशतः अंग्रेजी कानून लागू किया, चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी; हिंदुओं और मुसलमानों के पक्ष में अपवाद बनाए गए। इनमें से किसी भी धर्म के पक्षकारों के खिलाफ़ मुकदमों में, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया हो, चाहे वह यूरोपीय हो या भारतीय, प्रतिवादी पर लागू कानून ही लागू होता था। न्यायालयों की कार्यवाही प्रक्रिया के अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होती थी। कम से कम 1834 तक, वे अधिकांशतः केवल संसद

के विधायी अधिकार और सरकार के ऐसे विनियमों के अधीन थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार और पंजीकृत करना चुन सकता था।

दूसरी ओर, मुफ़स्सिल न्यायालयों का अंग्रेजी कानून से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि वे सभी मामलों में सरकारी नियमों के अधीन थे, और जब हिंदू या मुस्लिम कानून लागू नहीं होते थे, या जब कोई नियम लागू नहीं होते थे, तो उन्हें न्याय, समानता और अच्छे विवेक के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता था।

अवध को 1856 में अपने में मिला लिया गया, जिस पर बंगाल के न्यायिक नियम लागू नहीं होते थे। अन्य सभी गैर-विनियमन प्रांतों की तरह, यह भी एक गैर-विनियमन क्षेत्र बना रहा और अवध में न्यायिक प्रणाली अन्य गैर-विनियमन क्षेत्रों के पैटर्न का पालन करती थी और उत्तर-पश्चिम प्रांतों से अलग थी।

अवध में 1865 के अधिनियम XIV द्वारा विभिन्न ग्रेड के न्यायालय स्थापित किए गए, जो उसी अधिनियम के तहत मध्य प्रांतों के लिए प्रदान किए गए न्यायालयों के समान थे। लेकिन, चूंकि यह अधिनियम मुख्य रूप से मध्य प्रांतों के संदर्भ में तैयार किया गया था, इसलिए अवध के संबंध में यह अधूरा और असुविधाजनक पाया गया। तदनुसार, 1871 में अवध दिवानी/सिविल न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जो अवध के सभी दिवानी/सिविल न्यायालयों पर लागू हुआ। इसने लगभग 1865 के अधिनियम के समान ही न्यायालयों के पाँच ग्रेडों का पुनर्गठन किया, अर्थात (1) तहसीलदार, (2) सहायक या अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (3) लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर या दिवानी/सिविल जज, (4) आयुक्त, और (5) न्यायिक आयुक्त। गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को प्रत्येक ग्रेड के न्यायालयों की संख्या निर्धारित करने और समय-समय पर बदलने का अधिकार दिया गया था। किसी भी जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी न्यायालयों पर सामान्य नियंत्रण उपायुक्त में निहित होगा, तथा किसी भी संभाग में प्रथम तीन श्रेणी के न्यायालयों पर नियंत्रण न्यायिक आयुक्त के अधीक्षण के अधीन आयुक्त में निहित होगा। डिप्टी कमिश्नर का न्यायालय किसी भी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान दिवानी/सिविल न्यायालय था और वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायालयों में होने वाले कार्यों को ऐसे न्यायालयों में वितरित करने का निर्देश दे सकता था जिन्हें वह उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उचित समझता था। वह उन न्यायालयों से अपील स्वीकार करता था सिवाय तब जब विवाद की राशि 1,000 रूपये से अधिक हो, ऐसी स्थिति में अपील आयुक्त के पास होती थी। डिप्टी कमिश्नर से आयुक्त और न्यायिक आयुक्त से न्यायिक आयुक्त के पास भी अपील की जा सकती थी, जिसे ऐसे मामलों को संदर्भित करने का अधिकार था, जिसमें उसे कोई संदेह हो, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय को, जिस न्यायाधिकरण को इस प्रकार संदर्भित मामले से निपटने का निर्देश दिया गया था मानो वह उसी न्यायालय में शुरू की गई अपील हो।

अवध में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों की तर्ज पर 1879 के अधिनियम XIII द्वारा दिवानी/सिविल न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसे 1891 के अधिनियम XVI द्वारा संशोधित करके अवध में दिवानी/सिविल न्यायालयों के निम्नलिखित ग्रेड स्थापित किए गए; अर्थात, (1) न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, (2) जिला न्यायाधीश का न्यायालय, (3) अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, और (4) मुंसिफ का न्यायालय। अवध न्यायालय अधिनियम, IV, 1925 ने अवध में एक और न्यायालय बनाया, जिसका नाम अतिरिक्त न्यायाधीश था और 'अधीनस्थ न्यायाधीश' का पदनाम बदलकर 'दिवानी/सिविल न्यायाधीश' कर दिया। पदनाम में यह परिवर्तन 1936 में तत्कालीन आगरा प्रांत में हुआ था। उसी अधिनियम के तहत, अवध के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को एक मुख्य न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे अंततः 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ मिला दिया गया था। बंगाल, आगरा और असम दिवानी/सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 को उस वर्ष के यू.पी. अधिनियम संख्या II द्वारा 1956 में अवध तक विस्तारित किया गया था; और इसके बाद अवध न्यायालय अधिनियम, 1925 द्वारा गठित अवध के सभी दिवानी/सिविल न्यायालय और उन्हें प्रदत्त शक्तियां क्रमशः 1887 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित और प्रदत्त मानी गईं।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इतिहास

द्वारा श्री सत्येन्द्र नाथ वर्मा अधिवक्ता
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इतिहास पर नजर डालने पर कोई भी उस विस्मय और सम्मान से प्रभावित हो सकता है जो इसके महान और प्रतिष्ठित सदस्यों ने प्रेरित किया और अपने उदाहरणों से ऐसा करना जारी रखा। यह उन दिग्गजों का गौरवशाली इतिहास रहा है जो महज महान और प्रतिष्ठित वकील होने से संतुष्ट नहीं थे बल्कि जो एक विदेशी सरकार से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष जैसे मानवीय गतिविधियों के बहुत महान क्षेत्रों में बहुत आगे निकल गए। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है कि अतीत हमेशा दूर से अधिक चमकदार दिखाई देता है, बल्कि इसलिए कि हमारे बार के कुछ अधिक प्रतिष्ठित सदस्यों के योगदान राष्ट्रीय इतिहास का विषय बन गए हैं। पंडित अजुधिया नाथ, सर सुंदर लाल, पंडित मोती लाल नेहरू, पंडित के नामों का उल्लेख किए बिना देश के सार्वजनिक जीवन और प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तियों, शिक्षाविदों और राजनेताओं के किसी भी रिकॉर्ड की कल्पना करना मुश्किल होगा। मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉ. सतीश चंद्र बनर्जी, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सभी इस न्यायालय के बार से संबंधित थे। उपरोक्त केवल बार के हमारे उन प्रतिष्ठित सदस्यों की सूची है, जिनकी गतिविधियाँ कानून के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी चमके, और अपने तरीके से, इस राष्ट्र के इतिहास को आकार देने में सहायक रहे और जो अब हमारे बीच नहीं हैं। इसलिए, मैं इस बात पर गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता कि मैं न केवल उस पेशे से संबंधित हूँ जिसे लॉर्ड साइमन ने "दुनिया का सबसे बड़ा पेशा" कहा है, बल्कि मैं उस संघ का सदस्य हूँ जिससे ये महान वकील जुड़े थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का जन्म (एक अलग नाम के तहत) लगभग एक सदी पहले हुआ था, और अगर कोई इसकी जीवनी लिखने और विषय को न्याय देने का प्रयास करे तो यह कई खंडों को कवर करेगा। इसलिए, मैं विषय की केवल क्षणभंगुर झलकियाँ प्रदान करने का प्रयास करूँगा।

वर्ष 1869 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने वाला उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गया। उस समय बार में अंग्रेजी और आयरिश बार के बैरिस्टर, स्कॉटलैंड के अधिवक्ता और उच्च न्यायालय द्वारा नामांकित वकील शामिल थे। श्री सैयद एम. महमूद को छोड़कर यहाँ अभ्यास करने वाले बाकी बैरिस्टर यूरोपीयन थे, जो एक से अधिक कारणों से वकीलों से अलग रहना पसंद करते थे। वकील भी उन बैरिस्टरों से सामाजिक या अन्य रूप से घुलने-मिलने के लिए उत्सुक नहीं थे।

वर्ष 1873 में बैरिस्टरों ने एक संघ बनाने का फैसला किया और 3 फरवरी, 1873 को उन्होंने एक संघ बनाया, जिसे बार एसोसिएशन कहा गया, जिसके पहले सदस्य 12 यूरोपीयन बैरिस्टर थे और श्री जार्डाइन इसके पहले अध्यक्ष बने। एसोसिएशन का उद्देश्य प्रांत में बार के हितों से जुड़े मामलों पर विचार करना और विशेष रूप से कानूनी पेशे की सभी शाखाओं में उच्च पेशेवर लहजे को बढ़ावा देना और गैर-पेशेवर प्रथाओं को दबाना था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बहुत प्रतिष्ठित यूरोपीयन बैरिस्टर हुए हैं, जैसे सर आर्थर स्ट्रेची (जो बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 1899 में इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इलाहाबाद लौट आए), सर वाल्टर कॉल्विन और डिलन्स (पिता और पुत्र), कॉनलन, एलस्टन और ओ'कॉनर। हालांकि, श्री ओ'कॉनर के अपवाद के साथ, बैरिस्टर ज्यादातर आपराधिक पक्ष में ही फले-फूले। सर चार्ल्स रॉस एलस्टन इस न्यायालय के आपराधिक पक्ष के सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली वकीलों में से एक थे। सर चार्ल्स 1885 में उच्च न्यायालय में शामिल हुए और 1937 में अपनी

मृत्यु तक लगभग 53 वर्षों तक वकालत की। वह एक निडर वकील थे और जटिल से जटिल मामलों को अद्भुत संक्षिप्तता और स्पष्टता के साथ रखते थे। 1910 में उन्हें कुछ समय के लिए बेंच में पदोन्नत किया गया था वह न केवल बार के हर वर्ग में बहुत सम्मानित और लोकप्रिय थे, बल्कि उनका स्वभाव भी खुशमिजाज था और उनमें हास्य की गहरी समझ थी। सर चार्ल्स का कद बहुत छोटा था। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक जज, जो बहुत लंबा और तगड़ा था, ने सर चार्ल्स से एक निश्चित पार्टी में कहा कि वह उसे अपनी जेब में रख सकता है। सर चार्ल्स ने बिना देर किए कहा; "फिर आपके सिर में और भी दिमाग होंगे"। सर चार्ल्स कई वर्षों तक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।

श्री बी.ई.ओ.कॉनर, विशेष रूप से सिविल पक्ष में प्रैक्टिस करते थे और बार के नेताओं में से एक थे। उनके पास प्रसिद्ध प्रथम अपील कि बड़ी वक़ालत थी, और श्री ओ'कॉनर और सर तेज बहादुर सप्रू दोनों ने दशकों तक सिविल पक्ष में बार का नेतृत्व साझा किया। वे 1893 में हाई कोर्ट आए और 1937 तक प्रैक्टिस करते रहे जब उनकी मृत्य हुई। श्री ओ'कॉनर 1900 में बार एसोसिएशन के सचिव चुने गए और लगभग एक साल के अंतराल के साथ 1936 तक इस पद पर बने रहे। सचिव के रूप में उनके कार्यकाल की अवधि उनके साथी सदस्यों के उनके प्रति स्नेह और सम्मान को दर्शाती है। यह इस मिथक को भी दूर करता है कि व्यस्त वकीलों के पास अतिरिक्त-पेशेवर मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं हो सकता है।

सबसे पहले, जो विषय बैरिस्टरों के मन में उनके संघ के गठन के आरंभ से ही उद्वेलित करते रहे, वे थे बाहरी मामलों के लिए तथा इलाहाबाद के जिला न्यायालयों में उपस्थित होने के लिए ली जाने वाली फीस का मानक तथा "दलालों" की प्रथा को रोकने का प्रश्न। बार संघ की स्थापना के दो वर्ष पश्चात उच्च न्यायालय के वकीलों ने अपना स्वयं का संघ बनाने का निर्णय लिया तथा 1875 में वकीलों का संघ स्थापित किया गया। इस संघ के गठन के उद्देश्य थे, "(क) उत्तर पश्चिमी प्रांतों में कानूनी पेशे के हित को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करना तथा विशेष रूप से वकीलों के हित को प्रभावित करना, (ख) पेशे के सदस्यों में उच्च पेशेवर लहजे को बढ़ावा देना तथा (ग) कानून की स्थिति तथा विधान की प्रगति पर नजर रखना तथा उसके संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाना।" वकीलों के संघ के प्रथम अध्यक्ष पंडित अयोध्या नाथ थे, जिन्होंने बार में बहुत उच्च पद प्राप्त किया था। वे एक निर्भीक वकील थे तथा उन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन में बहुत योगदान दिया। पंडित अयोध्या नाथ ने कानून के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अजोधिया नाथ एक आदरणीय व्यक्ति थे और लंबी दाढ़ी के साथ राजसी दिखते थे।"1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष, जहाँ उनके प्रभावशाली भाषण की बहुत सराहना की गई थी। सौभाग्य से आज हमारे बीच उनके पुत्र पं. गोपी नाथ कुंजरू हैं, जो हमारे बार के नेताओं में से एक हैं, जिनकी निडरता के लिए हम सभी प्रशंसा करते हैं।

हाल ही तक बैरिस्टरों-विशेष रूप से यूरोपीयन बैरिस्टरों और इस न्यायालय के वकीलों के बीच एक पारंपरिक, लेकिन स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता थी। एक ही उच्च न्यायालय के बार में दो एसोसिएशनों के अस्तित्व के कारण यह खाई स्वाभाविक रूप से और चौड़ी हो गई। यूरोपीयन बैरिस्टरों ने अपनी जाति और इस तथ्य के कारण कि अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, "देशी वकीलों" (जिस शब्द का वे अक्सर अपनी कार्यवाही में उपयोग करते थे) के प्रति एक जटिलता विकसित कर ली थी। वे हमेशा खुद को वकीलों से श्रेष्ठ मानते थे, और भी अधिक इसलिए क्योंकि उस समय के नियमों के तहत सबसे कनिष्ठ बैरिस्टर को किसी भी वकील के विरुद्ध वरिष्ठता और पूर्व-श्रोता के अधिकार का दावा करने का अधिकार था, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो। वकीलों ने सोचा कि बैरिस्टरों के बीच यह जटिलता सिविल पक्ष में वकीलों की बड़ी प्रैक्टिस से उत्पन्न हुई थी, जिसमें बैरिस्टरों को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा गया था और कुछ उत्कृष्ट वकीलों की श्रेष्ठ बुद्धि और सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति उनका स्वतंत्र दृष्टिकोण और रवैया था। हालाँकि, तथ्य यह रहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार का नेतृत्व हमेशा वकीलों (बाद में अधिवक्ताओं) के पास रहा, उदाहरण के लिए, सर सुंदर लाल, श्री जोगेंद्र नाथ चौधरी, पंडित मोती लाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, डॉ. सतीश चंद्र बनर्जी, श्री प्यारे लाल बनर्जी, डॉ. कैलाश नाथ काटजू, पंडित श्याम कृष्ण

दार, डॉ. नारायण प्रसाद अस्थाना, पंडित गोपाल स्वरूप पाठक और पंडित कन्हैया लाल मिश्रा (हमारे वर्तमान महाधिवक्ता)। मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल रहा हूँ कि हमारे पास बार के नेताओं के रूप में प्रतिष्ठित बैरिस्टर भी रहे हैं, जैसे जी. मेसर्स राइट्स, ओ'कॉनर, बॉयज़, एलस्टन, डिलन, कॉल्विन, कोनलन और सुलेमान।

यह 1896 की बात है, जब हाईकोर्ट की स्थापना के लगभग तीस साल बाद, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी वकील को एडवोकेट का दर्जा दे सकते हैं, अगर उनकी राय में वकील में असाधारण योग्यता और गुण है। एम. राम प्रसाद, श्री जे. एन. चौधरी, पं. सुंदर लाल और पं. मोती लाल नेहरू को 1896 में वकीलों के पहले समूह के रूप में एडवोकेट का दर्जा दिया गया था।

यद्यपि इन चार वकीलों को एडवोकेट का दर्जा दिया गया था, उन्होंने बार एसोसिएशन में शामिल होने से इनकार कर दिया और वकील एसोसिएशन के सदस्य बने रहे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बार एसोसिएशन पर यूरोपीयन लोगों का प्रभुत्व था और वकील उनके प्रभुत्व में रहने के मूड में नहीं थे।

यद्यपि वकीलों और बैरिस्टरों के बीच छोटे-मोटे मुद्दों पर मतभेद होते थे, अक्सर पूर्व-श्रोता के अधिकार के सवाल पर, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, सिवाय एक बार के। जब वकीलों के पहले बैच को एडवोकेट का दर्जा दिया गया, तो यह सवाल उठा कि क्या वे वही गाउन पहन सकते हैं जो इंग्लैंड के बैरिस्टर पहनते हैं। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस आपत्ति के उठाए जाने पर, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर जॉन एज ने फैसला किया कि वकील-एडवोकेट वही गाउन पहनेंगे जो मुख्य न्यायाधीश खुद पहनते थे, यानी क्यू.सी. का गाउन और तब से वकील-एडवोकेट वही गाउन पहनते आ रहे हैं जो न्यायाधीश पहनते हैं, हाल ही में जब नियम बदले गए और बैरिस्टर और एडवोकेट दोनों को एक ही गाउन पहनना पड़ा।

यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 1957 तक जब उनका विलय हुआ, तब तक दोनों एसोसिएशन उच्च न्यायालय भवन के विभिन्न भागों में स्थित थे, जो संयोग से एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। 1929 के बाद से ही दोनों संघों को एकीकृत करने के कई प्रयास किये गये, लेकिन किसी न किसी कारण से 1957 से पहले एकीकरण नहीं हो सका।

जिन उद्देश्यों के लिए इन दोनों संघों का गठन किया गया था, उन्हें काफी हद तक प्राप्त किया जा सकता है। दोनों संघों के अभिलेखों से पता चलता है कि वे पेशे के हितों की कितनी ईमानदारी और सतर्कता से रक्षा कर रहे हैं। अभिलेखों में पिछले 93 वर्षों के दौरान पारित प्रस्तावों की भरमार है, जो सामान्य रूप से पेशे के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से इसके सदस्यों के आचरण को छूते हः संघ ने हमेशा निरंतर निगरानी रखी है और जब भी इसे नागरिक स्वतंत्रता पर कोई अतिक्रमण दिखाई दिया, इसने सबसे कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराते हुए तुरंत कार्रवाई की। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि दोनों संघों ने बार के सदस्यों द्वारा पेशेवर आचरण की उच्च संहिता को बनाए रखने और उसे बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और इस संबंध में, अगर बार का कोई महत्वपूर्ण सदस्य भी दोषी पाया जाता है, तो उसे बख्शा नहीं जाता था। उन दिनों बार के सदस्य से जिस उच्च पेशेवर नैतिकता की अपेक्षा की जाती थी, वह निम्नलिखित घटना से स्पष्ट होती है। हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील मिस्टर एक्स ने अपना दफ्तर एक इलाके से दूसरे इलाके में बदल लिया और इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले एक जर्नल में निम्नलिखित नोटिस प्रकाशित कराया:

नोटिस:

नीचे हस्ताक्षरकर्ता अपने मुवक्किलों को सूचित करता है कि उसने अपना दफ्तर कीडगंज से हटाकर चौक, मोहल्ला मीरगंज, यानी कोठी फलां के नाम से मशहूर घर में कर लिया है। इसलिए भविष्य में उसे सभी पत्र-व्यवहार उपरोक्त पते पर किए जाने चाहिए। उपस्थिति का समय सुबह 6-30 से 9-30 तक और शाम को 5 से 9 बजे तक है।

श्री. **x-** वकील,
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

इस नोटिस ने एसोसिएशन की सतर्क निगाह को तुरंत आकर्षित किया जिसने सदस्य से

स्पष्टीकरण मांगा क्योंकि एसोसिएशन के अनुसार यह नोटिस विज्ञापन के बराबर था। वकील ने अपना स्पष्टीकरण दिया, जो, हालांकि, एसोसिएशन को संतुष्ट करने में विफल रहा। तदनुसार सदस्य के आचरण की गैर-पेशेवर के रूप में निंदा की गई और उसे एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया और मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया। ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जहां एसोसिएशन ने उन सदस्यों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जिनके आचरण ने पेशे के अच्छे नाम को खराब किया।

वकीलों का संघ एक अच्छी तरह से संगठित निकाय था और यह 1927 में एक घटना के संबंध में प्रदर्शित हुआ जो एसोसिएशन के इतिहास में अद्वितीय होगा। सर तेज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।एसोसिएशन और पंडित श्याम किशन दार (बाद में इस न्यायालय के एक न्यायाधीश) इसके सचिव थे, न्यायमूर्ति दलाल और न्यायमूर्ति पुल्लन, दोनों भारतीय सिविल सेवा के सदस्य, ने आदेश ग्स्प्, नियम प्प्, सी.पी.सी. के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन किया। वे घर पर मामलों के कागजात पढ़ते थे। अगले दिन जब मामलों को लिया जाता था तो वे तर्कों को उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं तक ही सीमित रखते थे और वकील को अपने तर्क बनाने का मौका नहीं देते थे। परिणामस्वरूप मामले को ठीक से पेश नहीं किया जा सका। इससे वकीलों में काफी नाराजगी हुई और सर तेज बहादुर सप्रू ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एसोसिएशन की एक बैठक बुलाई क्योंकि उनकी राय में, अपील की सुनवाई का यह तरीका न्याय प्रशासन में वादी जनता के विश्वास को हिला सकता है। इसके बाद एसोसिएशन ने निम्नलिखित शब्दों में एक प्रस्ताव पारित किया: "यह निर्णय लिया गया कि सचिव द्वारा श्री न्यायमूर्ति दलाल और श्री न्यायमूर्ति पुल्लन को एक विनम्र लेकिन दृढ़ पत्र भेजा जाए, जिसमें न्यायालय में मामलों की सुनवाई करते समय उनकी अधीरता के प्रति सामान्य असंतोष को दर्शाया जाए। पत्र सचिव द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।" तदनुसार, एसोसिएशन के सचिव पंडित एस. के. डार के हस्ताक्षर से दोनों विद्वान न्यायाधीशों को एक पत्र भेजा गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सर सेसिल वाल्श की राय थी कि श्री डार अवमानना के दोषी हैं, उन्होंने श्री डार को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगने को कहा और श्री डार द्वारा यह बताए जाने पर कि उन्होंने एसोसिएशन के सचिव के रूप में केवल प्रस्ताव को संलग्न करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उनके व्यक्तिगत माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं था, विद्वान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने श्री डार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया। इस मामले पर वकीलों के संघ द्वारा विचार किया गया और सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में संघ के प्रत्येक सदस्य ने एक समान पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे दोनों विद्वान न्यायाधीशों को भेजा गया और इसकी प्रतिलिपि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई। इसके बाद संघ के सभी सदस्यों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किए गए कि क्यों न उन पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। चूंकि वकीलों के संघ का प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल था, इसलिए बैरिस्टरों से उनका बचाव करने का अनुरोध किया गया और श्री क्यू'कॉनर, श्री बी. मलिक (बाद में इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) और डॉ. एम. एन. अग्रवाल को वकीलों के संघ के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। मामले की सुनवाई के लिए गठित पीठ में सर सेसिल वाल्श, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और सर बेंजामिन लिंडसे शामिल थे। न्यायमूर्ति लिंडसे को जब पता चला कि मामला किस बारे में है तो उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वह खुद को हास्यास्पद बनाने से इनकार करते हैं और उस पीठ में नहीं रहना चाहेंगे। अन्य अंग्रेज न्यायाधीशों ने भी ऐसा ही रवैया अपनाया और फिर सर शाह मोहम्मद। सुलेमान से संपर्क किया गया जो मध्यस्थता के लिए 24 घंटे का समय दिए जाने की शर्त पर पीठ का सदस्य बनने के लिए सहमत हो गया। उसकी मध्यस्थता के परिणामस्वरूप सुखद अंत हुआ और कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

एक और घटना जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, वह वर्षों पहले हुई थी। प्रथम अपील पीठ के एक वरिष्ठ न्यायाधीश, जो एक अंग्रेज व्यक्ति थे, ने प्रथम अपील खुलते ही अपीलकर्ता के वकील से मामले में शामिल सटीक बिंदु पूछने का तरीका अपनाया था। विद्वान न्यायाधीश हमेशा अपील में शामिल प्रश्न को तुरंत जानने की जल्दी में रहते थे और चूंकि अधिकांश प्रथम अपीलों में तथ्यों के प्रश्न शामिल होते थे और बिंदु को सीधे और उस सटीकता के साथ तैयार नहीं किया जा सकता था जैसा कि विद्वान न्यायाधीश चाहते थे, इसलिए वकील खुद को मुश्किल में पाते थे। विद्वान न्यायाधीश जो स्वभाव से अधीर थे, उसके बाद आधे घंटे में अपील का निपटारा करना चाहते थे। वे एक दिन में बड़ी संख्या में प्रथम अपीलों का निपटारा करते थे। बार के सदस्यों ने इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और जब वकील संघ में इस मामले पर चर्चा हो रही थी तो श्री गोकुल प्रसाद (बाद में श्री न्यायमूर्ति गोकुल प्रसाद) जो बार के वरिष्ठ सदस्य थे और बड़े पैमाने पर सिविल प्रैक्टिस कर रहे थे, ने बार के एक कनिष्ठ सदस्य से पूछा कि क्या उनकी कोई प्रथम अपील सुनवाई के लिए है। उस कनिष्ठ सदस्य की उस पीठ के समक्ष प्रथम अपील थी। मुंशी गोकुल प्रसाद ने उनसे प्रथम अपील में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा। कनिष्ठ सदस्य ने मुंशी गोकुल प्रसाद से कहा कि

उनका मुवक्किल अपनी फीस नहीं दे पाएगा। मुंशी गोकुल प्रसाद ने कहा कि वह कोई फीस नहीं मांग रहे हैं। जब मामला बुलाया गया तो मुंशी गोकुल प्रसाद प्रथम अपील पर बहस करने के लिए खड़े हुए। वकील संघ के सदस्य अच्छी संख्या में अदालत कक्ष में एकत्र हुए थे। मुंशी गोकुल प्रसाद ने यह नहीं बताया था कि वह क्या करने जा रहे, मुंशी गोकुल प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय विद्वान न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे अपील के आधार वाली पेपर बुक के पहले दो पन्नों को छोड़ दें और शिकायत पत्र पढ़ना शुरू कर दिया, "न्यायालय में . . . . . फलां बनाम फलां ..."

मुंशी गोकुल प्रसाद की दलीलों के इस तरीके पर विद्वान न्यायाधीश आश्चर्यचकित थे, जो संक्षिप्त और सटीक होने के लिए जाने जाते थे। विद्वान न्यायाधीशों ने पूछा कि क्या यह सब पढ़ना जरूरी है और आगे टिप्पणी की कि मुंशी गोकुल प्रसाद आमतौर पर अपनी अपील पर इस तरह से बहस नहीं करते थे। इस दौरान विद्वान न्यायाधीशों ने अदालत में जमा भीड़ को भी देखा और यह देखते हुए कि यह कोई सनसनीखेज प्रकृति की पहली अपील नहीं थी, उन्हें कुछ असामान्य लगा। इस पर मुंशी गोकुल प्रसाद ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, "माई लॉर्ड्स, यह एक पहली अपील है जो अधिकार के तौर पर है। मुवक्किल ने भारी अदालती फीस का भुगतान किया है और उसे सुनवाई का अधिकार है। मैं आपके लॉर्डशिप को शुरू से अंत तक पेपर बुक के बारे में बताऊंगा।" तब विद्वान न्यायाधीशों को समझ में आया कि मामला क्या था और उन्होंने मुंशी गोकुल प्रसाद से अपने सामान्य तरीके से मामले को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। मुंशी गोकुल प्रसाद ने न्यायाधीशों को समझाया कि पहली अपील में अपीलकर्ताओं को वह सुनवाई देना वांछनीय है जिसके वे हकदार हैं। तब से विद्वान न्यायाधीश ने अपनी पद्धति बदल दी और कभी भी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया।

एम. राम प्रसाद, पं. बिशंभर नाथ, श्री जोगेंद्र नाथ चौधरी, पं. सुंदर लाल, पं. मोती लाल, पं. मदन मोहन मालवीय, श्री सत्य चरण मुखर्जी, डॉ. सतीश चंद्र बनर्जी, सर तेज बहादुर सप्रू और श्री प्यारे लाल बनर्जी बार के कुछ प्रतिष्ठित नेता रहे हैं जिन्होंने वकीलों के संघ (बाद में अधिवक्ता संघ) की एक या दूसरे क्षमता में विशिष्टता के साथ सेवा की है। मैंने उन लोगों के नामों का उल्लेख नहीं किया है जो सौभाग्य से अभी भी हमारे साथ हैं और जिन्होंने संघ की कम सेवा नहीं की है।

पाठकों को इस न्यायालय के महान वकीलों के जीवन के बारे में इस खंड में अलग-अलग स्थानों पर बताया गया है और उनके बारे में यहां लिखना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, मैं उनमें से कुछ के बारे में कुछ शब्द कहने का मोह नहीं छोड़ सकता।
ऐसा कहा जाता है कि श्री जोगेंद्र नाथ चौधरी इस उच्च न्यायालय के सबसे महान वकीलों में से एक थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था और कानूनी शिक्षा में उनकी बराबरी करने वाले बहुत कम लोग थे।

एक बार दो क्रॉस प्रथम अपीलें थीं और श्री जोगेंद्र नाथ चौधरी और पंडित मोती लाल नेहरू एक दूसरे के खिलाफ पेश हो रहे थे। श्री चौधरी की आदत थी कि वे जिन कागज़ों को देखते थे उन पर लाल और नीली पेंसिल से निशान लगा देते थे। प्रथम अपील का बहुत बड़ा अभ्यास होने के कारण वे इन अपीलों को नहीं देख पाए थे। हालाँकि, जिस अपील में पंडित मोती लाल नेहरू अपीलकर्ता की ओर से पेश हो रहे थे, वह पहले सूचीबद्ध थी। श्री चौधरी ने सोचा था कि जब पंडित नेहरू अपीलकर्ता के लिए बहस करेंगे, तब वे ब्रीफ देखेंगे। श्री चौधरी के अदालत में पहुंचने से पहले मोती लाल जी ने पाया कि श्री चौधरी ने ब्रीफ नहीं देखे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि श्री चौधरी के ब्रीफ पर निशान नहीं लगे थे। जब मामला सामने आया, पंडित मोती लाल खड़े हुए और श्री चौधरी को कुछ असुविधा में डालने के लिए नेहरू के मुवक्किल का अपनी अपील में बहुत मामूली दावा था। विद्वान न्यायाधीशों ने सोचा कि यह उचित सुझाव है और उन्होंने श्री चौधरी से अपनी अपील खोलने को कहा। श्री चौधरी पंडित मोती लाल के खेल को समझ गए। फिर भी, वे खड़े हुए, अपील के आधारों पर नज़र डाली और पाया कि मामला धोखाधड़ी का है। ऐसा कहा जाता है कि श्री चौधरी ने धोखाधड़ी के तत्वों पर लगभग तीन घंटे तक इतनी कुशलता से व्याख्या की कि उन्होंने पूरे न्यायालय को मंत्रमुग्ध कर दिया और जब एक बजे न्यायालय भोजन के लिए उठा तो श्री चौधरी ने अंतराल के दौरान मामले के तथ्यों पर गौर किया और उसके बाद न्यायालय के पुनः बैठने पर तथ्यों के आधार पर अपील पर बहस की।

पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते जिसने इतने सारे क्षेत्रों में इतनी लगन और त्याग की भावना के साथ काम किया हो और उनमें से प्रत्येक में महान पंडित मालवीय के समान विशिष्टता हासिल की हो। उन्हें

एक प्रखर बुद्धि वाला वकील माना जाता था, जो अपने मामले को प्रस्तुत करने में अत्यंत निष्पक्ष और अपने विरोधियों के प्रति विनम्र था। न्यायाधीश न केवल उनकी योग्यता के लिए बल्कि उनके बेदाग चरित्र के लिए भी उनका बहुत सम्मान करते थे। पं. मालवीय की अंग्रेजी पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि एक अवसर पर एक महान ब्रिटिश राजनेता ने (हाउस ऑफ कॉमन्स के एक कमरे में दर्शकों से उनका परिचय कराते हुए) आश्चर्य व्यक्त किया कि, छात्र के रूप में कभी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज न गए हुए भी पं. मालवीय के पास विदेशी भाषा में अभिव्यक्ति की ऐसी अद्भुत क्षमता कैसे हो सकती है। सक्रिय वकालत से सेवानिवृत्त होने के बाद मित्रों के अनुनय पर मालवीयजी प्रसिद्ध चौरी चौरा दंगा अपील पर बहस करने के लिए सहमत हुए। मालवीयजी को सुनने के लिए अदालत में स्वाभाविक रूप से भारी भीड़ थी। पं. मालवीय की दलीलें इतनी ऊंची उठ गईं कि मुख्य न्यायाधीश सर ग्रिमवुड मीयर्स, जो अपील की सुनवाई करने वाले दो न्यायाधीशों में से एक थे, बहस के दौरान तीन बार अपने स्थान से उठे और मालवीयजी को प्रणाम किया। बहस पूरी होने के बाद और फैसला सुरक्षित रखते समय सर ग्रिमवुड ने कार्यवाही रोक दी और न्यायालय में उपस्थित लोगों से कहा कि यद्यपि यह कहना संभव नहीं है कि अपील का क्या भाग्य होगा, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि यह उन लोगों का परम सौभाग्य था जिन्होंने इस मामले में मालवीय जी को सुना था और उनकी राय में कोई और इस अपील पर उनसे बेहतर बहस नहीं कर सकता था। कांग्रेस के अध्यक्षों में से एक के रूप में, बनारस के प्रसिद्ध हिंदू विश्वविद्यालय के अकेले संस्थापक के रूप में, केंद्रीय विधानमंडल में एक कुशल वाद-विवादकर्ता के रूप में) जिसकी कार्यवाही में उन्होंने वर्षों तक बहुत प्रमुख भाग लिया, पंडित मालवीय एक ऐसे नेता थे जिन पर न केवल इलाहाबाद बार बल्कि पूरा देश गर्व करता है।

डॉ. सतीश चंद्र बनर्जी इस न्यायालय के एक और रत्न थे। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ लॉ थे और प्रेमचंद रॉयचंद विद्वान थे। वे शेक्सपियर के बहुत उत्सुक छात्र थे और ऐसा कहा जाता है कि रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में, विश्वविद्यालय के छात्र अपनी कठिनाइयों के समाधान के लिए एडमोंस्टोन रोड पर उनके घर जाते थे। यहां तक कि भारी भरकम प्रथम अपील की तैयारी के दौरान भी वे छात्रों से स्नेहपूर्वक मिलते थे और उनकी शैक्षणिक समस्याओं में उनकी मदद करते थे। यदि वे 42 वर्ष की कम उम्र में नहीं मरे होते तो इस बार का इतिहास कुछ और होता। उन दिनों सप्रू, बनर्जी और सिन्हा (डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा) की तिकड़ी अपनी विद्वत्ता और संस्कृति के कारण विश्व भर में प्रशंसनीय थी।

श्री सत्यचरण मुखर्जी आपराधिक पक्ष के भारतीय सदस्यों में उच्च न्यायालय बार के निर्विवाद नेता थे। वे अत्यंत योग्य, अनुभवी और विद्वत्तापूर्ण वकील थे और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी।

इस उच्च न्यायालय में माननीय सर तेज बहादुर सप्रू की स्थिति अद्वितीय थी। 1898 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार में शामिल होने के बाद दृ जहाँ उन्होंने पचास वर्षों तक वकालत की, उन्हें 1906 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया, जिसे तब एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था क्योंकि इससे उन्हें अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश बार के सदस्यों के साथ समान दर्जा प्राप्त हुआ था।

लगातार दस वर्षों तक बढ़ते अभ्यास के बाद ही उन्हें अपना पहला बड़ा मौका मिला दृ हिंदू कानून के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला। सर तेज को इस मामले में उच्च न्यायालय बार के कुछ प्रतिष्ठित नेताओं के खिलाफ खड़ा किया गया था। यह मामला कुछ हफ्तों तक चला, और उन्होंने इस पर इतनी निपुणता और दुर्लभ फोरेंसिक क्षमता के साथ बहस की कि अपने संबोधन के अंत में बेंच की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश ने उनकी खुलकर प्रशंसा की। यह वह मामला था जिसने उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की और तुरंत उन्हें बार में सर्वोच्च पद के लिए चिह्नित किया। उन्होंने जल्द ही एक व्यापक और लाभदायक 'प्रथम अपील' प्रैक्टिस का निर्माण किया, और तब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला आया हो जिसमें उन्हें अपीलकर्ता या प्रतिवादी द्वारा नियुक्त न किया गया हो।

1912 तक, जब वे लखनऊ मुख्य न्यायालय में कुछ महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों में लगे हुए थे दृ 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शामिल हुए दृ उन्होंने भारतीय बार के तत्कालीन प्रमुख सर रास बिहारी घोष का सफलतापूर्वक विरोध किया, और इस तरह पूरे संयुक्त प्रांत में एक अग्रणी स्थान पर आ गए। 1916 तक जब वे एक सनसनीखेज 'वक्फ' मामले में लगे हुए थे, जिसमें एक समुदाय के रूप में मुसलमानों की गहरी दिलचस्पी थी और सर रास बिहारी ने फिर से उनका विरोध किया, तो उन्हें अखिल

भारतीय ख्याति प्राप्त बार के अग्रणी नेताओं में से एक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तब से पूरे देश में उनकी सेवाओं की निरंतर मांग होने लगी। इसके बाद वे कलकत्ता, पटना, लाहौर, नागपुर, मद्रास और अन्य स्थानों के उच्च न्यायालयों में कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुए और देश के लगभग सभी बड़े मामलों में उनका पहला इनकार था।

सर तेज कभी-कभार ही हास्य-विनोद करते थे, लेकिन जब वे ऐसा करते थे, तो इसका असर आम तौर पर विनाशकारी होता था। लंदन में एक पत्रकार ने एक बार रात में उन्हें फोन किया था, जिसे वह उतना ही पसंद करता था, जितना वह चाहता था। "हमारे भारतीय कार्यालय नेअभी-अभी केबल भेजा गया है कि आपको पीयरेज की पेशकश की गई ह" उसने उससे कहा। "इसमें क्या है"? सर तेज ने पूछा। "ठीक है, सर" उत्सुक लेकिन चिढ़ने वाले समाचारवाचक ने जोर दिया; "क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने कौन सी उपाधि चुनी है?" "निश्चित रूप से" उस कट्टर धूम्रपान करने वाले (सर तेज) ने उत्तर दिया, "यह ड्यूक ऑफ ब्लेज़ है", और रिसीवर नीचे रख दिया। यह वास्तव में अदालत में भी उसकी विशेषता थी। उसने अपना मामला लगभग वैज्ञानिक परिशुद्धता के साथ बताया। जब कोई न्यायाधीश किसी परेशान करने वाले प्रश्न से उसे उकसाता था, तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता था। पटना उच्च न्यायालय में "सर्च-लाइट" अवमानना मामले में अपने प्रस्तुतीकरण के दौरान, जब मुख्य न्यायाधीश (जिनके निर्णय के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू की गई थी) द्वारा कठोर दबाव डाला गया, तो उसने पूरी गंभीरता से निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किया "मेरे प्रभु, यह कोई अनुमान नहीं है कि एक न्यायाधीश को कानून जानने की आवश्यकता है।" उसके बाद उस बेंच के किसी भी जज को सर तेज को परेशान करने के लिए उकसाया नहीं गया।

यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि, जबकि भारत में कुछ वकील फोरेंसिक क्षमता, गहन कानूनी पांडित्य और संवैधानिक कानून के गहन ज्ञान में उनसे बेहतर थे, शायद, वर्तमान पीढ़ी में, पेशेवर मानकों की सर्वोत्तम और उच्चतम परंपराओं को बनाए रखने में उनसे बेहतर कोई नहीं था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने सामाजिक आचरण की सर्वोत्तम और उच्चतम परंपराओं को बनाए रखा। और यह वह था जिसने उन्हें एक नैतिक भव्यता प्रदान की, जिसने उनके विशाल पांडित्य के साथ मिलकर उनके नाम को इस देश और विदेश में प्यार और सम्मान दिया।

विशुद्ध फोरेंसिक वाक्पटुता में कुछ ही लोग श्री पीरी लाल बनर्जी की बराबरी कर सकते हैं। जिन लोगों को उनके पिता, अर्थात, इस न्यायालय के एक अन्य प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित वकील, श्री द्वारका नाथ बनर्जी को सुनने का सौभाग्य मिला, वे कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और भाषण श्री पीरी लाल बनर्जी से भी बेहतर था। पी.एल.बी., जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, यू.पी. के एडवोकेट-जनरल थे, जिस पद को उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा के साथ संभाला। डॉ. कैलाश नाथ काटजू के साथ उन्होंने दशकों तक बार का नेतृत्व साझा किया। उनके कई शानदार प्रदर्शनों में से एक सबसे खास था जब उन्हें पटना उच्च न्यायालय के महान पी.आर. दास का बचाव करने के लिए बुलाया गया था, जिन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ ने न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि पी.एल.बी. ने फोरेंसिक क्षमता में खुद को पार कर लिया और अवमानना के नोटिस को खारिज करवा लिया।

इलाहाबाद बार ने देश के कुछ महानतम न्यायाधीशों को जन्म दिया है और न्यायालय ने भारत के लगभग हर उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दिए हैं।

वकीलों का संघ वर्ष 1928 तक अस्तित्व में रहा। भारतीय बार काउंसिल अधिनियम, 1926 के पारित होने के बाद वकीलों के संघ ने अपना नाम बदल दिया और यह अधिवक्ता संघ बन गया। बैरिस्टर एसोसिएशन जिसे बार एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, ने किसी तरह वर्ष 1922 में बार लाइब्रेरी का नाम ले लिया।

अधिवक्ता संघ और बार लाइब्रेरी के अलावा, बार का एक तीसरा संघ भी था जिसकी सदस्य संख्या तुलनात्मक रूप से कम थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अस्तित्व में आया। भारतीय बैरिस्टर जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू करते थे और बार लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए आवेदन करते थे, तो अक्सर उन्हें ब्लैकबॉल कर दिया जाता था और दूसरे या तीसरे प्रयास में ही वे चुने जाते थे। जब बैरिस्टर श्री निहाल चंद को ब्लैकबॉल किया गया, तो उन्होंने बार लाइब्रेरी से कोई भी संबंध रखने से इनकार कर दिया। उन दिनों एक बैरिस्टर उच्च न्यायालय में छह महीने की वकालत

के बाद ही बार लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए पात्र होता था। उस अवधि के दौरान उनके पास श्री निहाल चंद के समूह में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उनमें से कुछ उस समूह में बने रहे, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं था और कोई सदस्यता शुल्क नहीं देना था। यह समूह धीरे-धीरे बढ़ता गया और 1933 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी गई और तब से इसे 'हाईकोर्ट बार एसोसिएशन' के रूप में जाना जाता है।

नवंबर 1957 में तीनों एसोसिएशनों का विलय हो गया और तब से वे नए भवन में रह रहे हैं और विलय हुए एसोसिएशनों ने इसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कहने का फैसला किया।

1957 से अब तक हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में मैं केवल तीन का उल्लेख करूंगा। 3 अक्टूबर 1960 को डॉ राजेंद्र प्रसाद एसोसिएशन आए थे, जब एसोसिएशन को उन्हें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मानद सदस्य के रूप में स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत ही यादगार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभाओं में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यताएं शुरू करने के प्रश्न पर और भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान की अनुपस्थिति पर भी बात की।

अगली महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब 4 मई 1961 को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन ने लाइब्रेरी हॉल में इस न्यायालय के तीन प्रतिष्ठित और महान वकीलों सर सुंदर लाल, पंडित मोती लाल नेहरू और सर तेज बहादुर सप्रू के चित्रों का अनावरण किया।

तीसरी महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब अप्रैल 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लाइब्रेरी हॉल में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र का अनावरण किया। श्री जवाहरलाल नेहरू बार की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1912 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शामिल हुए और लंबे समय तक बार लाइब्रेरी के सदस्य रहे।

इस बार ने देश को न केवल संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अर्थात् डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा दिए, जो 1896 में इलाहाबाद बार में शामिल हुए और 1910 तक यहां रहे जब इंपीरियल विधान परिषद में उनके चुनाव ने उन्हें कलकत्ता (भारत की तत्कालीन राजधानी) में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया, जहां वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में शामिल हुए, और देश के पहले प्रधान मंत्री, बल्कि भारत सरकार के कानून पोर्टफोलियो की देखभाल के लिए तीन प्रतिष्ठित वकील भी दिए हैं, अर्थात् सर तेज बहादुर सप्रू, जो वर्ष 1921 से 1923 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून सदस्य थे, डॉ, कैलाश नाथ काटजू, वर्ष 1951 से 1952 तक कानून मंत्री और हमारे वर्तमान कानून मंत्री, श्री गोपाल स्वरूप पाठक।

एसोसिएशन के पास एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय है, अपने सदस्यों के लिए सुसज्जित कक्ष प्रदान किए हैं, अध्ययन करने और मामलों को तैयार करने के लिए विशाल आवास और एक प्रिंटिंग प्रेसबार एसोसिएशन के इतिहास का कोई भी विवरण इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉ. नारायण प्रसाद अस्थाना का उल्लेख किए बिना अधूरा रहेगा, जो पेशे के एक दिग्गज हैं। डॉ. अस्थाना को 1949 में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था, जब सर तेज बहादुर सप्रू की मृत्यु के कारण यह पद रिक्त हो गया था, जो 25 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे थे। डॉ. अस्थाना इस प्रांत के पहले एडवोकेट जनरल थे। वे एक प्रखर वकील, प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं, जो कई बार आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, और इस प्रांत के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति हैं। डॉ. अस्थाना, जो अब 93 वर्ष के हैं, नियमित रूप से उच्च न्यायालय जाते हैं। बार एसोसिएशन उस दिन का इंतजार कर रही है जब वह न केवल अपनी शताब्दी मनाएगी बल्कि वर्ष 1974 में डॉ. अस्थाना की शताब्दी भी मनाएगी। अंत में मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि यदि मुझे हमारे कुछ सदस्यों की भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिले, जो आज भी हमारे बीच हैं और जिन्होंने न केवल कानून और न्याय प्रशासन के क्षेत्र में बल्कि देश के राजनीतिक और सामाजिक मामलों में भी अपनी भूमिका निभाई है, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक हमारे बार को और भी अधिक सम्मान के साथ देखेगा।

आपातकाल के दौरान मानवाधिकार

श्री सोली जे. सोराबजी वरिष्ठ अधिवक्ता,
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल

कुछ समय आते है जब एक राष्ट्र अप्रत्याशित रूप से और अचानक उन घटनाओं और ताकतों से घिर जाता है जो उसकी सुरक्षा और उसके नागरिकों के जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डालती हैं। ऐसी स्थितियों में राष्ट्र के सामने आने वाले खतरों से निपटने के लिए नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अस्थायी रूप से निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है। आपातकालीन स्थितियां लोकतांत्रिक सरकारों को एक वास्तविक दुविधा में डाल देती हैं, जिससे राज्य की अखंडता की रक्षा करने के अपने प्राथमिक दायित्व और अपने नागरिकों और अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के अपने समान रूप से महत्वपूर्ण दायित्व के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। राज्य को प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच और एक के लिए दूसरे के त्याग के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाता है। यही आपातकालीन प्रावधानों का तर्क है, जो कई राष्ट्रीय संविधानों में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देते हैं।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 358 के तहत, आपातकाल की घोषणा पर, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसके अलावा, मूल रूप से अधिनियमित संविधान का अनुच्छेद 359, यह प्रावधान करता है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तो राष्ट्रपति के आदेश जारी करके किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है।

मानवाधिकारों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपकरण भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ECHR) का अनुच्छेद 15 अनुबंधित राज्यों को युद्ध या राष्ट्र के जीवन को खतरे में डालने वाली अन्य सार्वजनिक आपात स्थितियों के समय गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता के संबंध में सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों से विचलित होने के लिए उपाय करने की अनुमति देता है। 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का अनुच्छेद 4 सार्वजनिक आपातकाल के समय सरकार द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है, जो राष्ट्र के जीवन को खतरे में डालता है। 1969 के अमेरिकी मानवाधिकार सम्मेलन (ACHR) में भी एक समान प्रावधान, अनुच्छेद 27 है, जो युद्ध, सार्वजनिक खतरे या किसी अन्य आपातकाल के समय सम्मेलन द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों के निलंबन को सशक्त बनाता है जो एक राज्य पार्टी की स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरे में डालता है।

साथ ही, यह भी माना जाता है कि कुछ बुनियादी मानवाधिकार हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे वह युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह या नागरिक विद्रोह। ये अधिकार इतने बुनियादी हैं कि उन्हें निलंबित करने से एक सभ्य राज्य और कानून के शासन का आधार नष्ट हो जाता है। वास्तव में, वे मानव व्यक्तित्व के लिए इतने मौलिक हैं कि उनके बिना, मानव जीवन या तो संभव नहीं है (जैसे जीवन के अधिकार की सुरक्षा) या सभ्य जीवन असंभव और अर्थहीन हो जाता है (जैसे यातना और क्रूर व्यवहार से मुक्ति, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार)। ये अधिकार आवश्यक मानवीय मूल्यों के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सोच और हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बीच समानता है कि संविधान की कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं, जो इसके मूल या बुनियादी ढांचे से असंशोधनीय हैं।

इसके अलावा, कुछ अधिकारों का आपातकाल के उद्देश्य से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है, इस अर्थ में कि उनका निलंबन आपातकाल के उद्देश्य की उपलब्धि को सुविधाजनक या उन्नत नहीं करता है, और इसलिए, उनका निलंबन अनावश्यक है। उदाहरण के लिए, युद्ध के प्रभावी अभियोजन या सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए, संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता

के लिए कारावास से प्रतिरक्षा की गारंटी को निलंबित करना आवश्यक नहीं है।

वर्ष 1949 में, यह सिद्धांत कि कुछ बुनियादी मानवाधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, मानवाधिक. ार उपकरणों में स्पष्ट नहीं किया गया था। फिर भी, हमारे कुछ संस्थापकों ने आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित संविधान सभा में बहसों में यही बात कही थी। प्रारुप अनुच्छेद 280, जो भारतीय संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 359 के अनुरूप है, जो राष्ट्रपति को सभी या किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश जारी करने का अधिकार देता है, की कड़ी आलोचना हुई।
संविधान सभा के स्टार्मी पेट्रेल एच.वी. कामथ ने आग्रह किया कि कुछ गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि सबसे गंभीर आपातकाल की स्थिति में भी नहीं। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले प्रावधान का उदाहरण दिया और पूछा । क्या आपका मतलब यह है कि जब आपातकाल होता है तो हम इन वर्जनाओं के पालन की अनुमति दे सकते हैं और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो किसी भी रूप में किसी और पर अस्पृश्यता लागू करते हैं? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का उल्लेख करने के बाद, उन्होंने जोरदार ढंग से कहा कि कुछ अधिकार हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल की स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो। (जोर दिया गया) शिब्बन लाल सक्सेना ने इस दृष्टिकोण का जोरदार समर्थन किया: इस अध्याय में कुछ अनुच्छेद हैं जिनका आपातकाल से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें निलंबित क्यों किया जाना चाहिए? यदि यह अनुच्छेद लागू होता है, तो भेदभाव भी किया जा सकता है। और यह मौलिक अधिकारों की भावना के विरुद्ध होगा।

पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने इस आशय का एक संशोधन पेश किया कि प्रारुप संविधान में केवल कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि, जब राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी की गई हो, तो सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए। (जोर दिया गया) आर. के. सिधवा ने संशोधन का समर्थन किया और तर्क दिया । बेगार (बलपूर्वक श्रम) के संबंध में एक खंड है। क्या आप चाहते हैं कि आपातकाल में बेगार जारी रहे? अनुच्छेद 18 कहता है कि पंद्रह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को खानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि यह आपातकाल है, तो क्या आप चाहते हैं कि चौदह वर्ष का बच्चा खान में जाकर काम करे? और फिर धर्म, शिक्षा आदि से संबंधित अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 19 है।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार के निलंबन को सक्षम करने वाले अनुच्छेद पर महावीर त्यागी की आपत्ति प्रभावी और स्पष्ट थी: भले ही पूरा सदन सरकार को आपातकाल की स्थिति में भी ऐसे अधिकार देने के लिए सहमत हो जाए, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध करता हूं, अभी और हमेशा। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के न्यायपालिका में जाने के अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाना चाहिए। वह लगभग भविष्यवक्ता थे । यदि इस हानिकारक अनुच्छेद को संविधान में आने दिया गया तो कई समृद्ध और मूल्यवान जीवन, कई विद्वानों और देशभक्तों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे।

दुर्भाग्य से, ये दूरदर्शी दलीलें प्रबल नहीं हुईं। आपातकालीन प्रावधानों का समर्थन करते हुए अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने यह स्वीकार करते हुए उन्हें चतुराई से कुंद कर दिया कि ऐसे अधिकार हैं जिन्हें युद्ध की अवधि के दौरान निलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा और नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष खंडों को अलग करने के बजाय, यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है, जिनके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे उचित और सही तरीके से कार्य करेंगे, संविधान में नागरिकों को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के खिलाफ बर्बरता की भावना से नहीं।

बाद की घटनाओं ने दुखद रूप से अल्लादी और अन्य संस्थापक नेताओं की आशाओं और आश्वासनों को झूठा साबित कर दिया, जिन्होंने आपातकालीन प्रावधानों का समर्थन किया था। 1949 में जिन चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया था, वे 26 जून

1975 को उस समय दर्दनाक रूप से सच साबित हुई, जब आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा होने के बहाने आपातकाल की घोषणा की गई।

सबसे बड़ा झटका अप्रत्याशित रूप से सर्वोच्च न्यायालय से आया। 28 अप्रैल 1976 को दिए गए ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के अपने फैसले में, न्यायालय ने 4 से 1 के बहुमत से, न्यायमूर्ति खन्ना के असहमति के साथ, फैसला सुनाया कि एक बार अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर देता है, तो एक व्यक्ति जिसे हिरासत आदेश द्वारा अपनी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, भले ही वह दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया हो, निवारण के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता है।
25 जनवरी 1977 को भारत संघ बनाम भानुदास में दिए गए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय और भी आगे बढ़ गया। इसने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाले आदेश की वैधता में किसी भी और हर न्यायिक जांच और जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं और न्यायालय को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके हिरासत के स्थान से उसके घर या परीक्षा हॉल में ले जाने या उसकी पसंद के डॉक्टर के तहत विशेष चिकित्सा उपचार या किसी अन्य सुविधा के लिए सुविधाएं देने के रूप में राहत देने से भी वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह न्यायालय की सहायता से मौलिक अधिकार को लागू करना होगा।

इन दो विनाशकारी फैसलों का परिणाम यह हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को वास्तव में निलंबित कर दिया गया, और कानून के शासन को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मनमानी हिरासतें बढ़ीं, जेल में हिरासत में लिए गए लोगों की स्थिति और उपचार बिगड़ गया, और कई मामलों में कार्यपालिका अपने आप में एक विधि बन गई।

जून 1975 के आपातकाल के कड़वे अनुभव के आलोक में, संविधान (चौवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 पारित किया गया। आपातकालीन प्रावधानों में कई लाभकारी परिवर्तन किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 359 में किया गया संशोधन था, जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों, दोहरे खतरे और आत्म-अपराध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारत ICCPR का एक पक्षकार है, जिसमें इसने जुलाई 1979 में परिग्रहण और अनुसमर्थन किया था। अनुच्छेद 4(2) में ICCPR (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि) के सात प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनसे कोई भी अपवाद की अनुमति नहीं है। ये हैं । अनुच्छेद 6 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 7 (यातना का निषेध), अनुच्छेद 8, पैराग्राफ 1 और 2 (दासता और दासता का निषेध), अनुच्छेद 11 (संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के लिए कारावास का निषेध), अनुच्छेद 11 (पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों और दंडों के खिलाफ निषेध), अनुच्छेद 16 (कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार), अनुच्छेद 18 (विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता)।

ICCPR के तहत एक पक्षकार-राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने कानूनों को अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप लाए। यह खेदजनक है कि आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों के गैर-निलंबन के मामले में, ICCPR के तहत सभी गैर-अपमानजनक अधिकारों को हमारे संविधान में गैर-निलंबित नहीं किया गया है। यह और भी खेदजनक है कि भारत के अटॉर्नी जनरल जी. रामास्वामी ने 1991 में ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के दौरान गलत तरीके से दावा किया कि भारत के कानून और संविधान पूरी तरह से ICCPR के अनुरूप हैं।

वर्तमान में ग्यारह अधिकार हैं, जिन्हें गैर-अपमानजनक, यानी गैर-निलंबित, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में मान्यता प्राप्त है।

i, जीवन का अधिकारः ICCPR: अनुच्छेद 6; ECHR: अनुच्छेद 2; ACHR: अनुच्छेद 4
ii, यातना का निषेधः ICCPR: अनुच्छेद 7; ECHR: अनुच्छेद 3; ACHR: अनुच्छेद 5
iii, दासता या दासत्व का निषेधः ICCPR: अनुच्छेद 8; ECHR: अनुच्छेद 4; ACHR: अनुच्छेद 6
iv, पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों का निषेधः ICCPR: अनुच्छेद 15; ECHR: अनुच्छेद 7; ACHR: अनुच्छेद 9
v, कानूनी व्यक्तित्व की मान्यता का अधिकारः ICCPR: अनुच्छेद 16; ACHR: अनुच्छेद 3
vi, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रताः ICCPR: अनुच्छेद 18; ACHR: अनुच्छेद 12
vii, संविदात्मक दायित्व के उल्लंघन के लिए कारावास का निषेधः ICCPR: अनुच्छेद 11
viii, परिवार के अधिकारः ACHR: अनुच्छेद 17
ix, बच्चे के अधिकारः ACHR: अनुच्छेद 19
x, राष्ट्रीयता का अधिकारः ACHR: अनुच्छेद 20
xi, सरकार में भागीदारी का अधिकारः ACHR: अनुच्छेद 23

इन दस्तावेजों में भेदभाव को उन्हीं प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, जो मानवाधिकारों के निलंबन की अनुमति देते हैं। चाहे वह स्पष्ट रूप से हो, जैसे ICCPR अनुच्छेद 4(1) और ACHR अनुच्छेद 27(1), या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अन्य दायित्वों के अनुपालन की आवश्यक परिणति के रूप में, जैसे ECHR अनुच्छेद 15(1)।
अपवाद की स्थिति में मानवाधिकार मानदंडों के न्यूनतम मानक लोकप्रिय रूप से चौधरी रिपोर्ट के रूप में जाने जाते हैं और पेरिस न्यूनतम मानकों के रूप में संदर्भित होते हैं, सोलह गैर-निलंबित अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं। वे हैं: कानूनी व्यक्तित्व का अधिकार; दासता और दासत्व से मुक्ति; भेदभाव से मुक्ति; जीवन का अधिकार; स्वतंत्रता का अधिकार; यातना और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्ति; निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार; विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता; संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असमर्थता के लिए कारावास से मुक्ति; अल्पसंख्यकों के अधिकार; परिवार के अधिकार; नाम का अधिकार; बच्चे का अधिकार; राष्ट्रीयता का अधिकार; सरकार में भाग लेने का अधिकार और न्यायिक उपचार का अधिकार।

पेरिस न्यूनतम मानक गैर-अपमानजनक अधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करते हैं। युद्ध और आपात स्थितियों के समय, कुछ अल्पसंख्यक हमले के विशेष लक्ष्य बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि सभ्यता का आकलन अल्पसंख्यकों के साथ किए गए व्यवहार से होता है। आपातकाल के दौरान अल्पसंख्यकों को दी गई सुरक्षा एक लाभकारी प्रगति है। हालांकि, अल्पसंख्यकों की अवधारणा को केवल भाषाई, जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समाज के सभी गैर-प्रमुख वर्गों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक होना चाहिए, जो अपनी विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति के कारण भेदभाव और अक्षमताओं के अधीन हैं।

क्या आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता भी गैर-निलंबित होनी चाहिए? 22 से 27 अगस्त 1982 को इंटर-अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा सैन जोस, कोस्टारिका में आयोजित एक बैठक में लैटिन अमेरिकी संवैधानिक विद्वानों के एक समूह की आम सहमति का प्रतिनिधित्व करने वाले सुझावों में से एक यह था कि, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो भी अन्य प्रतिबंध लगाए जाएं, मानवाधिकार उल्लंघनों की निंदा करने की स्वतंत्रता को संरक्षित करना आवश्यक था।

इस दृष्टिकोण में तर्क संगतता है। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपातकाल के दौरान वैध रूप से अधिक प्रतिबंधों के अधीन हो सकती है। लेकिन एक विशेष मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के बीच, जो स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर अपनी डिग्री और सीमा में भिन्न हो सकता है, और दूसरी ओर, इसके निलंबन या निरसन के

बीच गुणात्मक अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के देखे गए खतरों को प्रतिबंधों को लागू करके दूर किया जा सकता है, जो आपातकाल के दौरान सामान्य समय की तुलना में संवैधानिक रूप से अधिक कठोर हो सकते हैं।

उपचार के बिना अधिकार व्यर्थ हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायिक उपायों का अधिकार और विशेष रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत होनी चाहिए बल्कि आपातकाल के दौरान स्पष्ट रूप से गैर-निलंबित भी होनी चाहिए। महान याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अपार मूल्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और आपातकाल के दौरान इसकी उपलब्धता अपरिहार्य है। यह सक्षम न्यायालय द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि हिरासत कानूनी और वैध है या नहीं। यह न्यायालय के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की प्रस्तुति को भी सक्षम करेगा, जो यातना, अपमानजनक और अमानवीय व्यवहार और अन्य शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारों को रोकने में बहुत मददगार होगा, जिनके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को आमतौर पर अधीन किया जाता है। यदि प्रस्तुति स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है, तो सरकार को किसी भी स्थिति में न्यायालय को हिरासत के स्थान के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य होना चाहिए। न्यायालय को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की चिकित्सा जांच के साथ-साथ न्यायालय द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जेल या हिरासत के स्थान के निरीक्षण के लिए निर्देश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बंदी के परिवार के सदस्यों द्वारा नियमित मुलाकातें और कानूनी सलाहकारों के साथ साक्षात्कार, समय और स्थान के संबंध में उचित नियमों के अधीन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के सदस्यों द्वारा दौरे मददगार होंगे और बंदियों के अमानवीय व्यवहार के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेंगे।

सभी मानवाधिकार उपकरणों में ACHR इस संबंध में अद्वितीय है क्योंकि यह उन अधिकारों में न्यायिक गारंटी को शामिल करने वाला पहला उपकरण है जिन्हें गैर-निलंबित अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ACHR का अनुच्छेद 7 (1) प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 7 (6) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जिस किसी को भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, उसे सक्षम अदालत में जाने का अधिकार होगा ताकि अदालत उसकी गिरफ्तारी या हिरासत की वैधता पर बिना देरी के निर्णय ले सके और यदि गिरफ्तारी या हिरासत गैरकानूनी है तो उसकी रिहाई का आदेश दे सके। अनुच्छेद 7 को अनुच्छेद 27 (2) में उल्लिखित गैर-निलंबित अधिकारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो इस प्रकार है: अनुच्छेद 3 (कानूनी व्यक्तित्व का अधिकार); अनुच्छेद 4 (जीवन का अधिकार); अनुच्छेद 5 (मानवीय व्यवहार का अधिकार); अनुच्छेद 6 (दासता से मुक्ति); अनुच्छेद 9 (पूर्वव्यापी कानूनों से मुक्ति); अनुच्छेद 12 (अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता); अनुच्छेद 17 (परिवार के अधिकार); अनुच्छेद 18 (नाम का अधिकार); अनुच्छेद 19 (बच्चे के अधिकार); अनुच्छेद 20 (राष्ट्रीयता का अधिकार); और अनुच्छेद 23 (सरकार में भाग लेने का अधिकार), या ऐसे अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यायिक गारंटी।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ACHR के तहत आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निलंबित किया जा सकता है। मानवाधिकारों पर इंटर-अमेरिकन कमीशन (कमीशन) ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि आपातकालीन स्थितियों में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निलंबित या अप्रभावी नहीं किया जा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में भी, जिसे विशेष परिस्थितियों में अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न्यायाधीश को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती है कि गिरफ्तारी का वारंट युक्तियुक्त की परीक्षा को पूरा करता है या नहीं, जो कुछ ऐसे देशों के वाद कानून द्वारा निर्धारित मानक है जो आपातकाल की स्थिति में पाए गए हैं।

आयोग ने इंटर-अमेरिकन मानवाधिकार न्यायालय (न्यायालय) से इस प्रश्न पर उसकी परामर्शात्मक राय मांगी।

न्यायालय ने अपनी पिछली परामर्शात्मक राय का संदर्भ दिया, जिसमें उसने मत व्यक्त

किया था कि विधि की विधेयता के सिद्धांत, लोकतांत्रिक संस्थाएँ और विधि का शासन एक अविभाज्य संबंध साझा करते हैं। न्यायालय ने घोषणा की: 'एक लोकतांत्रिक समाज में, मानव व्यक्ति में निहित अधिकार और स्वतंत्रता, उन पर लागू गारंटियाँ और कानून का शासन एक त्रयी का निर्माण करते हैं। इसका प्रत्येक घटक स्वयं को परिभाषित करता है, पूरक होता है और अपने अर्थ के लिए दूसरों पर निर्भर करता है।' न्यायालय को यह ज्ञात था कि अनुच्छेद 7 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उन प्रावधानों में सूचीबद्ध नहीं है जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, इससे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अनुपलब्ध नहीं हो जाती है क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो हिरासत की वैधता का न्यायिक निर्धारण प्राप्त करना है, यह आवश्यक है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायाधीश या न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाए। यहां बंदी प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्ति के जीवन और शारीरिक अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने, उसके गायब होने या उसके ठिकाने को गुप्त रखने से रोकने और उसे यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक सजा या व्यवहार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय की सर्वसम्मत राय में, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अम्परों की याचिका उन न्यायिक उपायों में से हैं जो विभिन्न अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं जिनके विचलन को अनुच्छेद 27 (2) द्वारा निषिद्ध किया गया है और जो इसके अलावा, एक लोकतांत्रिक समाज में वैधता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। (जोर दिया गया)।

राय अपने तर्क के लिए उल्लेखनीय और अपने साहसी निष्कर्ष के लिए प्रशंसनीय है। एडीएम जबलपुर मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना अलग और स्फूर्तिदायक है! ये न्यायमूर्ति एच आर खन्ना के उस शानदार असहमति वाले बयान की तरह ही है।

यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक राज्य में आपातकाल का अंतिम औचित्य उसे असाधारण गंभीरता की अप्रत्याशित स्थितियों के कारण अस्थायी रूप से खतरे में पड़े एक लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण मूल्यों को संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। लोकतंत्र के आधार को कमजोर करने के लिए आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। विधि का शासन लोकतंत्र की एक अपरिहार्य विशेषता है। विधि के शासन की अनुपस्थिति में, अराजकता हावी हो जाती है, विशेष रूप से सरकारी अराजकता, जब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए कोई अधिकार नहीं होता है, इसे नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं होता है और इसे जवाबदेह बनाने और इसकी ज्यादतियों की जांच करने के लिए कोई संस्था नहीं होती है। चाहे आपातकाल कितना भी गंभीर क्यों न हो, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि विधि की विधेयता, लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन के बीच एक अविभाज्य संबंध होता है। एक बार जब वह बंधन टूट जाता है, तो सभ्य और शालीन जीवन से सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, और मानव मात्र अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं।

वियना संकल्प एवं कार्य योजना

25 जून 1993 को वियना में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन द्वारा अंगीकृत

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन,
यह देखते हुए कि मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए प्राथमिकता का विषय है, और यह कि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए तंत्र का व्यापक विश्लेषण करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, ताकि न्यायपूर्ण और संतुलित तरीके से उन अधिकारों के पूर्ण पालन को बढ़ाया जा सके और बढ़ावा दिया जा सके, यह स्वीकार करते हुए और पुष्टि करते हुए कि सभी मानवाधिकार मानव में निहित गरिमा और महत्व से उत्पन्न होते हैं, और यह कि मानव ही मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का केंद्र बिन्दु है, और परिणामस्वरूप उसे सर्वप्रमुख लाभार्थी होना चाहिए और इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए,संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 56 में संयुक्त और पृथक कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए, अनुच्छेद 55 में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, जिसमें सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और अनुपालन शामिल है, के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने पर उचित बल देते हुए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों की जिम्मेदारियों पर बल देते हुए, जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना, सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को विकसित करने और प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना का स्मरण करते हुए, विशेष रूप से मौलिक मानवाधिकारों, मानव की गरिमा और महत्व, तथा पुरुषों और महिलाओं तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों में विश्वास की पुनः पुष्टि करने के दृढ़ संकल्प को याद करते हुए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में व्यक्त संकल्प का स्मरण करते हुए, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाने, ऐसी स्थितियाँ स्थापित करने, जिनके अंतर्गत संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सके, व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देने, सहिष्णुता और अच्छे पड़ोसी के रूप में व्यवहार करने, तथा सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को नियोजित करने का संकल्प लिया गया है, इस बात पर जोर देते हुए कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रेरणा का स्रोत है जो सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक स्थापित करती है और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों, विशेष रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में निहित मानक निर्धारण में प्रगति करने में संयुक्त राष्ट्र के लिए आधार रही है,अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हो रहे बड़े बदलावों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सभी लोगों की आकांक्ष. ाओं, जिसमें सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना तथा लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत, शांति, लोकतंत्र, न्याय, समानता, कानून का शासन, बहुलवाद, विकास, बेहतर जीवन स्तर और एकजुटता के प्रति सम्मान शामिल है, को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण विश्व में महिलाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के भेदभाव और हिंसा से गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को युक्तिसंगत और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तंत्र को सशक्त किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के पालन के लिए सार्वभौमिक सम्मान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

ट्यूनिस, सैन जोस और बैंकॉक में आयोजित तीन क्षेत्रीय बैठकों में अपनाए गए घोषणापत्रों और सरकारों द्वारा दिए गए योगदानों को ध्यान में रखते हुए, तथा अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों और साथ ही मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन की तैयारी प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र विशेषज्ञों

द्वारा किए गए अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1993 का स्वागत करते हुए, अंत. र्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के रूप में, ताकि उनके सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग सुनिश्चित किया जा सके और उनकी संस्कृतियों और पहचानों के मूल्य और विविधता का सम्मान किया जा सके,
यह भी स्वीकार करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सभी मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए मौजूदा बाधाओं को दूर करने और चुनौतियों का सामना करने तथा दुनिया भर में इसके परिणामस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन को जारी रहने से रोकने के लिए तरीके और साधन तैयार करने चाहिए,हमारे युग की भावना और हमारे समय की वास्तविकताओं का आह्वान करते हुए, जो विश्व के लोगों और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान करती है कि वे सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के वैश्विक कार्य के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें, ताकि इन अधिकारों का पूर्ण और सार्वभौमिक उपभोग सुनिश्चित किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता के बढ़ते और निरंतर प्रयास द्वारा मानवाधिकार प्रयासों में पर्याप्त प्रगति हासिल करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता में नए कदम आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प होकर, वियना घोषणा और कार्य योजना को सत्यनिष्ठा से अपनाता है।

1. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवाधिकारों से संबंधित अन्य साधनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान, पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों की गंभीर प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वभौमिक प्रकृति पर कोई प्रश्न नहीं है।इस संरचना में, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएं सभी मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार हैं; उनका संरक्षण और संवर्धन सरकारों का प्राथमिक दायित्व है।

2. सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, तथा स्वतंत्र रूप से अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं।औपनिवेशिक या अन्य प्रकार के विदेशी प्रभुत्व या विदेशी कब्जे के तहत लोगों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन लोगों के आत्मनिर्णय के अविभाज्य अधिकार को साकार करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, कोई भी वैध कार्रवाई करने के अधिकार को मान्यता देता है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करने को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है तथा इस अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर घोषणा के अनुसार, इसे किसी भी कार्रवाई को अधिकृत या प्रोत्साहित करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक एकता को पूरी तरह से या आंशिक रूप से खंडित या क्षतिग्रस्त करेगा, जो लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के
सिद्धांत के अनुपालन में खुद को संचालित करते हैं और इस प्रकार किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उस क्षेत्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार रखते हैं।

3. विदेशी कब्जे के अधीन लोगों के संबंध में मानवाधिकार मानकों के कार्यान्वयन की गारंटी और निगरानी के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाने चाहिए, तथा मानवाधिकार मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से 14 अगस्त 1949 के युद्ध के समय नागरिक व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जिनेवा सम्मेलन, तथा मानवीय कानून के अन्य लागू मानदंडों के अनुसार, उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

4. सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन और संरक्षण को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य के अनुरूप, एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में माना जाना चाहिए। इन उद्देश्यों और सिद्धांतों की संरचना में, सभी मानवाधिकारों का संवर्धन और संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता वैध है। इसलिए मानवाधिकारों से संबंधित अंगों और विशेष एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों के सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण अनुप्रयोग के आधार पर अपनी गतिविधियों के समन्वय को और बढ़ाना

चाहिए।

5. सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित तथा परस्पर संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर निष्पक्ष और समान तरीके से, समान स्तर पर और समान महत्व के साथ मानना चाहिए। यद्यपि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशिष्टताओं तथा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए, फिर भी राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे, चाहे उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कुछ भी हो, सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दें और उनकी रक्षा करें।

6. सभी के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौमिक सम्मान और पालन की दिशा में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रयास, राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए आवश्यक स्थिरता और कल्याण में योगदान करते हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांति और सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहतर परिस्थितियों में योगदान करते हैं।
7. मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की जानी चाहिए।

8. लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा एक दूसरे को सशक्त करते हैं। लोकतंत्र लोगों की अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को निर्धारित करने की स्वतंत्र इच्छा तथा उनके जीवन के सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी पर आधारित है। उपर्युक्त के संदर्भ में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का संवर्धन और संरक्षण सार्वभौमिक होना चाहिए और बिना किसी शर्त के किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूरे विश्व में लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को मजबूत करने एवं बढ़ावा देने का समर्थन करना चाहिए।

9. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि लोकतंत्रीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध कम विकसित देशों को, जिनमें से कई अफ्रीका में हैं, लोकतंत्र और आर्थिक विकास की ओर उनके संक्रमण में सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए।

10. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन विकास के अधिकार की घोषणा में स्थापित विकास के अधिकार को एक सार्वभौमिक और अविभाज्य अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारों का एक अभिन्न अंग मानता है।
जैसा कि विकास के अधिकार पर घोषणा में कहा गया है, मानव व्यक्ति विकास का केन्द्रीय विषय है।
यद्यपि विकास सभी मानव अधिकारों के आनंद को सुगम बनाता है, फिर भी विकास की कमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों के हनन को उचित ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता।
विकास सुनिश्चित करने और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में राज्यों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकास के अधिकार की प्राप्ति और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
विकास के अधिकार के कार्यान्वयन की दिशा में स्थायी प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी विकास नीतियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समतापूर्ण आर्थिक संबंध और अनुकूल आर्थिक वातावरण की आवश्यकता है।

11. विकास के अधिकार को इस तरह पूरा किया जाना चाहिए कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की विकासात्मक और पर्यावरणीय आवश्यकताएं समान रूप से पूर्ण हो सकें। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने माना है कि विषाक्त और ख़तरनाक पदार्थों और कचरे का अवैध रूप से ढेर लगाया जाना संभावित रूप से सभी के जीवन और स्वास्थ्य के मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर ख़तरा है।
परिणामस्वरूप, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से विषाक्त और खतरनाक उत्पादों और अपशिष्टों के ढेर लगाने से संबंधित मौजूदा सम्मेलनों को अपनाने और उनका सख्ती से

क्रियान्वयन करने तथा अवैध ढर लगाने की रोकथाम में सहयोग करने का आह्वान करता है।
प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक प्रगति और उसके अनुप्रयोगों का लाभ उठाने का अधिकार है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि कुछ प्रगतियों, विशेष रूप से जैव-चिकित्सा और जीवन विज्ञान के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, से व्यक्ति की अखंडता, गरिमा और मानवाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है कि सार्वभौमिक चिंता के इस क्षेत्र में मानवाधिकारों और गरिमा का पूर्ण सम्मान किया जाए।

12. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करता है कि वह विकासशील देशों के विदेशी ऋण बोझ को कम करने में सहायता करने के लिए सभी प्रयास करे, ताकि ऐसे देशों की सरकारों के अपने लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के प्रयासों में सहायता मिल सके।

13.राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने की आवश्यकता है ताकि मानवाधिकारों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को मानवाधिकारों के सभी उल्लंघनों और उनके कारणों को खत्म करना चाहिए, साथ ही इन अधिकारों के उपयोग में आने वाली बाधाओं को भी दूर करना चाहिए।

14. व्यापक रूप से व्याप्त अत्यधिक गरीबी मानवाधिकारों के पूर्ण और प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है; इसका तत्काल निवारण और अंततः उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

15. किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक मूलभूत नियम है। सभी प्रकार के नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और संबंधित असहिष्णुता का शीघ्र और व्यापक उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए प्राथमिकता वाला कार्य है। सरकारों को इन बुराइयों को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। समूहों, संस्थाओं, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से आग्रह है कि वे इन बुराइयों के खिलाफ अपनी गतिविधियों में सहयोग और समन्वय करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें।

16. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन रंगभेद को समाप्त करने में हुई प्रगति का स्वागत करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली से इस प्रक्रिया में सहायता करने का आह्वान करता है।विश्व मानवाधिकार सम्मेलन भी रंगभेद के शांतिपूर्ण उन्मूलन के प्रयास को कमजोर करने के उद्देश्य से जारी हिंसा की निंदा करता है।

17. आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के कृत्य, तरीके और व्यवहार, साथ ही कुछ देशों में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ाव होना, ऐसी गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को नष्ट करना, क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की सुरक्षा को खतरे में डालना तथा वैध रूप से गठित सरकारों को अस्थिर करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद को रोकने और उससे निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

18. महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकार सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अपरिहार्य, अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्राथमिक उद्देश्य हैं।
लिंग आधारित हिंसा और सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न और शोषण, जिनमें सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी के परिणामस्वरूप होने वाले उत्पीड़न भी शामिल हैं, मानव व्यक्ति की गरिमा और महत्व के साथ असंगत हैं, और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। इसे कानूनी उपायों तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास, शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक समर्थन जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्रवाई एवं अंत. र्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

महिलाओं के मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार गतिविधियों का अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसमें महिलाओं से संबंधित सभी मानवाधिकार उपकरणों को बढ़ावा देना भी शामिल है।विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सरकारों, संस्थाओं, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से आग्रह करता है कि वे महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने प्रयासों को तेज करें।

19. अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व तथा ऐसे संवर्धन और संरक्षण के उन राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता में योगदान, जिनमें ऐसे व्यक्ति रहते हैं, को ध्यान में रखते हुए, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन राज्यों के दायित्व की पुनः पुष्टि करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा के अनुसार कानून के समक्ष बिना किसी भेदभाव और पूर्ण समानता के साथ सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का पूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें।
अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का उपभोग करने, अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने तथा निजी और सार्वजनिक रूप से, बिना किसी हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार के भेदभाव के, अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है।

20. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन समाज के विकास और बहुलता में स्वदेशी लोगों की अंतर्निहित गरिमा और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है तथा उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण तथा सतत विकास के लाभों के उनके आनंद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि करता है। राज्यों को समाज के सभी पहलुओं में, विशेषकर उनसे संबंधित मामलों में, स्वदेशी लोगों की पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वदेशी लोगों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, तथा ऐसे संवर्धन और संरक्षण के उन राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता में योगदान, जिनमें ऐसे लोग रहते हैं, को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, समानता और गैर-भेदभाव के आधार पर स्वदेशी लोगों के सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस सकारात्मक कदम उठाने चाहिए, तथा उनकी विशिष्ट पहचान, संस्कृतियों और सामाजिक संगठन के मूल्य और विविधता को मान्यता देनी चाहिए।

21. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, अनेक देशों द्वारा बाल अधिकार सम्मेलन के शीघ्र अनुसमर्थन का स्वागत करता है तथा बच्चों के जीवन, संरक्षण और विकास पर विश्व घोषणापत्र और विश्व बाल सम्मेलन द्वारा अपनाई गई कार्य योजना में बच्चों के मानवाधि. कारों को मान्यता दिए जाने का उल्लेख करते हुए, 1995 तक सम्मेलन के सार्वभौमिक अनुसमर्थन तथा सभी आवश्यक विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपायों को अपनाने तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके सदस्य देशों द्वारा इसके प्रभावी क्रियान्वयन का आग्रह करता है। बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में भेदभाव न करना तथा बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा बच्चे के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, परित्यक्त बच्चों, बेघर बच्चों, बाल पोर्नोग्राफी, बाल वेश्यावृत्ति या अंगों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक और यौन शोषण के शिकार बच्चों, अधिग्रहित प्रतिरक्षा-अक्षमता सिंड्रोम सहित बीमारियों के शिकार बच्चों, शरणार्थी और विस्थापित बच्चों, हिरासत में लिए गए बच्चों, सशस्त्र संघर्ष में फंसे बच्चों, साथ ही अकाल और सूखे तथा अन्य आपात स्थितियों के शिकार बच्चों की रक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों और कार्यक्रमों को सशक्त किया जाना चाहिए। सम्मेलन के कार्यान्वयन के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली-व्यापी कार्रवाई में बाल अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उसे ऐसे पारिवारिक वातावरण में बड़ा होना चाहिए जो उसे व्यापक संरक्षण प्रदान कर सके।

22. विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो तथा उन्हें सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का समान लाभ मिले, तथा समाज के सभी पहलुओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

23. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के, उत्पीड़न से बचने के लिए अन्य देशों में शरण लेने और उसका उपभोग करने का अधिकार है, साथ ही उसे अपने देश लौटने का भी अधिकार है। इस संबंध में यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के कन्वेंशन, इसके 1967 के प्रोटोकॉल और क्षेत्रीय उपकरणों के महत्व पर बल देता है। यह उन देशों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है जो अपने क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं और उनकी मेज़बानी करते हैं, और शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय को उसके कार्य के प्रति समर्पण के लिए धन्यवाद देता है। यह निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के प्रति भी अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है।

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने माना है कि सशस्त्र संघर्षों सहित मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन, लोगों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार अनेक एवं जटिल कारकों में से एक है।

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने माना है कि वैश्विक शरणार्थी संकट की जटिलताओं को देखते हुए तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा दायित्व-साझाकरण की भावना के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देशों और प्रासंगिक संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें शरणार्थियों और अन्य विस्थापित व्यक्तियों के आवागमन के मूल कारण ों और प्रभावों को दूर करने के लिए रणनीतियों का विकास, आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना, महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी संरक्षण और सहायता का प्रावधान, साथ ही स्थायी समाधान की प्राप्ति, मुख्य रूप से सम्मानजनक और सुरक्षित स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के पसंदीदा समाधान के माध्यम से, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलनों द्वारा अपनाए गए समाधान भी शामिल हैं, शामिल होना चाहिए। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन राज्यों की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से जहां तक उनका संबंध मूल देशों से है।

व्यापक दृष्टिकोण के आलोक में, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन अंतर-सरकारी और मानवीय संगठनों के माध्यम से विशेष ध्यान देने तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों का स्थायी समाधान खोजने के महत्व पर बल देता है, जिसमें उनकी स्वैच्छिक और सुरक्षित वापसी और पुनर्वास भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को मानवीय सहायता के महत्व और आवश्यकता पर बल देता है।

24. प्रवासी श्रमिकों सहित असुरक्षित समूहों से संबंधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, तथा मौजूदा मानवाधिकार साधनों को मजबूत और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्रों में, अपनी आबादी के असुरक्षित क्षेत्रों में व्यक्तियों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय बनाए रखें तथा उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें जो अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में रुचि रखते हैं।

25. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि अत्यधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार मानव गरिमा का उल्लंघन है और अत्यधिक गरीबी और इसके कारणों, जिनमें विकास की समस्या से संबंधित कारण भी शामिल हैं, के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, ताकि सबसे गरीब लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया जा सके, अत्यधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त किया जा सके और सामाजिक प्रगति के लाभों के उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने समुदाय के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे गरीब लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दें, मानवाधिकारों को बढ़ावा दें तथा अत्यधिक गरीबी से निपटने के प्रयास करें।

26. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार दस्तावेजों के संहिताकरण में हुई प्रगति का स्वागत करता है, जो एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है, और मानवाधिकार संधियों के सार्वभौमिक अनुसमर्थन का आग्रह करता है। सभी राज्यों को इन अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; सभी राज्यों को यथासंभव आरक्षण का सहारा लेने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

27. प्रत्येक राज्य को मानवाधिकार शिकायतों या उल्लंघनों के निवारण के लिए उपायों का एक प्रभावी संरचना प्रदान करना चाहिए। कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों सहित न्याय प्रशासन और, विशेष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निहित लागू मानकों के पूर्ण अनुरूप एक स्वतंत्र न्यायपालिका और कानूनी पेशा, मानवाधिकारों की पूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण प्राप्ति के लिए आवश्यक है और लोकतंत्र और सतत विकास की प्रक्रियाओं के लिए अपरिहार्य है। इस संदर्भ में, न्याय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं को समुचित रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह न्याय के सुदृढ़ एवं स्वतंत्र प्रशासन की प्राप्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर सलाहकार सेवाओं के विशेष कार्यक्रमों का उपयोग करे।

28. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन मानव अधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन, विशेष रूप से नरसंहार, 'जातीय सफाइ' और युद्ध की स्थितियों में महिलाओं के सुनियोजित दुष्कर्म पर अपनी निराशा व्यक्त करता है, जिससे शरणार्थियों और विस्थापितों का बड़े पैमाने पर पलायन होता है। ऐसी घृणित कार्यों की कड़ी निंदा करते हुए यह आह्वान दोहराया जाता है कि ऐसे अपराध करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए तथा ऐसे कार्यों को तत्काल रोका जाना चाहिए।

29. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में निहित मानकों की अवहेलना करते हुए विश्व के सभी भागों में जारी मानवाधिकार उल्लंघनों तथा पीड़ितों के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपायों के अभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करता है।
विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गहराई से चिंतित है, जिससे नागरिक आबादी, विशेषकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और विकलांग प्रभावित होते हैं। इसलिए सम्मेलन राज्यों और सशस्त्र संघर्षों में शामिल सभी पक्षों से आह्वान करता है कि वे 1949 के जिनेवा सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य नियमों और सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सख्ती से पालन करें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में निर्धारित मानवाधिकारों के संरक्षण के न्यूनतम मानकों का भी पालन करें।
विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, 1949 के जिनेवा सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों में निर्धारित मानवीय संगठनों द्वारा पीड़ितों को सहायता दिए जाने के अधिकार की पुनः पुष्टि करता है, तथा ऐसी सहायता के लिए सुरक्षित और समय पर पहुंच का आह्वान करता है।

30.मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन इस बात पर भी निराशा और निंदा व्यक्त करता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में घोर और सुनियोजित उल्लंघन तथा ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं जो सभी मानवाधिकारों के पूर्ण उपभोग करने में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। ऐसे उल्लंघनों और बाधाओं में यातना और क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड, संक्षिप्त और मनमाने ढंग से फांसी, गायब होना, मनमाने ढंग से हिरासत में लेना, सभी प्रकार के नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और रंगभेद, विदेशी कब्ज़ा और विदेशी वर्चस्व, विदेशी लोगों से नफ़रत, गरीबी, भूख और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अन्य प्रकार से हनन, धार्मिक असहिष्णुता, आतंकवाद, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और कानून के शासन का अभाव शामिल हैं।

31. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन राज्यों से किसी भी एकतरफा उपाय से बचने का आह्वान करता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप नहीं है, जो राज्यों के बीच व्यापार संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों में निर्धारित मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालता है, विशेष रूप से भोजन और चिकित्सा देखभाल, आवास और आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के सभी के अधिकार। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि भोजन को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

32. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन मानवाधिकार मुद्दों पर विचार-विमर्श की सार्वभौमिकता, वस्तु. निष्ठता और गैर-चयनात्मकता सुनिश्चित करने के महत्व की पुनः पुष्टि करता है।

33. जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में निर्धारित है, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा का उद्देश्य मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को सुदृढ़ बनाना है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में मानवाधिकार शिक्षा विषय को कार्यक्रम में शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया है तथा राज्यों से ऐसा करने का आह्वान किया गया है। शिक्षा को राष्ट्रों और सभी जातीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता, शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए और इन उद्देश्यों के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए, मानवाधिकारों पर शिक्षा तथा सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की उचित जानकारी का प्रसार, जाति, लिंग, भाषा या धर्म जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के संबंध में मानवाधिकारों के प्रचार और सम्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में इस बात पर गौर किया गया कि संसाधनों की कमी और संस्थागत अपर्याप्तता इन उद्देश्यों की तत्काल प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

34. ऐसे देशों की सहायता के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए जो ऐसी परिस्थितियाँ बनाने का अनुरोध करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकें। सरकारों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और साथ ही अन्य बहुपक्षीय संगठनों से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्रीय विधान, राष्ट्रीय संस्थाओं और संबंधित अवसंरचनाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि करें जो कानून और लोकतंत्र के शासन, चुनावी सहायता, प्रशिक्षण, शिक्षण और शिक्षा, लोकप्रिय भागीदारी और नागरिक समाज के माध्यम से मानवाधिकार जागरूकता को बनाए रखते हैं।
मानवाधिकार केंद्र के अंतर्गत सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों को मजबूत किया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार मानवाधिकारों के सम्मान में सुधार के लिए एक बड़ा योगदान बनना चाहिए। राज्यों से इन कार्यक्रमों में अपना योगदान बढ़ाने का आह्वान किया गया है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से अधिक आवंटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, तथा स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है।

35. मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा मानवाधिकारों को दिए गए उच्च महत्व और सदस्य राज्यों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार गतिविधियों की मांगों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार गतिविधियों को बढ़े हुए संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।

36. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारियों को परामर्श देने की उनकी क्षमता में, मानवाधिकार उल्लंघनों के निवारण में उनकी भूमिका में, मानवाधिकार सूचना के प्रसार में, तथा मानवाधिकारों की शिक्षा में उनकी भूमिका में, मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका की पुनः पुष्टि करता है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें 'राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों' को ध्यान में रखा जाता है तथा यह माना जाता है कि प्रत्येक राज्य का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त ढांचे का चयन करे।

37. क्षेत्रीय व्यवस्थाएं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में मौलिक भूमिका निभाती हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में निहित सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों और उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार गतिविधियों के साथ सहयोग के महत्व पर बल देता है।
विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उन स्थानों

पर क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय व्यवस्थाएं स्थापित करने की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है जहां ये पहले से मौजूद नहीं हैं।

38. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सभी मानवाधिकारों के संवर्धन तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय गतिविधियों में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन मानवाधिकार मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, इस क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के संचालन तथा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्धन और संरक्षण में उनके योगदान की सराहना करता है। यह स्वीकार करते हुए कि मानक निर्धारण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है, सम्मेलन इस प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान की भी सराहना करता है। इस संबंध में, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग के महत्व पर जोर देता है।
मानवाधिकारों के क्षेत्र में वास्तविक रूप से शामिल गैर-सरकारी संगठनों और उनके सदस्यों को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मान्यता प्राप्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं तथा राष्ट्रीय कानून के संरक्षण का उपभोग मिलना चाहिए। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विपरीत नहीं किया जा सकता। गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ढांचे के भीतर, बिना किसी हस्तक्षेप के, अपने मानवाधिकार गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

39. मानवाधिकारों और मानवीय मुद्दों के बारे में वस्तुनिष्ठ, उत्तरदायी और निष्पक्ष जानकारी के महत्व को रेखांकित करते हुए, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मीडिया की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिसके लिए राष्ट्रीय कानून की संरचना के भीतर स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए।

II

A - संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अंतर्गत मानवाधिकारों पर समन्वय में वृद्धि

1. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के समर्थन में समन्वय बढ़ाने की सिफारिश करता है। इस उद्देश्य से, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों, निकायों और विशेष एजेंसियों से, जिनकी गतिविधियां मानवाधिकारों से संबंधित हैं, आग्रह करता है कि वे अनावश्यक दोहराव से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपनी गतिविधियों को सुदृढ़, तर्कसंगत और सुव्यवस्थित करने के लिए सहयोग करें। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने महासचिव को यह भी सिफारिश की है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक निकायों और विशिष्ट एजेंसियों के उच्च-स्तरीय अधिकारी अपनी वार्षिक बैठक में अपनी गतिविधियों के समन्वय के अलावा, सभी मानवाधिकारों के उपभोग पर अपनी रणनीतियों और नीतियों के प्रभाव का भी आकलन करें।

2. इसके अलावा, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन क्षेत्रीय संगठनों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय वित्त एवं विकास संस्थाओं से आह्वान करता है कि वे मानवाधिकारों के उपभोग पर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का भी आकलन करें।

3. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन यह मानता है कि संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की प्रासंगिक विशेषीकृत एजेंसियां, निकाय और संस्थाएं तथा अन्य प्रासंगिक अंतर-सरकारी संगठन, जिनकी गतिविधियां मानवाधिकारों से संबंधित हैं, अपने-अपने अधिदेशों के अंतर्गत मानवाधिकार मानकों के निर्माण, संवर्धन और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए।

4. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि सार्वभौमिक स्वीकृति के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की संरचना के अन्तर्गत अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन और परिग्रहण या उत्तराधिकार को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। महासचिव को संधि निकायों के परामर्श से, इन मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर न करने वाले राज्यों के साथ बातचीत प्रारम्भ करने पर विचार करना चाहिए, ताकि

बाधाओं की पहचान की जा सके और उन पर काबू पाने के तरीकों की खोज की जा सकें।

5. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन राज्यों को प्रोत्साहित करता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों पर अपनी आपत्तियों की सीमा को सीमित करने पर विचार करें, किसी भी आपत्ति को यथासंभव सटीक और संकीर्ण रूप से तैयार करें, सुनिश्चित करें कि कोई भी आपत्ति प्रासंगिक संधि के उद्देश्य और प्रयोजन के साथ असंगत न हो तथा किसी भी आपत्ति को वापस लेने की दृष्टि से नियमित रूप से उसकी समीक्षा करें।

6. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उच्च गुणवत्ता के साथ सामंजस्य बनाए रखने तथा मानवाधिकार साधनों के प्रसार से बचने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, 4 दिसम्बर 1986 के महासभा संकल्प 41/120 में निहित नए अंतर्राष्ट्रीय साधनों के विस्तार से संबंधित दिशानिर्देशों की पुनः पुष्टि करता है तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों से आह्वान करता है कि वे नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विस्तार पर विचार करते समय उन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें, नए मानकों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता पर मानवाधिकार संधि निकायों से परामर्श करें तथा सचिवालय से अनुरोध करें कि वह प्रस्तावित नए साधनों की तकनीकी समीक्षा करे।

7. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि जब भी आवश्यक हो संयुक्त राष्ट्र संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में मानवाधिकार अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित सदस्य देशों के अनुरोध पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में सूचना का प्रसार किया जा सके तथा प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके। मानवाधिकारों से संबंधित कार्य करने के लिए नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।

8. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन मानवाधिकार आयोग के आपातकालीन सत्र के आयोजन को एक सकारात्मक पहल के रूप में स्वागत करता है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रासंगिक अंगों द्वारा मानवाधिकारों के तीव्र उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया देने के अन्य तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

संसाधन

9. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, मानवाधिकार केन्द्र की गतिविधियों तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध मानव, वित्तीय और अन्य संसाधनों के बीच बढ़ती असमानता से चिंतित है, तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, महासचिव और महासभा से अनुरोध करता है कि वे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान और भावी नियमित बजटों के भीतर से मानवाधिकार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएं, तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

10. इस संरचना के अंतर्गत, नियमित बजट का एक बढ़ा हुआ अनुपात सीधे मानवाधिकार केन्द्र को आवंटित किया जाना चाहिए ताकि इसकी लागतों तथा मानवाधिकार केन्द्र द्वारा वहन की जाने वाली अन्य सभी लागतों के अन्तर्गत लाया जा सके, जिनमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकायों से संबंधित लागतें भी शामिल हैं। केंद्र की तकनीकी सहयोग गतिविधियों के स्वैच्छिक वित्तपोषण से इस बढ़े हुए बजट को बल मिलेगा; विश्व मानवाधिकार सम्मेलन मौजूदा ट्रस्ट फंड में उदार योगदान का आह्वान करता है।

11. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन महासचिव और महासभा से अनुरोध करता है कि वे मानवाधिकार केंद्र को पर्याप्त मानव, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वह अपनी गतिविधियों को प्रभावी, कुशलता और शीघ्रता से पूर्ण कर सके।

12. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान देते हुए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 101 के अनुसार महासचिव और सदस्य राज्यों से एक सुसंगत

दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है कि अंतर-सरकारी निकायों द्वारा अधिदेशित मानवाधिकार गतिविधियों को चलाने के लिए मानव और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़े हुए अधिदेशों के अनुरूप संसाधन सचिवालय को आवंटित किए जाएं। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन महासचिव को यह विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या कार्यक्रम बजट चक्र में प्रक्रियाओं में समायोजन आवश्यक या सहायक होगा, ताकि सदस्य राज्यों द्वारा अधिदेशित मानवाधिकार गतिविधियों का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मानवाधिकार केन्द्र

13. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केन्द्र को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर देता है।

14. मानवाधिकार केन्द्र को मानवाधिकारों के लिए प्रणाली-व्यापी ध्यान के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। केन्द्र की केन्द्रीय भूमिका तभी सबसे अच्छी तरह से समझी जा सकती है जब इसे संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों और अंगों के साथ पूर्ण सहयोग करने में सक्षम बनाया जाए। मानवाधिकार केन्द्र की समन्वयकारी भूमिका का यह भी अर्थ है कि न्यूयॉर्क में मानवाधिकार केन्द्र के कार्यालय को मजबूत बनाया जाए।

15. मानवाधिकार केन्द्र को विषयगत और देश के प्रतिवेदकों, विशेषज्ञों, कार्य समूहों और संधि निकायों की प्रणाली के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई मानवाधिकार आयोग द्वारा विचार के लिए प्राथमिकता वाला मामला बन जाना चाहिए।

16. मानवाधिकार केन्द्र को मानवाधिकारों के संवर्धन में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। सदस्य देशों के साथ सहयोग और सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहायता के एक उन्नत कार्यक्रम के माध्यम से इस भूमिका को आकार दिया जा सकता है। इन उद्देश्यों के लिए मौजूदा स्वैच्छिक निधियों का पर्याप्त विस्तार करना होगा तथा उन्हें अधिक कुशल और समन्वित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। सभी गतिविधियों में सख्त और पारदर्शी परियोजना प्रबंधन नियमों का पालन किया जाना चाहिए तथा नियमित कार्यक्रम और परियोजना मूल्यांकन समय-समय पर आयोजित किए जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, ऐसे मूल्यांकन अभ्यासों के परिणाम और अन्य प्रासंगिक जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। केंद्र को, विशेष रूप से, वर्ष में कम से कम एक बार सूचना बैठकें आयोजित करनी चाहिए जो इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सीधे तौर पर शामिल सभी सदस्य राज्यों और संगठनों के लिए खुली हों। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र का अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण, जिसमें मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की स्थापना का प्रश्न भी शामिल है।

17. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र के निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता को पहचानता है, जैसा कि वर्तमान घोषणा में और सभी लोगों के लिए संतुलित और सतत विकास के ढांचे के भीतर परिलक्षित होता है। विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अंगों को अपने समन्वय, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना चाहिए।

18. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन महासभा को अनुशंसा करता है कि अपने अड़तालीसवें सत्र में सम्मेलन की रिपोर्ट की जांच करते समय, वह प्राथमिकता के तौर पर सभी मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए मानवाधिकारों के लिए एक उच्चायुक्त की स्थापना के प्रश्न पर विचार करना शुरू करे।

B - समानता, गरिमा और सहिष्णुता

1. नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और असहिष्णुता के अन्य रूप

19. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने पर विचार करता है, विशेष रूप से उनके संस्थागत रूपों जैसे रंगभेद या नस्लीय श्रेष्ठता या विशिष्टता या नस्लवाद के समकालीन रूपों और अभिव्यक्तियों के सिद्धांतों के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक विश्वव्यापी संवर्धन कार्यक्रम के रूप में। संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों को नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए तीसरे दशक से संबंधित कार्रवाई के ऐसे कार्यक्रम को लागू करने के साथ-साथ उसी उद्देश्य के लिए बाद के जनादेशों को लागू करने के अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिए कार्रवाई के दशक के कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट फंड में उदारतापूर्वक योगदान करने की जोरदार अपील करता है।

20. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सभी सरकारों से आग्रह करता है कि वे नस्लवाद, विदेशी द्वेष या संबंधित असहिष्णुता के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए तत्काल उपाय करें और मजबूत नीतियां विकसित करें, जहां आवश्यक हो, दंडात्मक उपायों सहित उचित कानून बनाकर और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करके।

21. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और संबंधित असहिष्णुता के समकालीन रूपों पर एक विशेष प्रतिवेदक नियुक्त करने के मानवाधिकार आयोग के निर्णय का स्वागत करता है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सभी पक्षकारों से सम्मेलन के अनुच्छेद 14 के तहत घोषणा करने पर विचार करने की भी अपील करता है।

22. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी सरकारों से आह्वान करता है कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन में तथा अपनी-अपनी कानूनी प्रणालियों के प्रति उचित सम्मान के साथ असहिष्णुता तथा धर्म या विश्वास के आधार पर संबंधित हिंसा, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की प्रथाएँ तथा धार्मिक स्थलों का अपमान शामिल है, का मुकाबला करने के लिए सभी उचित उपाय करें, तथा यह स्वीकार करें कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक, अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। सम्मेलन सभी राज्यों से आग्रह करता है कि वे सभी प्रकार की असहिष्णुता तथा धर्म या विश्वास के आधार पर भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा के प्रावधानों को व्यवहार में लाएँ।

23. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात पर बल देता है कि जातीय सफाए से जुड़े आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले या अधिकृत करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार तथा उत्तरदायी हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे उल्लंघनों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

24. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों से आह्वान करता है कि वे जातीय सफाए की प्रथा का मुकाबला करने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से तत्काल उपाय करें, ताकि इसे शीघ्र समाप्त किया जा सके। जातीय सफाए की घृणित प्रथा के शिकार लोगों को उचित और प्रभावी उपचार का अधिकार है।

2. राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति

25. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार आयोग से राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा में निर्धारित अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के तरीकों और साधनों की जांच करने का आह्वान करता है। इस संदर्भ में, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार केंद्र से संबंधित सरकारों के अनुरोध पर और सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहायता के अपने कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, अल्पसंख्यक

मुद्दों और मानवाधिकारों के साथ-साथ विवादों की रोकथाम और समाधान पर योग्य विशेषज्ञता प्रदान करने का आह्वान करता है, ताकि अल्पसंख्यकों से जुड़ी मौजूदा या संभावित स्थितियों में सहायता की जा सके।

26. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा के अनुसार उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का आग्रह करता है।

27. जहाँ उचित हो, उठाए जाने वाले उपायों में समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं और उनके देश में आर्थिक प्रगति और विकास में उनकी पूर्ण भागीदारी को सुविधाजनक बनाना शामिल होना चाहिए।

स्थानीय लोग

28. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अल्पसंख्यकों के भेदभाव की रोकथाम और संरक्षण पर उप-आयोग के स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह से अपने ग्यारहवें सत्र में स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा का मसौदा तैयार करने का आह्वान करता है।

29. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि मानवाधिकार आयोग स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा का मसौदा तैयार करने के पूरा होने पर स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के अधिदेश के नवीनीकरण और अद्यतनीकरण पर विचार करे।

30. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह भी अनुशंसा करता है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सलाहकार सेवाएं और तकनीकी सहायता कार्यक्रम राज्यों द्वारा सहायता के अनुरोधों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें जो स्वदेशी लोगों के लिए प्रत्यक्ष लाभ होगा। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन आगे अनुशंसा करता है कि इस दस्तावेज़ द्वारा परिकल्पित केंद्र की गतिविधियों को मजबूत करने के समग्र ढांचे के भीतर मानवाधिकार केंद्र को पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

31. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन राज्यों से आग्रह करता है कि वे समाज के सभी पहलुओं में, विशेष रूप से उनके लिए चिंता के मामलों में स्वदेशी लोगों की पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करें।

32. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि महासभा जनवरी 1994 से शुरू होने वाले विश्व के स्वदेशी लोगों के एक अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा करे, जिसमें स्वदेशी लोगों की भागीदारी में तय किए जाने वाले कार्योन्मुख कार्यक्रम शामिल हों। इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे दशक के ढांचे में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में स्वदेशी लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रवासी श्रमिक

33. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों से आग्रह करता है कि वे सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के मानवाधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दें।

34. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मानता है कि प्रवासी श्रमिकों और जिस राज्य में वे रहते हैं, उसके बाकी समाज के बीच अधिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए परिस्थितियों का निर्माण विशेष महत्व का है।

35. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों को जल्द से जल्द सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने और अनुसमर्थन करने की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है।

3. महिलाओं की समान स्थिति और मानवाधिकार

36. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों के पूर्ण और समान व्यवहार का आग्रह करता है और यह सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन विकास प्रक्रिया में एजेंट और लाभार्थी दोनों के रूप में महिलाओं के एकीकरण और पूर्ण भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित करता है, और पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा और एजेंडा 21 के अध्याय 24 में निर्धारित सतत और न्यायसंगत विकास की दिशा में महिलाओं के लिए वैश्विक कार्रवाई पर स्थापित उद्देश्यों को दोहराता है, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो डी जेनेरो, ब्राजील, 3-14 जून 1992) द्वारा अपनाया गया था।

37. महिलाओं की समान स्थिति और महिलाओं के मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र-व्यापी प्रणाली गतिविधि की मुख्यधारा में एकीकृत किया जाना चाहिए। इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रासंगिक निकायों और तंत्रों में नियमित और व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, महिलाओं की स्थिति पर आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति, महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और उद्देश्यों और लक्ष्यों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, मानवाधिकार केंद्र और महिला उन्नति प्रभाग के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।

38. विशेष रूप से, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सार्वजनिक और निजी जीवन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन, महिलाओं में सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न, शोषण और तस्करी के उन्मूलन, न्याय के प्रशासन में लैंगिक पूर्वाग्रह के उन्मूलन और महिलाओं के अधिकारों और कुछ पारंपरिक या प्रथागत प्रथाओं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अतिवाद के हानिकारक प्रभावों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष के उन्मूलन की दिशा में काम करने के महत्व पर जोर देता है। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन महासभा से महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर मसौदा घोषणा को अपनाने का आह्वान करता है और राज्यों से इसके प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने का आग्रह करता है। सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस तरह के सभी उल्लंघन, जिनमें विशेष रूप से हत्या, व्यवस्थित बलात्कार, यौन हत्या शामिल है, को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है। इस प्रकार के सभी उल्लंघनों, विशेषकर हत्या, व्यवस्थित बलात्कार, यौन दासता और जबरन गर्भधारण सहित, के लिए विशेष रूप से प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

39. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन महिलाओं के खिलाफ़ सभी प्रकार के भेदभाव, चाहे वे छिपे हों या प्रत्यक्ष, के उन्मूलन का आग्रह करता है। संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2000 तक महिलाओं के खिलाफ़ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के सभी राज्यों द्वारा सार्वभौमिक अनुसमर्थन के लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। कन्वेंशन के लिए विशेष रूप से बड़ी संख्या में आरक्षणों को संबोधित करने के तरीकों और साधनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति को कन्वेंशन के लिए आरक्षणों की अपनी समीक्षा जारी रखनी चाहिए। राज्यों से आग्रह किया जाता है कि वे उन आरक्षणों को वापस लें जो कन्वेंशन के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत हैं या जो अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के साथ असंगत हैं।

40. संधि निगरानी निकायों को महिलाओं को मानवाधिकारों और गैर-भेदभाव के पूर्ण और समान व्यवहार के लक्ष्य में मौजूदा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का अधिक प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी का प्रसार करना चाहिए। महिलाओं की समानता और महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए नई प्रक्रियाओं को भी अपनाया जाना चाहिए। महिलाओं की स्थिति पर आयोग और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल की तैयारी के माध्यम से याचिका के अधिकार

को पेश करने की संभावना की जल्दी से जांच करनी चाहिए। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन अपने पचासवें सत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक विशेष प्रतिवेदक की नियुक्ति पर विचार करने के मानवाधिकार आयोग के फैसले का स्वागत करता है।

41. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में महिलाओं द्वारा जीवन भर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानक का आनंद लेने के महत्व को मान्यता दी गई है। महिलाओं पर विश्व सम्मेलन और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के संदर्भ में, 1968 की तेहरान घोषणा के साथ-साथ, विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता के आधार पर, सुलभ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं की व्यापक श्रृंखला के साथ-साथ सभी स्तरों पर शिक्षा तक समान पहुंच के लिए महिलाओं के अधिकार की पुष्टि की।

42. संधि निगरानी निकायों को लिंग-विशिष्ट डेटा का उपयोग करते हुए, अपने विचार-विमर्श और निष्कर्षों में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं के मानवाधिकारों को शामिल करना चाहिए। राज्यों को संधि निगरानी निकायों को अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति के बारे में विधिक और वास्तविक जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मानवाधिकार आयोग ने 8 मार्च 1993 को अपने उनचासवें सत्र में प्रस्ताव 1993/46 पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रतिवेदकों और कार्य समूहों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिला उन्नति प्रभाग को अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, विशेष रूप से मानवाधिकार केंद्र के साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार गतिविधियां नियमित रूप से महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन, जिसमें लिंग-विशिष्ट दुर्व्यवहार भी शामिल है, को संबोधित करें। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और मानवीय राहत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें विशेष रूप से महिलाओं के मानवाधिकार हनन को पहचानने और उससे निपटने में सहायता मिल सके तथा वे लैंगिक पक्षपात के बिना अपना कार्य कर सकें।

43. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन सरकारों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से महिलाओं को निर्णय लेने वाले पदों तक पहुँच प्रदान करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार महिला कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आगे के कदमों को प्रोत्साहित करता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख और सहायक अंगों को समानता की शर्तों के तहत महिलाओं की भागीदारी की गारंटी देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

44. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित होने वाले विश्व महिला सम्मेलन का स्वागत करता है और आग्रह करता है कि विश्व महिला सम्मेलन के समानता, विकास और शांति के प्राथमिक विषयों के अनुरूप महिलाओं के मानवाधिकारों को इसके विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

4. बाल अधिकार

45. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 'बच्चों के लिए प्रथम आह्वान' के सिद्धांत को दोहराता है तथा इस संबंध में, बच्चों के जीवन, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है।

46. 1995 तक बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के सार्वभौमिक अनुसमर्थन और बच्चों के जीवन, संरक्षण और विकास पर विश्व घोषणा और बच्चों के लिए विश्व शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाई गई कार्य योजना पर सार्वभौमिक हस्ताक्षर के साथ-साथ उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जाने चाहिए। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे बाल अधिकार सम्मेलन के प्रति अपनी आपत्तियों को वापस लें, जो सम्मेलन के उद्देश्य और प्रयोजन के विपरीत हों या अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के विपरीत हों।

47. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे अपने उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम सीमा तक अंत. र्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थन से विश्व शिखर सम्मेलन कार्य योजना में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय करें। सम्मेलन राज्यों से आग्रह करता है कि वे बाल अधिकार सम्मेलन को अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में एकीकृत करें। इन राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने, कुपोषण और निरक्षरता दर को कम करने और सुरक्षित पेयजल और बुनियादी शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने पर विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब भी ऐसा करने की आवश्यकता हो, प्राकृतिक आपदाओं और सशस्त्र संघर्षों से उत्पन्न विनाशकारी आपात स्थितियों और अत्यधिक गरीबी में बच्चों की समान रूप से गंभीर समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए।

48. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थन से विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में बच्चों की गंभीर समस्या का समाधान करें। बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार का सक्रिय रूप से मुकाबला किया जाना चाहिए, जिसमें उनके मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। कन्या भ्रूण हत्या, हानिकारक बाल श्रम, बच्चों और अंगों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति, बाल पोर्नोग्राफी, साथ ही यौन शोषण के अन्य रूपों के खिलाफ प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।
49. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन बालिकाओं के मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों द्वारा किए गए सभी उपायों का समर्थन करता है। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन राज्यों से मौजूदा कानूनों और विनियमों को निरस्त करने और उन रीति-रिवाजों और प्रथाओं को हटाने का आग्रह करता है जो बालिकाओं के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।

50. विश्व मानवाधिकार सम्मेलन इस प्रस्ताव का दृढ़ता से समर्थन करता है कि महासचिव सशस्त्र संघर्षों में बच्चों की सुरक्षा में सुधार के साधनों पर अध्ययन शुरू करें। युद्ध क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा और सहायता को सुविधाजनक बनाने के लिए मानवीय मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए और उपाय किए जाने चाहिए। उपायों में युद्ध के सभी हथियारों, विशेष रूप से एंटी-पर्सनल माइंस के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा शामिल होनी चाहिए। युद्ध से पीड़ित बच्चों की देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता को तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए। सम्मेलन बाल अधिकार समिति से सशस्त्र बलों में भर्ती की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रश्न का अध्ययन करने का आह्वान करता है।

51. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि मानवाधिकारों और बच्चों की स्थिति से संबंधित मामलों की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सभी प्रासंगिक अंगों और तंत्रों तथा विशेष एजेंसियों के पर्यवेक्षी निकायों द्वारा उनके अधिदेशों के अनुसार नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाए।

52. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी मानवाधिकार साधनों और विशेष रूप से बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

53. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि बाल अधिकार समिति को मानवाधिकार केंद्र की सहायता से विशेष रूप से अनुसमर्थन की अभूतपूर्व सीमा और उसके बाद राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मद्देनजर अपने अधिदेश को शीघ्रता और प्रभावी रूप से पूरा करने में सक्षम बनाया जाए।

5. यातना से मुक्ति

54. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन के कई सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन का स्वागत करता है और अन्य सभी सदस्य राज्यों द्वारा इसके शीघ्र अनुसमर्थन को प्रोत्साहित करता है।

55. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि मानव गरिमा के खिलाफ सबसे जघन्य उल्लंघनों में से एक यातना का कृत्य है, जिसके परिणामस्वरूप गरिमा नष्ट हो जाती है और पीड़ितों की अपने जीवन और अपनी गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता क्षीण हो जाती है।

56. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत, यातना से मुक्ति एक अधिकार है जिसे सभी परिस्थितियों में संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय अशांति या सशस्त्र संघर्ष के समय भी शामिल हैं।

57. इसलिए मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों से आग्रह करता है कि वे यातना की प्रथा को तत्काल समाप्त करें और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ-साथ प्रासंगिक सम्मेलनों के पूर्ण कार्यान्वयन और जहां आवश्यक हो, मौजूदा तंत्रों को मजबूत करके इस बुराई को हमेशा के लिए मिटा दें। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों से आग्रह करता है कि वे अपने अधिदेश की पूर्ति में यातना के प्रश्न पर विशेष प्रतिवेदक के साथ पूर्ण सहयोग करें।

58. कैदियों और बंदियों को यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार से बचाने में स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से चिकित्सकों की भूमिका से संबंधित चिकित्सा नैतिकता के सिद्धांतों के लिए सार्वभौमिक सम्मान और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

59. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन यातना के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने तथा उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामा. जिक पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर और अधिक ठोस कार्रवाई के महत्व पर बल देता है। इस उद्देश्य के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यातना के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक कोष में अतिरिक्त योगदान देकर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

60. राज्यों को यातना जैसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्ड से मुक्ति दिलाने वाले कानून को निरस्त करना चाहिए तथा ऐसे उल्लंघनों पर मुकदमा चलाना चाहिए, जिससे कानून के शासन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान हो।

61. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि यातना को समाप्त करने के प्रयासों को सबसे पहले रोक. थाम पर केंद्रित किया जाना चाहिए तथा इसलिए यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार या दण्ड के विरुद्ध कन्वेंशन के लिए एक वैकल्पिक प्रोटोकॉल को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य हिरासत के स्थानों पर नियमित दौरे की एक निवारक प्रणाली स्थापित करना है।

जबरन गुमशुदगी

62. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन, जबरन गायब होने से सभी व्यक्तियों के संरक्षण पर घोषणापत्र को महासभा द्वारा अपनाए जाने का स्वागत करते हुए, सभी राज्यों से जबरन गायब होने के कृत्यों को रोकने, समाप्त करने और दंडित करने के लिए प्रभावी विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य उपाय करने का आह्वान करता है। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि किसी भी परिस्थिति में सभी राज्यों का यह कर्तव्य है कि जब भी यह मानने का कारण हो कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र में जबरन गायब होने की घटना हुई है, तो वे जांच करें और यदि आरोपों की पुष्टि हो जाती है, तो इसके अपराधियों पर मुकदमा चलाएं।

6. दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार

63. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि सभी मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ सार्वभौमिक हैं और इस प्रकार बिना किसी शर्त के विकलांग व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति समान पैदा होता है और उसे जीवन और कल्याण, शिक्षा और काम, स्वतंत्र रूप से रहने और समाज के सभी पहलुओं में सक्रिय भागीदारी के समान अधिकार हैं। इसलिए विकलांग व्यक्ति के साथ कोई भी प्रत्यक्ष भेदभाव या अन्य नकारात्मक भेदभावपूर्ण व्यवहार उसके अधिकारों का उल्लंघन है। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन सरकारों से, जहाँ आवश्यक हो, विकलांग व्यक्तियों के लिए इन तथा अन्य अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कानून अपनाने या समायोजित करने का आह्वान करता है।

64. विकलांग व्यक्तियों का स्थान सर्वत्र है। विकलांग व्यक्तियों को सभी सामाजिक रूप से निर्धारित बाधाओं, चाहे वे शारीरिक, वित्तीय, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक हों, को समाप्त करके समान अवसर की गारंटी दी जानी चाहिए, जो समाज में पूर्ण भागीदारी को बाहर करती हैं या प्रतिबंधित करती हैं।

65 विकलांग व्यक्तियों के संबंध में विश्व कार्य कार्यक्रम को याद करते हुए, जिसे महासभा ने अपने सैंतीसवें सत्र में अपनाया था, मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से 1993 में अपनी बैठकों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के समानीकरण पर मानक नियमों का मसौदा अपनाने का आह्वान करता है।

C - मानवाधिकारों के विकास में सहयोग और सुदृढ़ीकरण

66. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि लोकतंत्र, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

67. मानवाधिकारों से संबंधित संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और निर्माण, बहुलवादी नागरिक समाज के सुदृढ़ीकरण तथा असुरक्षित समूहों के संरक्षण में सहायता के उपायों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकारों के अनुरोध पर प्रदान की जाने वाली सहायता, जिसमें चुनाव के मानवाधिकार पहलुओं में सहायता और चुनाव के बारे में सार्वजनिक सूचना शामिल है, विशेष महत्व रखती है। कानून के शासन को सुदृढ़ करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के प्रशासन को बढ़ावा देने तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लोगों की वास्तविक और प्रभावी भागीदारी के लिए दी जाने वाली सहायता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

68. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार केंद्र द्वारा मजबूत सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहायता गतिविधियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देता है। केंद्र को मानवाधिकार संधियों के तहत रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए सुसंगत और व्यापक कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन सहित विशिष्ट मानवाधिकार मुद्दों पर राज्यों को अनुरोध पर सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मानवाधिकारों और लोकतंत्र की संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों का कानूनी संरक्षण, अधिकारियों और अन्य लोगों का प्रशिक्षण, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक शिक्षा और सार्वजनिक सूचना, ये सभी इन कार्यक्रमों के घटक के रूप में उपलब्ध होने चाहिए।

69. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक व्यापक कार्यक्रम स्थापित किया जाए ताकि राज्यों को पर्याप्त राष्ट्रीय संरचनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य में सहायता मिल सके, जिसका मानवाधिकारों के समग्र पालन और कानून के शासन के रखरखाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मानवाधिकार केंद्र द्वारा समन्वित किया जाने वाला ऐसा कार्यक्रम इच्छुक सरकार के अनुरोध पर, दंड और सुधारात्मक प्रतिष्ठानों में सुधार, मानवाधिकारों में वकीलों, न्यायाधीशों और सुरक्षा बलों की शिक्षा और प्रशिक्षण, और कानून के शासन के अच्छे कामकाज के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य गतिविधि के क्षेत्र में राष्ट्रीय

परियोजनाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उस कार्यक्रम को मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

70. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है, जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम की स्थापना, संरचना, परिचालन तौर-तरीकों और वित्तपोषण के लिए विकल्प शामिल हों।

71. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन प्रत्येक राज्य को एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने की वांछनीयता पर विचार करने की संस्तुति करता है, जिसमें ऐसे कदमों की पहचान की जाए, जिससे वह राज्य मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में सुधार कर सके।

72. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन इस बात की पुष्टि करता है कि विकास के अधिकार की घोषणा में स्थापित सार्वभौमिक और अविभाज्य विकास के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए और उसे साकार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार आयोग द्वारा विकास के अधिकार पर एक विषयगत कार्य समूह की नियुक्ति का स्वागत करता है और आग्रह करता है कि कार्य समूह, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य अंगों और एजेंसियों के परामर्श और सहयोग से, विकास के अधिकार पर घोषणा के कार्यान्वयन और प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने और सभी राज्यों द्वारा विकास के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में तरीकों और साधनों की सिफारिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शीघ्र विचार के लिए व्यापक और प्रभावी उपाय तैयार करे।

73. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि विकास और/या मानवाधिकारों में सक्रिय गैर-सरकारी और अन्य जमीनी स्तर के संगठनों को विकास के अधिकार से संबंधित विचार, गतिविधियों और कार्यान्वयन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाया जाना चाहिए और सरकारों के साथ मिलकर विकास सहयोग के सभी प्रासंगिक पहलुओं में सहयोग करना चाहिए।

74. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सरकारों, सक्षम एजेंसियों और संस्थानों से अपील करता है कि वे मानवाधिकारों की रक्षा करने में सक्षम अच्छी तरह से काम करने वाली कानूनी प्रणालियों के निर्माण के लिए समर्पित संसाधनों में काफी वृद्धि करें और इस क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं से भी। विकास सहयोग के क्षेत्र में काम करने वालों को विकास, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बीच परस्पर मजबूत अंतर्संबंध को ध्यान में रखना चाहिए। सहयोग संवाद और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन व्यापक कार्यक्रमों की स्थापना का भी आह्वान करता है, जिसमें कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने से संबंधित जानकारी और विशेषज्ञता वाले कर्मियों के संसाधन बैंक शामिल हैं।

75. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के सहयोग से, मानवाधिकार आयोग को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोवनेन्ट के वैकल्पिक प्रोटोकॉल की जांच जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

76. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि मानवाधिकार केंद्र के सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहायता के कार्यक्रमों के तहत मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने या स्थापित करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। राज्यों को क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सूचना आदान-प्रदान जैसे उद्देश्यों के लिए सहायता का अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निहित सार्वभौमिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए निर्मित किए गए हैं।

77. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कोवनेन्ट और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में निर्धारित ट्रेड यूनियन अधिकारों के प्रभावी संवर्धन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और इसकी

प्रासंगिक विशेष एजेंसियों द्वारा सभी उपायों का समर्थन करता है। यह सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में निहित इस संबंध में अपने दायित्वों का पूरी तरह से पालन करने का आह्वान करता है।

D - मानवाधिकार शिक्षा

78. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन समुदायों के बीच स्थिर और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और प्राप्त करने तथा आपसी समझ, सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और सार्वजनिक सूचना को आवश्यक मानता है।

79. राज्यों को निरक्षरता को मिटाने का प्रयास करना चाहिए और शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित करना चाहिए। मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन सभी राज्यों और संस्थानों से औपचारिक और अनौपचारिक सेटिंग्स में सभी शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार, मानवीय कानून, लोकतंत्र और कानून के शासन को विषयों के रूप में शामिल करने का आह्वान करता है।

80. मानवाधिकार शिक्षा में शांति, लोकतंत्र, विकास और सामाजिक न्याय को शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निर्धारित किया गया है, ताकि मानवाधिकारों के प्रति सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से आम समझ और जागरूकता हासिल की जा सके।

81. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मार्च 1993 में अपनाई गई मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए शिक्षा पर विश्व कार्य योजना और अन्य मानवाधिकार साधनों को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने सिफारिश की है कि राज्य महिलाओं की मानवाधिकार आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए व्यापक मानवाधिकार शिक्षा और सार्वजनिक सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और रणनीति विकसित करें।

82. सरकारों को अंतः-सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से मानवाधिकारों और आपसी सहिष्णुता के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए मानवाधिकारों के लिए विश्व सार्वजनिक सूचना अभियान को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। उन्हें मानवाधिकारों में शिक्षा शुरू करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए और इस क्षेत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रभावी प्रसार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सलाहकार सेवाओं और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों को मानवाधिकारों के क्षेत्र में शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों और मानवीय कानून में निहित मानकों और सैन्य बलों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, पुलिस और स्वास्थ्य पेशे जैसे विशेष समूहों पर उनके अनुप्रयोग के संबंध में विशेष शिक्षा के लिए राज्यों से अनुरोधों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। इन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए मानवाधिकार शिक्षा के लिए दशकों तक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर विचार किया जाना चाहिए।

E- कार्यान्वयन और निगरानी विधियाँ

83. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन सरकारों से आग्रह करता है कि वे घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निहित मानकों को शामिल करें और राष्ट्रीय संरचनाओं, संस्थानों और समाज के अंगों को मजबूत करें जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं।

84. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन उन राज्यों द्वारा सहायता के अनुरोधों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और कार्यक्रमों को मजबूत करने की सिफारिश करता है जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए अपने स्वयं के राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना या सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं।

85. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच सहयोग को विशेष रूप से सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान के माध्यम से, साथ ही क्षेत्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग के माध्यम से मजबूत करने को भी प्रोत्साहित करता है।

86. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन इस संबंध में दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने तंत्रों को बेहतर बनाने और अनुभवों को साझा करने के तरीकों और साधनों की जांच करने के लिए मानवाधिकार केंद्र के तत्वावधान में आवधिक बैठकें आयोजित करें।

87. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार संधि निकायों, संधि निकायों के अध्यक्षों की बैठकों और राज्य पक्षों की बैठकों को अनुशंसा करता है कि वे संबंधित मानवाधिकार सम्मेलनों के तहत राज्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई कथित आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों को समन्वित करने के उद्देश्य से कदम उठाना जारी रखें और इस सुझाव का अध्ययन करें कि प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए संधि दायित्वों पर एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने से ये प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी और उनका प्रभाव बढ़ेगा।

88. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साधनों के पक्षकार राष्ट्र, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को मौजूदा मानवाधिकार संधि निकायों और विभिन्न विषयगत तंत्रों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर विचार करना चाहिए, ताकि विभिन्न निकायों, तंत्रों और प्रक्रियाओं के बेहतर समन्वय के माध्यम से अधिक दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, तथा उनके अधिदेशों और कार्यों के अनावश्यक दोहराव और ओवरलैपिंग से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा सके।

89. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन संधि निकायों के कामकाज में सुधार, जिसमें निगरानी कार्य भी शामिल हैं, पर निरंतर काम करने की अनुशंसा करता है, जिसमें इस संबंध में किए गए कई प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है, विशेष रूप से संधि निकायों द्वारा स्वयं और संधि निकायों के अध्यक्षों की बैठकों द्वारा किए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। बाल अधिकार समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

90. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि मानवाधिकार संधियों के पक्षकार राष्ट्र सभी उपलब्ध वैकल्पिक संचार प्रक्रियाओं को स्वीकार करने पर विचार करें।

91. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकारों के उल्लंघन के अपराधियों की दण्डमुक्ति के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करता है, तथा इस मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यकों के भेदभाव की रोकथाम एवं संरक्षण पर उप आयोग के प्रयासों का समर्थन करता है।

92. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर विद्यमान मानवाधिकार साधनों के बेहतर क्रियान्वयन की संभावना की जांच करे तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अपना कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

93. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन उन राज्यों से अपील करता है जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि वे 12 अगस्त 1949 के जिनेवा सम्मेलनों और उसके प्रोटोकॉल को स्वीकार करें, तथा उनके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए विधायी उपायों सहित सभी उचित राष्ट्रीय उपाय करें।

94. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समाज के अंगों के अधिकार और जिम्मेदारी पर मसौदा घोषणा को शीघ्र पूरा करने और अपनाने

की अनुशंसा करता है।

95. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यकों के भेदभाव की रोकथाम और संरक्षण पर उप-आयोग की विशेष प्रक्रियाओं, प्रतिवेदकों, प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और कार्य समूहों की प्रणाली को संरक्षित और मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है, ताकि उन्हें दुनिया भर के सभी देशों में अपने जनादेश को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके, उन्हें आवश्यक मानव और वित्तीय संसाधन प्रदान किए जा सकें। प्रक्रियाओं और तंत्रों को आवधिक बैठकों के माध्यम से अपने काम को सुसंगत और तर्कसंगत बनाने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। सभी राज्यों से इन प्रक्रियाओं और तंत्रों के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा जाता है।

96. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन अनुशंसा करता है कि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार सशस्त्र संघर्ष की सभी स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए।

97. मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुछ शांति-रक्षा अभियानों से संबंधित विशिष्ट व्यवस्थाओं में मानवाधिकार घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, यह अनुशंसा करता है कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप मानवाधिकार केंद्र और मानवाधिकार तंत्र की रिपोर्टिंग, अनुभव और क्षमताओं को ध्यान में रखें।

98. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के आनंद को मजबूत करने के लिए, अतिरिक्त दृष्टिकोणों की जांच की जानी चाहिए, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा में निर्धारित अधिकारों की प्राप्ति में प्रगति को मापने के लिए संकेतकों की एक प्रणाली। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए।

F- मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन का अनुवर्ती

99. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन यह अनुशंसा करता है कि महासभा, मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य अंग और एजेंसियां वर्तमान घोषणा में निहित अनुशंसाओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए बिना किसी देरी के तरीकों और साधनों पर विचार करें, जिसमें मानवाधिकारों के लिए दशकों तक संयुक्त राष्ट्र की घोषणा करने की संभावना भी शामिल है। मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन यह भी अनुशंसा करता है कि मानवाधिकार आयोग इस दिशा में प्रगति की वार्षिक समीक्षा करे।

100. मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध करता है कि वे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी राज्यों, मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सभी अंगों और एजेंसियों को आमंत्रित करें, ताकि वे वर्तमान घोषणा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर उन्हें रिपोर्ट करें और मानवाधिकार आयोग और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के माध्यम से महासभा के पचासवें सत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह, क्षेत्रीय और, जहां उपयुक्त हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं, साथ ही गैर-सरकारी संगठन, वर्तमान घोषणा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर महासचिव के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के ढांचे के भीतर अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और प्रोटोकॉल के सार्वभौमिक अनुसमर्थन के लक्ष्य की दिशा में प्रगति का आकलन करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रथम तिमाही 2025 के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक)

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
1	MATTERS UNDER ARTICLE 227	8387	2024	Allahabad	M/S Lr Print Solutions Vs. M/S Exflo Sanitation Pvt Ltd And 2 Others	28/3/2025
2	APPLICATION U/s 482	28882	2024	Allahabad	Mukul Kumar Jain And Another Vs. Central Bureau Of Investigation	28/3/2025
3	WRIT - A	6716	2024	Lucknow	Raj Kishore Singh Vs. State Of U.P.	28/3/2025
4	WRIT - C	12502	2012	Allahabad	M/S Jubilant Life Sciences Limited Vs. State Of U.P.	28/3/2025
5	WRIT TAX	1892	2024	Allahabad	Surender Gupta Vs. Appellate Authority State Gst	28/3/2025
6	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1667	2025	Lucknow	Kanti Devi Vs. State Of Up	27/3/2025
7	APPLICATION U/s 482	18295	2021	Allahabad	Taufik Ahmad Vs. State Of U.P. And Another	27/3/2025
8	WRIT - B	1043	2024	Lucknow	Chandan Singh @ Chandra Pal Singh Vs. Deputy Director Of Consolidation	27/3/2025
9	FIRST APPEAL FROM ORDER	12	2011	Lucknow	Avinash Sharma S/O Gurvachan Lal Sharma Vs. Sobhran Lal	26/3/2025
10	INCOME TAX APPEAL	422	2006	Allahabad	The Commissioner of Income Tax Central Kanpur Vs. Shri Umang Agarwal	26/3/2025
11	INCOME TAX APPEAL	86	2015	Allahabad	Umang Agarwal Vs. The Commissioner of Income Tax Central Circle	26/3/2025
12	WRIT - A	5027	2021	Allahabad	Ompal Singh Irrigation Supervisor Vs. State Of U.P.	26/3/2025
13	WRIT - C	1005313	2013	Lucknow	Usha Devi @ Urmila Devi And Others Vs. Malti Devi And Others	26/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
14	WRIT - C	15023	2024	Allahabad	M/S Anandeshwar Agro Foods Private Ltd Vs. State Of Up	26/3/2025
15	CRIMINAL APPEAL	1954	1993	Allahabad	Gendan Lal Vs. State Of U.P.	25/3/2025
16	WRIT - A	634	2025	Allahabad	Dilip Kumar Singh Rajpoot And 20 Others Vs. State Of U.P.	25/3/2025
17	MATTERS UNDER ARTICLE 227	7777	2024	Allahabad	Dharm Pal Singh Vs. State Of Up And Another	24/3/2025
18	SALES/TRADE TAX REVISION	10	2025	Allahabad	The Commissioner, Commercial Tax, Up Lucknow Vs. S/S Janki Industries	24/3/2025
19	WRIT - A	14895	2017	Allahabad	Jay Pal Singh Vs. State Of U.P. And 3 Ors.	24/3/2025
20	WRIT - C	22308	2023	Allahabad	C/M, Dr. Beni Prasad Vidyawati Shiksha Samiti And 3 Others Vs. State Of U.P.	24/3/2025
21	WRIT - C	8169	2025	Allahabad	Committee Of Management Sheelchand Inter College Vs. State Of U.P.	24/3/2025
22	WRIT TAX	1287	2024	Allahabad	M/S Solvi Enterprises Vs. Additional Commissioner Grade 2	24/3/2025
23	MATTERS UNDER ARTICLE 227	10194	2024	Allahabad	Govind Ram Pandey And Another Vs. Nutan Prakash And 15 Others	21/3/2025
24	WRIT - C	1001314	1999	Lucknow	Sudhakar Mani Tripathi Vs. State Of U.P.	21/3/2025
25	CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL	329	2025	Lucknow	Ashok Kumar Verma And 5 Others Vs. State Of U.P.	20/3/2025
26	WRIT - A	3371	2025	Allahabad	Smt Chandani Pandey Vs. State Of Up And 2 Others	19/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
27	WRIT - C	1002243	2001	Lucknow	Raju Vs. The Collector Sitapur And Others	19/3/2025
28	WRIT - C	41735	2024	Allahabad	Vijay Kumar Dixit Vs. Union Of India And 7 Others	19/3/2025
29	WRIT - A	7114	2023	Allahabad	Rajnish Kumar Pandey Vs. Union Of India And 5 Others	18/3/2025
30	WRIT - A	18801	2024	Allahabad	Priyankar Upadhyaya Vs. Union Of India And 3 Others	18/3/2025
31	WRIT - C	16710	2015	Allahabad	C/M Janta Prasar Samiti And Another Vs. State Of U.P.	18/3/2025
32	WRIT - C	31219	2024	Allahabad	Kalyan Singh Vs. State Of U.P. And 4 Others	18/3/2025
33	CRIMINAL APPEAL	1876	1983	Allahabad	Laxman Vs. State Of U.P.	17/3/2025
34	CRIMINAL REVISION	1449	2024	Allahabad	Akash And 2 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	17/3/2025
35	SPECIAL APPEAL	703	2024	Allahabad	State Of Up And 3 Others Vs. Mahendra Paliwal And Another	17/3/2025
36	WRIT - A	122	2025	Allahabad	Smt. Maimuna Begum Vs. State Of U.P. And 5 Others	17/3/2025
37	WRIT - C	1001723	2003	Lucknow	Pawan Kumar Vs. State Of U.P.	17/3/2025
38	WRIT - C	22762	2024	Allahabad	M/S Dada Gurudev Educational Private Ltd Vs. State Of Up	17/3/2025
39	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1133	2025	Lucknow	M/S Durga Travels Thru. Proprietor Pankaj Sharma Vs. Debts Recovery Tribunal	12/3/2025
40	SPECIAL APPEAL	996	2024	Allahabad	Registrar Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Vs. Firoz Ahmad	12/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
41	WRIT - A	10045	2020	Allahabad	Shivakar Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	12/3/2025
42	WRIT - A	368	2021	Allahabad	Amna Khatoon And 2 Others Vs. Aligarh Muslim University	12/3/2025
43	WRIT - C	1003067	2015	Lucknow	Smt. Bigni Devi Vs. U.P. Cooperative Tribunal Lucknow	12/3/2025
44	MATTERS UNDER ARTICLE 227	11807	2024	Allahabad	Smt. Santosh Awasthi Vs. Smt. Urmila Jain	11/3/2025
45	CRIMINAL REVISION	1965	2024	Allahabad	Rajendra Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	11/3/2025
46	FIRST APPEAL	27	2018	Lucknow	Khajanchi Vs. Preete	11/3/2025
47	WRIT - A	20509	2024	Allahabad	Govind Prasad Nishad Vs. The State Of U.P.	11/3/2025
48	WRIT - A	6586	2024	Allahabad	Shafique Ahmad Vs. State Of U.P. And 3 Others	11/3/2025
49	APPLICATION U/s 482	1400	2025	Allahabad	Om Prakash And 2 Others Vs. State of U.P.	10/3/2025
50	FIRST APPEAL FROM ORDER	137	2017	Lucknow	National Insurance Co. Ltd. Lucknow Vs. Gaurav Sharma	10/3/2025
51	SPECIAL APPEAL	89	2025	Lucknow	State Of U.P. Thru. Its Addl. Chief Secy. Deptt. Of Higher Education,Lko. And Another Vs. Prof. Bimal Jaiswal And 2 Others	10/3/2025
52	WRIT - A	16327	2022	Allahabad	Saurabh Lal Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/3/2025
53	WRIT - A	13305	2024	Allahabad	Rk Prasad And 11 Others Vs. Union Of India And 12 Others	10/3/2025
54	WRIT - C	3000181	1997	Lucknow	Surya Lal And Others Vs. State Of U.P. Through Secy.Revenue And Others	10/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
55	WRIT - C	47262	2017	Allahabad	Jaiprakash Associates Limited Vs. State Govt. Thru Prin. Secy. And Another	10/3/2025
56	WRIT - C	6049	2020	Allahabad	M/S Jai Prakash Associates Ltd Vs. State Of U.P. And Another	10/3/2025
57	WRIT - C	21532	2021	Allahabad	Jaypee Sports City Welfare Society And Another Vs. State Of U.P. And 2 Others	10/3/2025
58	WRIT - C	8909	2021	Allahabad	Suraksha Asset Reconstruction Limited Vs. State of U.P. and Another	10/3/2025
59	WRIT - C	31628	2024	Allahabad	M/S Bharat Enterprises Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/3/2025
60	WRIT - C	605	2025	Allahabad	Thoughtsol Infotech Private Limited Vs. Union Of India And 2 Others	10/3/2025
61	CIVIL MISC REVIEW APPLICATION	33	2025	Allahabad	Adeel Ahmad Khan Vs. State Of U.P. And 3 Others	7/3/2025
62	WRIT - A	14995	2024	Allahabad	Dr Suman Jain Vs. Union Of India And 2 Others	7/3/2025
63	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4173	2018	Allahabad	Yogeshwar Raj Nagar And Another Vs. State Of U.P. And Another	6/3/2025
64	APPLICATION U/s 482	25836	2024	Allahabad	Smt. Suman Prajapati Vs. State Of U.P. And Another	6/3/2025
65	CRIMINAL APPEAL	186	1993	Allahabad	Ram Bharosey And Others Vs. State Of U.P.	6/3/2025
66	CRIMINAL APPEAL	3376	2010	Allahabad	Ram Sujan Vs. State Of U.P.	6/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
67	SPECIAL APPEAL	75	2025	Allahabad	Smt. Renu Vs. State Of U.P. And 3 Others	6/3/2025
68	WRIT - A	7393	2000	Lucknow	Sarwar Hussain Vs. Managing Director U.P.Rajkiya Nirman Nigam Ltd. Lucknow	6/3/2025
69	WRIT - A	18731	2024	Allahabad	Gaurav Kumar Vs. State Of Up And 2 Others	6/3/2025
70	WRIT - A	19031	2024	Allahabad	Radheshyam Shukla And 14 Others Vs. State Of Up And 3 Others	6/3/2025
71	WRIT - C	39180	2024	Allahabad	Seema Padalia And Another Vs. State Of Up And 4 Others	6/3/2025
72	WRIT - C	39442	2024	Allahabad	Arvind Kumar Singh Vs. Lok Ayukta Uttar Paradesh And 3 Others	6/3/2025
73	MATTERS UNDER ARTICLE 227	8117	2024	Allahabad	Raj Kumar Chauturve-di Vs. U.P. Awas Evam Vikas Parishad And 11 Others	5/3/2025
74	FIRST APPEAL FROM ORDER	182	2023	Lucknow	Tata Aig General In-surance Company Ltd. Thru. Its Manager Gomti Nagar,Lucknow Vs. Aman Kumar And 2 Others	5/3/2025
75	WRIT - A	7683	2021	Allahabad	Ras Bihari Srivastava Vs. State Of U.P. And 3 Others	5/3/2025
76	WRIT - C	2218	2025	Lucknow	Vijay Pratap Singh And 5 Others Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./Prin. Secy. Excise Civil Sectt. Lko. And 3 Others	5/3/2025
77	WRIT - C	3824	2025	Allahabad	Deepak Kumar Verma Vs. Union Of India And 2 Others	5/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
78	WRIT TAX	1177	2022	Allahabad	M/S Gurunanak Are-canut Traders Vs. Commercial Tax And Another	5/3/2025
79	CRIMINAL MISC. BAIL APPLI-CATION	2232	2025	Allahabad	Harish Kumar Dubey Vs. State of U.P.	4/3/2025
80	CRIMINAL REVISION	4747	2023	Allahabad	Baldhir Vs. State Of U.P.	4/3/2025
81	CRIMINAL REVISION	6045	2024	Allahabad	Praveen Kumar Agarwal Vs. State Of U.P. And 2 Others	4/3/2025
82	HABEAS CORPUS WRIT PETI-TION	384	2024	Allahabad	Kapil Kasana Vs. Union Of Indi A And 8 Others	4/3/2025
83	WRIT - A	26967	2008	Allahabad	Ram Narain Ram And Others Vs. State Of U.P. Thru Secy. Secondary Edu. And Others	4/3/2025
84	WRIT - A	10743	2018	Allahabad	Raj Karan Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	4/3/2025
85	WRIT - A	2154	2025	Lucknow	Dinesh Kumar Kureel Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Public Works Deptt. Lko. And 2 Oth-ers	4/3/2025
86	WRIT - B	15451	1996	Allahabad	Ram Shanker And Another Vs. Board Of Revenue And Others	4/3/2025
87	WRIT - C	27598	2020	Allahabad	Kanyawati Vs. State Of U.P. And 5 Others	4/3/2025
88	WRIT - C	8253	2022	Allahabad	M/S Manoj Petroleum And Another Vs. Union Of India And 2 Others	4/3/2025
89	WRIT TAX	147	2023	Lucknow	Ashok Gandhi Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. State Tax Civil Secrt. Lko. And Others	4/3/2025
90	CRIMINAL APPEAL	5381	2019	Allahabad	Varun Kuamr Dwivedi Vs. State of U.P.	3/3/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
91	WRIT - A	63857	2007	Allahabad	Sanjay Kumar Sengar Vs. State Of U.P. And Others	3/3/2025
92	WRIT - A	11524	2024	Allahabad	Jagmohan Vs. State Of U.P And 2 Others	3/3/2025
93	WRIT - A	52	2025	Allahabad	Ashwani Kumar Srivastava Vs. Central Bank Of India Through Its Managing Director, Chandennukhi, Nariman Point , Mumbai	3/3/2025
94	WRIT - B	4405	1985	Lucknow	Agya Ram Vs. Joint Director Of Consolidation And Others	3/3/2025
95	WRIT - C	23088	2018	Allahabad	Satyaveer Vs. State Of U P And 2 Others	3/3/2025
96	WRIT - C	7611	2019	Allahabad	C/M Of Sri Ramdeo Sanskrit Mahavidylaya And Another Vs. State Of U.P. And 3 Others	3/3/2025
97	WRIT TAX	1022	2021	Allahabad	M/S Jaya Traders Through Its Proprietor Mr. Vishwanath Tiwari Vs. Additional Commissioner Grade-2 And Another	3/3/2025
98	MATTERS UNDER ARTICLE 227	7467	2021	Lucknow	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd. Vs. Shradha Padmaja Awasthi And Ors.	28/2/2025
99	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	1126	2025	Allahabad	M/s Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd., Vs. State of U.P. and 2 others	28/2/2025
100	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	3924	2025	Allahabad	Priyanka Bharti Vs. State Of U.P. And 3 Others	28/2/2025
101	SECOND APPEAL	42	2013	Lucknow	Juggi Lal Vs. Guru Prasad	28/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
102	WRIT - A	10287	2024	Allahabad	Saurabh Sahai Vs. State of U.P. and others	27/2/2025
103	WRIT - C	30788	2011	Allahabad	Rajeev Kumar Rana Vs. State of U.P. and Others	27/2/2025
104	WRIT TAX	2300	2024	Allahabad	M/S Rajat Infra Developers Private Ltd Vs. Union Of India And 4 Others	27/2/2025
105	APPLICATION U/s 482	11952	2024	Lucknow	Brij Bhushan Sharan Singh Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. U.P. Lko. And Another	24/2/2025
106	APPLICATION U/s 482	27233	2024	Allahabad	Amit Kumar Tiwari And 4 Others Vs. State Of U.P. And 3 Others	24/2/2025
107	WRIT - A	9193	2023	Lucknow	Shiv Datt Joshi And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./ Prin. Secy., Secretariat Administration Dept. Lko And Others	24/2/2025
108	WRIT - A	5381	2024	Lucknow	Sanjeev Kumar Sinha And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./Prin. Secy. Secretariat Administration Deptt. And 10 Others	24/2/2025
109	WRIT - A	2211	2025	Lucknow	Dineshwar Mishra Vs. State Of U.P. Thru. Chief Secy. Govt. Lko. And 4 Others	24/2/2025
110	WRIT - C	31823	2019	Allahabad	M/S Three C Green Developers Pvt. Ltd. And 8 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	24/2/2025
111	WRIT - C	15604	2021	Allahabad	M/S Lotus Green Constructions Pvt. Ltd. Vs. State Of U.P. And 2 Others	24/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
112	WRIT - C	26640	2021	Allahabad	M/S Xanadu Estates Private Limited Vs. State Of U.P. And 2 Others	24/2/2025
113	WRIT - C	21238	2024	Allahabad	M/S Sequel Buildcon Private Limited Vs. State Of Up And Another	24/2/2025
114	WRIT - C	6041	2024	Allahabad	M/S Arena Super-structures Pvt Ltd And Another Vs. State Of Up And Another	24/2/2025
115	MATTERS UNDER ARTICLE 227	13987	2024	Allahabad	Jaypee Hospital Vs. State Of Up And 3 Others	21/2/2025
116	MATTERS UNDER ARTICLE 227	15602	2024	Allahabad	Rajesh Kumar Sharma Vs. State Of U.P. And 2 Others	21/2/2025
117	APPLICATION U/s 482	2882	2016	Lucknow	Pradeep Kumar Maurya And Ors. Vs. State Of U.P. And Anr.	21/2/2025
118	CRIMINAL APPEAL U/S 372 CR.P.C.	254	2023	Allahabad	Ashok Kumar Vs. State Of U.P. And 2 Others	21/2/2025
119	GOVERNMENT APPEAL	1062	2024	Allahabad	State Of Up Vs. Manish Kumar And Another	21/2/2025
120	CRIMINAL MISC. BAIL APPLI-CATION	39053	2024	Allahabad	Saurabh Meena Vs. State of U.P.	20/2/2025
121	WRIT - A	19167	2024	Allahabad	Sheetal Chaudhary Vs. State Of Up And 3 Others	20/2/2025
122	WRIT - C	9298	2021	Allahabad	Birjesh Aggarwal Vs. State Of U.P. And 2 Others	20/2/2025
123	APPLICATION U/s 482	6694	2019	Lucknow	Bhagwati Sharana Dwivedi Vs. State Of U.P. And Anr.	19/2/2025
124	APPLICATION U/s 482	2818	2020	Allahabad	Surendra Kumar And Anr Vs. State Of U.P. And Anr	19/2/2025
125	APPLICATION U/s 482	1307	2025	Allahabad	Hooblal Yadav And 3 Others Vs. State of U.P. and Another	19/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
126	CRIMINAL REVISION	2019	2024	Allahabad	Ramesh Tiwari Vs. State Of U.P. And Another	19/2/2025
127	FIRST APPEAL FROM ORDER	758	2011	Lucknow	National Insurance Co. Ltd. Thro. Its Assistant Manager Vs. Shiv Gopal S/O Late Fateh Bahadur And Another	19/2/2025
128	WRIT - A	6576	2023	Lucknow	Vidhya Kishor Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Civil Sectt. Lko And 5 Others	19/2/2025
129	WRIT - A	2077	2025	Lucknow	Gorakhnath Shukla Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Revenue Lko. And 2 Others	19/2/2025
130	WRIT - C	1000956	1993	Lucknow	Rajesh Kumar Vs. Upper Collectorf.And R.Raibareli And Others	19/2/2025
131	WRIT - C	1000097	1995	Lucknow	Shiv Balak Singh And Another Vs. Board Of Revenue And Others	19/2/2025
132	WRIT - C	7948	2019	Allahabad	Sanjeev Kumar Vs. State Of U.P. And 2 Others	19/2/2025
133	WRIT - C	10598	2024	Lucknow	M/S Shree Shanker Medicals Thru. Proprietor Sachin Shanker Dixit Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Deptt. Food Safety And Drug Administration Lko. And 4 Others	19/2/2025
134	WRIT - C	3948	2025	Allahabad	Rajneeta Vs. Union Of India And 2 Others	19/2/2025
135	WRIT - A	1977	2025	Lucknow	U.O.I. Thru. The Secy. Ministry Of Railway Nr New Delhi And 2 Others Vs. Sri Santosh Kumar And Another	18/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
136	FIRST APPEAL FROM ORDER	32	2022	Lucknow	Prakash Narain And Others Vs. Hari Bux Singh And Others	17/2/2025
137	WRIT - A	15433	2024	Allahabad	Yudhveer Singh Vs. State Of Up And 5 Others	17/2/2025
138	WRIT - A	1940	2025	Lucknow	U.O.I. Thru. General Manager North Eastern Railway And 2 Others Vs. Dharmendra Kumar Sahu	17/2/2025
139	WRIT - B	4491	1999	Allahabad	Lalsa Yadav Vs. Board Of Revenue, Lucknow and Ors	17/2/2025
140	CRIMINAL MISC. BAIL APPLI-CATION	36992	2024	Allahabad	Arsh Saifi Alias Ballu Saifi Vs. State of U.P.	14/2/2025
141	SPECIAL APPEAL	70	2025	Lucknow	Prashant Kumar Mishra And 3 Others Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Home Deptt. Lko. And 26 Others	14/2/2025
142	WRIT TAX	830	2024	Allahabad	M/S Zhuzoor Infratech Private Limited Vs. Ad-ditional Commissioner Grade 2 And Another	14/2/2025
143	MATTERS UNDER ARTICLE 227	5780	2023	Allahabad	Mahendra Kumar Jain Vs. Mohammad Imran And Another	13/2/2025
144	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1401	2025	Allahabad	Shreeram Yadav Vs. Sanjay Mall And 3 Others	13/2/2025
145	CIVIL MISC REVIEW APPLICA-TION DEFECTIVE	26	2025	Lucknow	State Of U.P. Thru. The Prin. Secy. Secondary Education And 2 Others Vs. Dev Vrat Gautam And Another	13/2/2025
146	CRIMINAL APPEAL	2806	1983	Allahabad	Rakshpal And Another Vs. State Of U.P.	13/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
147	SECOND APPEAL	12	2022	Lucknow	Ram Lal(Dead) And 5 Others Vs. Smt. Vijay Laxmi And Another	13/2/2025
148	SPECIAL APPEAL	459	2023	Allahabad	State Of U.P. And 2 Others Vs. Md. Sameer Rao And 3 Others	13/2/2025
149	WRIT - C	10671	2024	Lucknow	M/S Al-Haq Foods Pvt. Ltd. Thru Its Director Navin Kumar Bhambri Vs. State Of U.P. Thru Addl. Chief/Prin.Secy. Deptt. Of Environment Forests And Climate Change And Ors.	13/2/2025
150	WRIT - C	24307	2024	Allahabad	Shahnawaz Ali Vs. State Of U.P. And 6 Others	13/2/2025
151	APPLICATION U/s 482	1287	2025	Lucknow	Anil Kumar Srivastava Vs. Cbi / S.C.B. Lko.	11/2/2025
152	FIRST APPEAL FROM ORDER	44	2021	Lucknow	Amrendra Bahadur Singh And Another Vs. Union Of India	11/2/2025
153	WRIT - A	12905	2024	Lucknow	Dan Bahadur Yadav Vs. Managing Director And Ceo Bank Of Baroda	11/2/2025
154	WRIT - A	16401	2024	Allahabad	Surya Pratap Singh Vs. State Of U.P.	11/2/2025
155	APPLICATION U/s 482	25418	2024	Allahabad	Piyush Gupta And Anothers Vs. State Of U.P.	10/2/2025
156	WRIT - A	11079	2024	Allahabad	Jagbeer Singh Vs. State Of U.P.	10/2/2025
157	WRIT - C	6744	2019	Allahabad	The Mechanical Department Primary And Another Vs. Union Of India	10/2/2025
158	WRIT - C	28993	2024	Allahabad	Gyanendra Kumar Vs. Union Of India	10/2/2025
159	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	12654	2023	Lucknow	Jaswant Singh Vs. State Of U.P.	7/2/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
160	CRIMINAL REVISION	3040	2023	Allahabad	Nagendra Sirohi Vs. State of U.P.	7/2/2025
161	WRIT - A	17707	2023	Allahabad	Amar Pal Singh Vs. State Of U.P.	7/2/2025
162	WRIT - C	33222	2023	Allahabad	Span Infra Developers Private Limited Vs. State Of U.P.	7/2/2025
163	MATTERS UNDER ARTICLE 227	3900	2022	Allahabad	Rambabu Gupta And 3 Others Vs. Shri Ganesh Ji Maharaj Virajman	6/2/2025
164	CRIMINAL APPEAL	8466	2022	Allahabad	Mayank Parasari Vs. State Of U.P.	6/2/2025
165	TRANSFER APPLICATION (CRIMINAL)	672	2024	Allahabad	Smt Kavita Chaudhary Vs. State Of U.P.	6/2/2025
166	WRIT - A	10045	2020	Allahabad	Shivakar Singh Vs. State Of U.P.	6/2/2025
167	WRIT - A	56331	2012	Allahabad	Sripal Giri Vs. State Of U.P.	5/2/2025
168	WRIT - C	3268	2025	Allahabad	Smt Rekha Devi Vs. State Of U.P.	5/2/2025
169	WRIT - A	3769	2023	Lucknow	Roshan Lal And Others Vs. State Of U.P	4/2/2025
170	WRIT - A	3770	2023	Lucknow	Jai Prakash Chand And 2 Others Vs. State Of U.P.	4/2/2025
171	WRIT - A	713	2025	Allahabad	Smt Durgesh Sharma And 2 Others Vs. State Of Uttar Pradesh	4/2/2025
172	APPLICATION U/s 482	6982	2017	Lucknow	Sharad Kumar And Another Vs. State Of U.P.	31/1/2025
173	APPLICATION U/s 482	363	2025	Lucknow	Kalavati Devi @ Kalavati Vs. State Of U.P.	31/1/2025
174	FIRST APPEAL FROM ORDER	1780	2024	Allahabad	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd Vs. Smt. Arti Devi	31/1/2025
175	WRIT - A	11282	2018	Allahabad	Ramesh Chandra Bari And 13 Others Vs. Union Of India	31/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
176	WRIT - A	9913	2023	Lucknow	Ashutosh Pandey And 5 Others Vs. State Of U.P.	31/1/2025
177	WRIT - A	1416	2025	Lucknow	Dr. Meenakshi Saxena Vs. State Of U.P.	31/1/2025
178	WRIT - C	953	2025	Lucknow	Smt. Rachana Soni Vs. State Of U.P.	31/1/2025
179	SECOND APPEAL	23	2025	Lucknow	Girja Shankar And 3 Others Vs. Ram Saje-evan	30/1/2025
180	WRIT - A	17904	2020	Lucknow	Om Prakash And Ors. Vs. State Of U.P.	30/1/2025
181	WRIT - A	23739	2021	Lucknow	Anand Kumar Vs. State Of U.P.	29/1/2025
182	APPLICATION U/s 482	743	2025	Lucknow	Bharatendu Pratap Singh Vs. State Of U.P.	28/1/2025
183	WRIT - C	1000717	1997	Lucknow	Shyam Lal And Others Vs. State of U.P.	28/1/2025
184	CRIMINAL REVISION	5217	2023	Allahabad	Abbas And Another Vs. State Of U.P.	27/1/2025
185	GOVERNMENT APPEAL	1178	2024	Allahabad	State Of Up Vs. Kallan And 3 Others	27/1/2025
186	MATTERS UNDER ARTICLE 227	12692	2024	Allahabad	Ajit Singh Yadav Vs. Smt. Neelam Yadav	24/1/2025
187	APPLICATION U/s 483	453	2024	Lucknow	Krishna Chandra Singh @ Munna Singh Vs. State Of U.P.	24/1/2025
188	CRIMINAL MISC. BAIL APPLI-CATION	41474	2024	Allahabad	Sarvajeet Singh Vs. State Of Up	24/1/2025
189	SECOND APPEAL	151	2016	Lucknow	Surya Kumar Tripathi Deceased And Ors. Vs. Ram Pal	24/1/2025
190	SECOND APPEAL	2	2017	Lucknow	Sabhapati Verma Vs. Ved Prakash	24/1/2025
191	WRIT - A	4769	2022	Allahabad	Anand Kumar Vs. State Of U.P.	24/1/2025
192	WRIT - A	43	2025	Allahabad	Rauhl Kumar And Another Vs. Union Of India	24/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
193	WRIT - C	35310	2024	Allahabad	V Marc India Limited Vs. State Of Up	24/1/2025
194	WRIT - C	888	2025	Allahabad	Aaghaz Khan And 95 Others Vs. State Of Uttar Pradesh	24/1/2025
195	FIRST APPEAL	844	2024	Allahabad	Nimmi Infratech Private Limited Vs. Fundan	23/1/2025
196	S.C.C. REVISION	95	2023	Allahabad	Sri Raman Arora Vs. Susheel Kumar (De-ceased)	23/1/2025
197	WRIT - A	1049	2024	Lucknow	Nand Kishor Shukla Vs. State Of U.P.	23/1/2025
198	WRIT - A	8637	2024	Lucknow	Anil Kumar Gangwar Vs. State Of U.P.	23/1/2025
199	WRIT - B	13084	1983	Allahabad	Mst. Purshottami Vs. Board Of Revenue	23/1/2025
200	APPLICATION U/s 482	14626	2019	Allahabad	Krishnawati Devi And 06 Others Vs. State Of Up	22/1/2025
201	APPLICATION U/s 482	21759	2024	Allahabad	Ram Avtar Agarwal Vs. State of U.P. and Anoth-er	22/1/2025
202	CIVIL REVISION	524	2011	Allahabad	Pawan Kumar Kothiwal And Others Vs. State of U.P. and Others	22/1/2025
203	CRIMINAL REFERENCE	1	2024	Lucknow	In Re- Procedure To Be Followed In Hearing Of Criminal Appeals Vs. State Of U.P.	22/1/2025
204	CRIMINAL APPEAL	351	2005	Lucknow	Annu Khatik And 2 Ors. Vs. State Of U.P.	22/1/2025
205	CRIMINAL APPEAL	2142	2008	Allahabad	Hari Singh @ Hari Shankar Vs. State Of U.P.	22/1/2025
206	HABEAS CORPUS WRIT PETI-TION	270	2024	Allahabad	Neil Tuteja Vs. State Of U.P. And 3 Others	22/1/2025
207	WRIT - A	19256	2024	Allahabad	Narendra And Another Vs. State Of Up And 2 Others	22/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
208	WRIT - B	47925	2014	Allahabad	Rajeshwari Devi Vs. Dy. Director Of Consolidation Shahjahanpur And 3 Others	22/1/2025
209	APPLICATION U/s 482	43911	2019	Allahabad	Faraheem Qureshi Vs. State Of U.P. And Another	21/1/2025
210	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	29850	2020	Allahabad	Sreedhaar Prasad Vs. State of U.P.	21/1/2025
211	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	35494	2024	Allahabad	Om Prakash Kushwaha Vs. State of U.P.	21/1/2025
212	CRIMINAL APPEAL	2696	1981	Allahabad	Devendra Kumar @ Jhunna And Others Vs. State Of U.P.	21/1/2025
213	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	3586	2022	Allahabad	Nizam Malik @ Kabadi @ Nizamuddin Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/1/2025
214	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4818	2022	Allahabad	Firoj Malik Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/1/2025
215	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4820	2022	Allahabad	Sajid Malik Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/1/2025
216	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4870	2022	Allahabad	Imran Malik Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/1/2025
217	WRIT - B	39710	2003	Allahabad	Hari Chand And Another Vs. The Board Of Revenue And Others	21/1/2025
218	WRIT - C	2228	2025	Allahabad	Anil Pathak And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/1/2025
219	MATTERS UNDER ARTICLE 227	7309	2024	Allahabad	Ankit Agrawal Vs. Smt. Monika Agrawal	20/1/2025
220	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	25993	2024	Allahabad	Smt. Rekha Vs. State Of U.P.	20/1/2025
221	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	439	2023	Allahabad	Gurmel Singh And Another Vs. State Of U.P. And Another	20/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
222	SECOND APPEAL	400	2011	Lucknow	Zila Ganna Utpadak Sahkari Samiti Ltd. Hardoi Theu. Its Vs. Union Of India Thru. Its Secy. Post And Telegraph Deptt. Andors.	20/1/2025
223	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	23378	2024	Allahabad	Bajarangi Singh Yadav Vs. State Of U.P.	17/1/2025
224	CRIMINAL APPEAL	2534	2011	Allahabad	Rajesh Vs. State of U.P.	17/1/2025
225	WRIT - A	507	2025	Allahabad	Aftab Khan Vs. State Of U.P. And 5 Others	17/1/2025
226	WRIT - A	59	2025	Allahabad	Mangey Ram Vs. Union Of India And Another	17/1/2025
227	WRIT - C	32144	2021	Allahabad	M/S Annapurna Construction Co. Through Its Proprietor Vs. State Of U.P. And 3 Others	17/1/2025
228	WRIT - C	41517	2024	Allahabad	M/S. Arya Rice Mill Vs. State Of U.P. And 6 Others	17/1/2025
229	MATTERS UNDER ARTICLE 227	8363	2024	Allahabad	Pramod Kumar Goyal And 3 Others Vs. Smt Saroj Sharma	16/1/2025
230	APPLICATION U/s 482	1251	2019	Allahabad	Dilip Singh Vs. State of U.P. and Another	16/1/2025
231	APPLICATION U/s 482	41426	2024	Allahabad	Anant Kumar Yadav Vs. State of U.P. and Another	16/1/2025
232	CRIMINAL APPEAL	10939	2024	Allahabad	Vishu Vs. State Of U.P. Though It Principal Secretary And Another	16/1/2025
233	SPECIAL APPEAL	367	2024	Allahabad	Shiv Dutt Sharma Vs. State Of U.P. Through Its Secretary, Basic Education And 4 Others	16/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
234	SPECIAL APPEAL	614	2024	Allahabad	Manish Kumar Vs. General Manager Personnel Human Resource Management And 4 Others	16/1/2025
235	SPECIAL APPEAL	969	2024	Allahabad	Naveen Kamal Srivastava And 2 Others Vs. State Of U.P. Through Secretary, Department Of Basic Education, Government Of U.P. And 3 Others	16/1/2025
236	SPECIAL APPEAL DEFECTIVE	10	2025	Lucknow	Saurabh Saxena Vs. Union Of India Thru. Secy. Ministry Skill Development Entreneurship New Delhi And 5 Others	15/1/2025
237	WRIT - A	17483	2024	Allahabad	Ashish Yadav Vs. Managing Director, U.P. State Road Transport Corporation And 2 Others	15/1/2025
238	WRIT - C	28277	2024	Allahabad	Smt. Anita And Another Vs. State Of Up And 3 Others	15/1/2025
239	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	39835	2024	Allahabad	Suraj Kumar Alias Vishwapratap Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/1/2025
240	WRIT - A	10247	2024	Lucknow	Smt. Anju Srivastava Vs. U.P. State Agro Industrial Corporation Ltd. Thru. Managing Director And 3 Others	10/1/2025
241	WRIT - A	9166	2024	Allahabad	Gopal Singh Vs. State Of Up And Another	10/1/2025
242	WRIT - C	22636	2024	Allahabad	Surendra Mani Vs. State Of Up And 5 Others	10/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
243	WRIT - C	33495	2024	Allahabad	Vikash Kumar And Another Vs. State Of Up And 3 Others	10/1/2025
244	MATTERS UNDER ARTICLE 227	15637	2024	Allahabad	Hari Shankar Vs. Rakesh Kumar	9/1/2025
245	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	7768	2024	Allahabad	Raghvendra Singh Alias Prince Vs. State Of U.P.	9/1/2025
246	WRIT - C	40479	2018	Allahabad	Ram Sajiwan Kori Vs. State Of U.P. And 5 Others	9/1/2025
247	WRIT - C	38488	2024	Allahabad	Mrs Manju Rakesh Vs. State Of Up And 2 Others	9/1/2025
248	APPLICATION U/s 482	724	2012	Lucknow	Dr. Rajesh Kumar Singh And Anr. Vs. The State Of U.P And Anr.	8/1/2025
249	APPLICATION U/s 482	2966	2017	Lucknow	Sachchidanand Rai And Anr. Vs. State Of U.P. And Anr.	8/1/2025
250	CIVIL REVISION	205	2009	Allahabad	Suresh Kumar Sharma And Others Vs. M/S Khanna Automobiles And Others	8/1/2025
251	CRIMINAL APPEAL	165	2001	Lucknow	Raj Deo And 4 Ors. Vs. State Of U.P.	8/1/2025
252	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	22470	2024	Allahabad	Vuenow Infotech Pvt. Ltd. Through Its Director Sh. Nitin Srivastava Vs. State Of Uttar Pradesh	8/1/2025
253	WRIT - A	4610	2024	Lucknow	Ravi Kumar Shukla And Others Vs. State Of U.P.	8/1/2025
254	APPLICATION U/s 482	418	2008	Lucknow	Smt. Rekha And 3 Ors. Vs. State Of U.P.	7/1/2025
255	APPLICATION U/s 482	885	2013	Lucknow	Sanajy Gaur Advocate And Ors. Vs. The State Of U.P	7/1/2025

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
256	CRIMINAL APPEAL	4817	2019	Allahabad	Arun Kumar Yadav And 2 Ors. Vs. State Of U.P.	7/1/2025
257	CRIMINAL APPEAL	9467	2024	Allahabad	Pardeshi Vs. State Of U.P.	7/1/2025
258	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	9825	2024	Lucknow	Mohd. Ali Vs. State Of U.P.	7/1/2025
259	SPECIAL APPEAL	296	2024	Lucknow	Kalamuddin @ Shanu Vs. State Of U.P.	7/1/2025
260	WRIT - C	30440	2024	Allahabad	Rajveer Singh And 10 Others Vs. State Of Up	7/1/2025
261	WRIT - A	12422	2024	Lucknow	Union Of India Thru. Secy. Govt. India Ministry Mines New Delhi And 3 Others Vs. Central Administrative Tribunal Lko.	6/1/2025
262	APPLICATION U/s 482	2440	2016	Lucknow	Ram Surat Singh And Others Vs. State Of U.P.	3/1/2025
263	APPLICATION U/s 482	40201	2024	Allahabad	Jitendra And 5 Others Vs. State Of U.P.	3/1/2025
264	CRIMINAL REVISION	1237	2024	Allahabad	Shamima And 4 Others Vs. State of U.P.	3/1/2025
265	WRIT - A	12938	2024	Lucknow	Smt. Pin Maya Kumal Vs. Govt. Of India	3/1/2025
266	APPLICATION U/s 482	30740	2024	Allahabad	Premanshu Vs. State of U.P.	2/1/2025
267	SPECIAL APPEAL	432	2024	Allahabad	Padmakar Dixit Vs. State Of Up	2/1/2025

प्रथम तिमाही 2025 के पूर्ण पीठ के निर्णयों की सूची (जनवरी से मार्च तक)

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
1	Writ C	905	2025	Lucknow	Brij Mohan Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Panchayati Raj Lko. And 2 Others	25/03/25	Interlocutory Non AFR
2	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.	25/03/25	Interlocutory Non AFR
3	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.	18/03/25	Interlocutory Non AFR
4	Writ A	2001811	2014	Lucknow	Ashtosh Tripathi Vs. State Of U.P. Through Prin. Secy. Appointment Deptt. Lko. And ors	10/3/2025	Final Non AFR
5	Writ A	2001776	2014	Lucknow	Akhilesh Kumar Sharma Vs. State Of U.P. Through Prin. Secy. Appointment Deptt.Lko and Ors.	10/3/2025	Final Non AFR
6	Writ A	2001775	2014	Lucknow	Asha Ram Pandey Vs. State Of U.P. Thru Prin. Secy.Appointment Deptt. Lko. And Ors.	10/3/2025	Final Non AFR
7	Writ A	2001357	2015	Lucknow	Hirdesh Kumar And Anr. Vs. State Of U.P. Thru. Prin.Secy. Appointment Lucknow And 2 Ors.	10/3/2025	Final Non AFR
8	Writ A	2001356	2015	Lucknow	Mukesh Kumar And Anr. Vs. State Of U.P. Thru. Prin.Secy. Appointment Lucknow And 2 Ors.	10/3/2025	Final Non AFR
9	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	10/3/2025	Final Non AFR

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
10	Writ A	4460	2013	Lucknow	Jai Prakash Sharma And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Housing And Urban Planning And A	10/3/2025	Interlocutory Non AFR
11	Writ A	4460	2013	Lucknow	Jai Prakash Sharma And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Housing And Urban Planning And A	28/2/2025	Interlocutory Non AFR
12	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.	25/2/2025	Interlocutory Non AFR
13	Writ C	306	2021	Lucknow	Ram Kishor Verma And Anr. Vs. U.O.I.Thru Secy. Corporate Affairs Ministry Newdelhi And Ors.	18/2/2025	Interlocutory Non AFR
14	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.	17/2/2025	Interlocutory Non AFR
15	Writ A	4460	2013	Lucknow	Jai Prakash Sharma And 2 Others Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Housing And Urban Planning And Another	7/2/2025	Interlocutory Non AFR
16	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	6/2/2025	Interlocutory Non AFR
17	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	5/2/2025	Interlocutory Non AFR
18	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	4/2/2025	Interlocutory Non AFR

S.NO.	CASE TYPE	CASE NUMBER	YEAR	AT	PARTY NAME	DATE OF DECISION	JUDGMENT TYPE
19	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	30/01/25	Interlocutory Non AFR
20	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	29/01/25	Interlocutory Non AFR
21	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.	24/01/25	Interlocutory Non AFR
22	Criminal Appeal	2174	2024	Lucknow	Shailendra Yadav @ Salu Vs. State Of U.P Thru. Prin. Secy. Home Lko.	24/01/25	Interlocutory Non AFR
23	Criminal Reference	1	2024	Lucknow	In Re- Procedure To Be Followed In Hearing Of Criminal Appeals Vs. State Of U.P.	22/1/2025	Final AFR
24	Special Appeal	541	2023	Allahabad	Authorized Officer, Prathama U P Bank Vs. Smt. Manjeet Kaur	16/1/2025	Interlocutory Non AFR
25	Writ A	2001502	2014	Lucknow	Sudhir Misha Vs. State Of U.P.Thru Prin.Secy. Appointment Deptt.Lucknow And Ors.	09/1/2025	Interlocutory Non AFR
26	Writ A	22052	2020	Lucknow	Heera Man Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Cooperative And Ors.		

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

हम आशा करते है की **"न्यायभा-न्याय की किरण"** के इस द्वितीय संस्करण ने अपेक्षानुसार आप विद्वान पाठकगणों को उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास के संदर्भ में ज्ञानसंवर्धन की प्राप्ति कराई होगी।

इसी क्रम में, **"न्यायभा-न्याय की किरण"** के साथ ही हमारे अन्य प्रकाशन आपके पठन हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

1. **ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR)**

   क. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास के सारांश के साथ ही
   ख. हिन्दी मे अनुवादित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय,
   ग. सर्वोच्च न्यायालय के हिन्दी मे अनुवादित निर्णय,
   घ. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतहासिक निर्णय।
   च. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय द्वारा पारित हिन्दी में अनुवादित निर्णय / अंतिम आदेश
   छ. विभिन्न अधिनियम(हिन्दी मे तथा हिन्दी मे अनुवादित) और
   ज. एक नि:शुल्क सर्च इंजन, जो दिए गए कीवर्ड के आधार पर न्यायालय के निर्णयों की खोज करता है, तथा मूल और इसके अनुवादित संस्करण दोनों के लिए कार्य करता है। साथ ही इसमे विभिन्न अन्य फ़िल्टर मानदंड जैसे वाद शीर्षक, माननीय न्यायमूर्ति का नाम, तटस्थ उद्धरण, आदि भी उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की खोज को मूल्यवान बनाते हैं।

2. **ई पुस्तिका स्वरूप मे ऐतिहासिक निर्णय** के प्रथम अंक मे **चौरी चौरा मुकदमे** मे पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अनुवादित निर्णय प्रकाशित किया गया तथा आगामी अंकों मे अन्य ऐतिहासिक मुकदमों मे पारित निर्णयों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

न्यायाभा-न्याय की किरण
संपादक मण्डल

श्री दिवाकर द्विवेदी,
(एच.जे.एस.) संयुक्त निबंधक (न्या)
(एससीएमएस)/(समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
प्रधान संपादक

श्री विवेक श्रीवास्तव,
उप-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
संपादक

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
सह-संपादक

पदेन सदस्य

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,
अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ट , इलाहाबाद

श्री मनीष कुमार सिंह,
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ट, इलाहाबाद

विधि प्रतिवेदक

श्री आशीष कुमार, सुश्री गौरी दूबे, सुश्री निधि वर्मा, श्री यावर मुख्तार, सुश्री अर्चना सिंह

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ई - निर्णय पत्रिका

न्यायाभा - न्याय की किरण